www.navpradesh.com
दैनिक नवप्रदेश
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्
प्रदेश के साथ पूरा देश...
अंदर के पृष्ठों पर ◆◆ 2 | छत्तीसगढ़ 4 | अभिव्यक्ति 11 | कारोबार/खेल
बिलासपुर, शुक्रवार, 22 मई 2026 | कृष्ण पक्ष-षष्ठी, | विक्रम संवत -2083 / वर्ष-12 अंक- 40 | पृष्ठ-12 मूल्य-5 रुपए | रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

49 हजार करोड़ की बोधघाट योजना, बस्तर में बिजली-सिंचाई और रोजगार का नया सपना

अनिल सामंत

जगदलपुर/नवप्रदेश। दंतेवाड़ा जिले के बारसुर के समीप इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बहुप्रतीक्षित बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना एक बार फिर चर्चा में है। करीब 45 वर्षों से फाइलों, विरोध और विस्थापन की आशंकाओं के बीच अटकी यह परियोजना अब नए सर्वे के साथ निर्णायक दिशा की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा परियोजना को पुनर्जीवित करने के फैसले के बाद दिल्ली की वेपकोस लिमिटेड ने क्षेत्र में सर्वे कार्य शुरू कर दिया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार आगामी तीन महीनों में सर्वे पूरा कर लिया जाएगा, जिसके आधार पर नई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होगी।

नवप्रदेश विशेष

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं इस परियोजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार इस बार बोधघाट परियोजना को ■ शेष पृष्ठ 8 पर

सर्वे शुरू

- ■ वेपकोस का सर्वे तय करेगा भविष्य, योजना से बदलेगी बस्तर की तस्वीर
- ■ तीन माह में सर्वे पूरा होने की उम्मीद, सरकार परियोजना पर गंभीर
- ■ उम्मीदों के बीच विस्थापन व जनसहमति सबसे बड़ी चुनौती

पोलावरम-बोधघाट योजना एक समय में हुई थी शुरू

बताया जा रहा है कि पोलावरम परियोजना और बोधघाट परियोजना लगभग एक ही समय में शुरू हुई थीं, लेकिन पोलावरम का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि बोधघाट परियोजना अब तक प्रारंभ नहीं हो सकी। परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं आजीविका के लिए पशुपालन, मत्स्य पालन, पर्यटन और परिवहन जैसे वैकल्पिक रोजगार की योजना भी तैयार की जा रही है।

3 जिलों के 269 गांव में बढ़ेगी सिंचाई व्यवस्था

परियोजना पूरी होने पर दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले के 269 गांवों के किसानों को सालभर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। जल संसाधन विभाग के अनुसार बस्तर संभाग में कुल नौ बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं और बोधघाट के आगे बढ़ने के बाद मटनार, चित्रकोट, कुटरू, नुगूर जैसे अन्य जलविद्युत एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए भी रास्ता खुल सकता है।

सर्वे-डीपीआर वाप्कोस लिमिटेड की जिम्मेदारी

“प्रस्तावित बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना के सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने की जिम्मेदारी भारत सरकार के मिनीरत्न उपक्रम वाप्कोस लिमिटेड को सौंपी गई है। कंपनी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया भी पूरी करेगी।

– **ग्राहम**, सीई, जल संसाधन विभाग

आज बेबाक

दस रुपये की झालमुड़ी से बहुतों को झाल लगी। कई तो जल भूनकर राख ही हो गए। अब एक रुपये वाली मेलोडी चाकलेट ने भी जलकुकड़ों के तन बदन में आग लगाकर रख दी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली प्रवास के दौरान वहां की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी को मेलोडी चाकलेट का छोटा पैकेट देकर बड़ा धमाका कर दिया। इसके वीडियो ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया। जाहिर है इससे रुदाली गैंग को मिर्ची लगनी ही थी। नतीजतन देश में बर्नाल की बिक्री बढ़ गई। समझ में नहीं आता कि इन दुखी आत्माओं का दुख कम क्यों नहीं होता?

तापमान	
अधिकतम 44°	न्यूनतम 27°

बाजार भाव	
गोल्ड 1,51,140	सिल्वर 2,54,798

शेयर बाजार	
सेंसेक्स 77,328.19	निफ्टी 24,176.15

विश्व जनसंख्या	भारत जनसंख्या
8,291,743,121	1,474,975,253

बिना एग्रीस्टेक पंजीयन नहीं मिलेगी खाद, सॉफ्टवेयर तय करेगा कोटा

डिजिटल कृषि से जमाखोरों पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

हेमंत धोटे

रायपुर/नवप्रदेश। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और अमेरिका-ईरान तनाव के कारण पैदा हुए वैश्विक संकट के बीच भारत सरकार और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार पूरी तरह ‘अलर्ट मोड’ पर आ गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उर्वरकों की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति बाधित होने की आशंका को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के लिए एक अभेद्य ‘सुरक्षा कवच’ तैयार कर लिया है। आगामी खरीफ सीजन 2026 के लिए राज्य में खाद-बीज का स्टॉक फुल है और किसानों को किसी भी तरह की किल्लत नहीं होने दी जाएगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री भी सख्त-जमाखोरों पर होगी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’: खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए जिला स्तर पर उड़नदस्तों (स्काड) और निरीक्षकों को तैनात कर दिया गया है। ये टीमें फील्ड पर जाकर हर दिन की सप्लाई और स्टॉक की रिपोर्ट शासन को भेजेंगी। उधर नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक उच्चस्तरीय बैठक कर साफ कर दिया है कि वैश्विक संकट का असर देश के किसानों पर नहीं पड़ने दिया ■ शेष पृष्ठ 8 पर

- ■ खाद की कालाबाजारी पर लगेगा ब्रेक, छत्तीसगढ़ में ‘फार्मर आईडी’ और ‘ई-वितरण’ प्रणाली लागू
- ■ वैश्विक संकट के बीच साय सरकार का ‘सुरक्षा कवच’
- ■ एग्रीस्टेक पोर्टल से तय होगा खाद का कोटा, गड़बड़ी करने वालों पर गिरेगी गाज

कृषि विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से खाद-बीज की उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। एक-एक पंजीकृत किसान को समय पर खाद मिलेगी, कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

छत्तीसगढ़ में उर्वरक उपलब्धता की वर्तमान स्थिति (30 मार्च तक)

नाम	लक्ष्य	वर्तमान उपलब्धता
यूरिया	आवंटित लक्ष्य 7.25 लाख मीट्रिक टन	(वर्तमान उपलब्धता: 2.43 लाख मीट्रिक टन)
डीएपी	आवंटित लक्ष्य 3.00 लाख मीट्रिक टन	(वर्तमान उपलब्धता: 1.05 लाख मीट्रिक टन)
एनपीके	आवंटित लक्ष्य 2.50 लाख मीट्रिक टन	(वर्तमान उपलब्धता: 1.69 लाख मीट्रिक टन)
एसएसपी	आवंटित लक्ष्य 2.00 लाख मीट्रिक टन	(वर्तमान उपलब्धता: 1.78 लाख मीट्रिक टन)
एमओपी	आवंटित लक्ष्य 0.80 लाख मीट्रिक टन	(वर्तमान उपलब्धता: 0.50 लाख मीट्रिक टन)

25 लाख टन यूरिया मंगाया

अमेरिका-ईरान तनाव के कारण पैदा हुए संकट को देखते हुए सरकार ने 2026 के लिए 25 लाख टन यूरिया के आयात को मंजूरी दी है। यह सप्लाई ‘स्ट्रेट ऑफहॉर्मुज’ के रास्ते को छोड़कर अल्जीरिया, नाइजीरिया, ओमान और रूस से सीधे मंगवाई जा रही है।

भारत-रूस मिलकर यूरिया फैक्ट्री लगाएंगे

अभी जरूरत का 71% यूरिया मिडिल-ईस्ट से आता है। ईरान जंग के कारण पैदा हुए यूरिया संकट के बीच भारत और रूस ने जॉइंट वेंचर में फर्टिलाइजर प्लांट लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी हैं। यह प्लांट रूस के समारा में लगाया जा रहा है, जो अगले दो साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसे लेकर हाल ही में एक भारतीय दल ने रूस का दौरा किया है।

छत्तीसगढ़ में खाद का ‘फुलप्रुफ’ ब्लूप्रिंट और वर्तमान स्टॉक

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य आवंटित किया है। राज्य ने अग्रिम भंडारण तेज कर दिया है और 30 मार्च तक गोदामों में 7.48 लाख मीट्रिक टन खाद का सुरक्षित स्टॉक जमा किया जा चुका है।

यूरिया का सस्ता और जैविक विकल्प: ‘नील हरित काई’ और ‘नैनो यूरिया’ का जादू रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करने और किसानों की लागत घटाने के लिए सरकार आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दे रही है।

नील हरित काई: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से अप्रैल से कृषि विज्ञान केंद्रों और सरकारी उद्यानों में इसके ‘मदर कल्चर’ का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो रहा है। यह तकनीक हवा से नाइट्रोजन सोखकर धान की फसल को प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व देगी।

नैनो फर्टिलाइजर्स: कम खर्च में अधिक पैदावार के लिए नैनो यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और इसके लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

हरी खाद: मृदा स्वास्थ्य (मिट्टी की सेहत) सुधारने के लिए ढेंचा और अन्य दलहनी फसलों के लिए मंडी निधि से विशेष बजट स्वीकृत किया गया है।

किसानों के लिए सलाह

खरीफ2026 के लिए खाद की कोई किल्लत नहीं है। किसानों से अपील की गई है कि वे घबराकर जरूरत से ज्यादा भंडारण न करें। खाद व अन्य सरकारी लाभ सुचारू रूप से पाने के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल पर अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से जल्द से जल्द कराएं और यूरिया के खर्च को कम करने के लिए नैनो यूरिया व नील-हरित काई जैसे विकल्पों को अपनाएं।

यूरिया का उत्पादन कम, खपत ज्यादा

सालाना खपत: करीब 400 लाख मीट्रिक टन।
घरेलू उत्पादन: करीब 300 लाख मीट्रिक टन।
खाद की कमी: लगभग 100 लाख मीट्रिक टन।
इंपोर्ट पर खर्च: यूरिया की कमी को पूरा करने के लिए भारत पूरी तरह इम्पोर्ट पर निर्भर है। 2025 में भारत ने यूरिया आयात पर करीब 20 हजार करोड़ खर्च किए।

पुलवामा ग्रेनेड अटैक में शामिल आतंकी हमजा बुरहान की हत्या

इस्लामाबाद (ए.)। पुलवामा में 2020 में हुए ग्रेनेड हमले में शामिल आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुजफ्फराबाद के एआईएमएस कॉलेज के बाहर अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भारत ने 2022 में हमजा बुरहान को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया था। वह अबू दुजाना, अबू कासिम, बुरहान वानी और जाकिर मूसा का करीबी था।

भारत से पाकिस्तान गया, फिर आतंकी संगठन से जुड़ा: सरकार के मुताबिक, अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ डॉक्टर पुलवामा के रत्नीपोरा इलाके का रहने वाला था। 23 साल का हमजा, आतंकी संगठन अल बद्र से जुड़ा हुआ था। अल बद्र को सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। वह कानूनी तरीके से पाकिस्तान गया था। वहां जाकर वह अल बद्र में शामिल हो गया और बाद में संगठन का सक्रिय आतंकी ■ शेष पृष्ठ 8 पर

ईरान जंग पर ट्रम्प-नेतन्याहू में टकराव, अमेरिका डील चाहता है

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमले जारी रहें, जबकि ट्रम्प फिलहाल बातचीत और डील को मौका देना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि नेतन्याहू ने ट्रम्प से कहा कि ईरान पर प्रस्तावित हमले रोकना गलती है और सैन्य कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। सीएनएन के मुताबिक, ट्रम्प ने रविवार को नेतन्याहू को बताया था कि अमेरिका ईरान पर नए टारगेटेड हमले की तैयारी कर रहा है। इस ■ शेष पृष्ठ 8 पर

राजनाथ ने भारतीय युद्ध स्मारक का किया उद्घाटन

नयी दिल्ली/वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के पूर्व सैनिक मामलों के मंत्री क्वोन ओह-यूल ने गुरुवार को सियोल स्थित इमजिंगाक पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि निर्मित यह स्मारक भारतीय सेना की 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस और कस्टोडियन फोर्स ऑफ इंडिया द्वारा युद्ध के दौरान प्रदर्शित साहस, बलिदान और मानवीय सेवा को समर्पित है।

बीजेपी नेता और युवाओं ने एक-दूसरे को पीटा

दुर्ग-भिलाई/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के भिलाई में जन्मदिन पार्टी के दौरान घर के सामने बीयर की बोतल टूटने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बीजेपी के कैंप-1 मंडल कोषाध्यक्ष राजेश चौधरी ने टूटे कांच साफ करने कहा, तो विवाद हो गया। दो तरफ से गाली-गलौज के बाद हाथ-मुक्कों और डंडे से एक-दूसरे को पीटा गया। जिसका वीडियो भी सामने आया है। मारपीट मामले में समझौते करने देर रात दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे।

पीएम नरेंद्र मोदी की 5 दिवसीय यात्रा से भारत को मिला 40 अरब डॉलर का निवेश

नई दिल्ली/एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पांच दिवसीय यात्रा से भारत को करीब 40 अरब डॉलर के नए निवेश की प्रतिबद्धताएं हासिल हुई हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन और एआई जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली 50 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के CEOs और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इन कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्य 2.7 से 3 ट्रिलियन डॉलर के बीच है।

प्रमुख निवेश घोषणाएं

- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भारत में 5 अरब डॉलर के नए निवेश की घोषणा की।
- कई कंपनियों ने भारत में अपने परिचालन विस्तार और नए निवेश का वादा किया है।

अधिकारियों के अनुसार, यात्रा के दौरान हुई चर्चाओं और प्रस्तावित योजनाओं का कुल अनुमानित ■ शेष पृष्ठ 8 पर

बंगाल के मदरसों में ‘वंदे मातरम’ गाना अनिवार्य

■ मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी सरकार का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला

कोलकाता/ए.। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने एक बेहद बड़ा, कड़ा और दूरगामी सांस्कृतिक व राजनीतिक प्रभाव वाला नीतिगत फैसला लिया है। राज्य सरकार ने गुरुवार को एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी स्कूलों के साथ-साथ अब सभी सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में भी क्लास शुरू होने से पहले यानी प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ गाना पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद से ही राज्य के भीतर और शैक्षणिक हलकों में एक नई कूटनीतिक व ■ शेष पृष्ठ 8 पर

13 मई को सरकारी स्कूलों के लिए जारी हुआ था पहला आदेश

गौरतलब है कि इससे पहले बीते 13 मई की शाम को पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सामान्य सरकारी स्कूलों में ‘वंदे मातरम’ गाना अनिवार्य करने संबंधी पहली अधिसूचना जारी की थी। राज्य के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 14 मई को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर शिक्षा विभाग की इस अधिसूचना को खुद साझा कर जनता को इसकी जानकारी दी थी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी उस अधिसूचना में कहा गया था कि स्कूलों में कक्षाएं शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ का गायन तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा, और अब ठीक इसी तर्ज पर इसे सूबे के सभी श्रेणी के मदरसों पर भी पूरी तरह से बाध्यकारी बना दिया गया है।

सुशासन तिहार : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तेंदूपत्ता संग्राहकों से किया आत्मीय संवाद, सुनी समस्याएं

तेंदूपत्ता संग्राहकों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री, महुआ पेड़ के नीचे लगाई चौपाल

■ चरण पादुका वितरण कर संग्राहकों का बढ़ाया उत्साह: राशन, पेयजल, शिक्षा और महतारी वंदन योजना की ली जानकारी

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सूरजपुर प्रवास के दौरान रामानुजनगर प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण फड़ पटना का निरीक्षण कर तेंदूपत्ता संग्राहकों से आत्मीय संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने तेंदूपत्ता संग्रहण कार्यों का जायजा लेते हुए संग्राहकों की समस्याओं, आजीविका और मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली तथा वनाधारित अर्थव्यवस्था से जुड़े परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के आगमन पर तेंदूपत्ता संग्राहकों ने आत्मीय स्वागत करते हुए तेंदूपत्ता और तेंदू फलों से निर्मित विशेष माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, विधायक भूलन सिंह मरावी तथा वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा का भी सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने संग्राहकों के श्रम और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वनाधारित आजीविका से जुड़े लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण शक्ति हैं और उनके जीवन में ■ शेष पृष्ठ 8 पर

प्रशासनिक कामकाज का लिया फीडबैक

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महुआ पेड़ की छांव में चौपाल लगाकर संग्राहकों से सीधा संवाद किया और कहा कि सरकार स्वयं लोगों का हालचाल जानने गांव-गांव पहुंच रही है। उन्होंने राशन वितरण व्यवस्था, पेयजल उपलब्धता, जल जीवन मिशन की प्रगति, राजस्व प्रकरणों, शिक्षा व्यवस्था तथा महतारी वंदन योजना की राशि प्राप्ति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री साय ने महिलाओं से महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि के उपयोग के बारे में चर्चा करते हुए परिवार की आर्थिक मजबूती और बच्चों की जरूरतों में उसके सकारात्मक उपयोग की जानकारी प्राप्त की।

मौसम की ‘अग्नि’ परीक्षा अभी रहेगी जारी, पूरब में तीन दिन का रेड अलर्ट

लखनऊ/वार्ता। प्रचंड गर्मी और ताप लहरी का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को राहत मिलने के फिलहाल कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा।

पूर्वांचल के लिये मौसम विभाग ने गुरुवार को विशेष तौर पर रेड अलर्ट जारी कर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने और सुबह 11 बजे से शाम पांच तक जरुरी काम से ही घर या दफ्तर से बाहर निकलने की सलाह दी है। गर्मी के तल्ख तेवरों ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। गर्मी से पशु पक्षी भी बेहाल हैं। दिन चढ़ने के साथ पक्षी पेड़ की घनी शाखाओं में दुबक रहे हैं वहीं सड़कों पर सुबह से शाम तक पसरा सन्नाटा गर्मी के प्रचंड रुप की तस्कीद कर रहा है। लू से बचने के लिये लोग घर से बाहर निकलते ही गीले गमछे और तौलिये का इस्तेमाल कर रहे है। इसके अलावा ठंडे शीतल पेय जैसे लस्सी, छाछ,आम का पना,बेल का ■ शेष पृष्ठ 8 पर

गरमा-गरम

भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए दौड़ी दिल्ली स्पेशल,आम यात्रियों को फिर इंतजार

- **बस्तरवासियों की वर्षों पुरानी मांग पर चली ट्रेन, लेकिन नियमित सेवा अब भी अधर में**
- **पहली बार दिल्ली से जुड़ा जगदलपुर,पर उठे कई सवाल**

जगदलपुर/नवप्रदेश। आदिवासी बाहुल्य बस्तर संभाग पहली बार सीधे देश की राजधानी नई दिल्ली से रेल मार्ग से जुड़ गया है। जगदलपुर से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली के लिए विशेष ट्रेन 21 मई को अपने निर्धारित समय पूर्वान्ह 11.15 बजे रवाना हुई। 22 कोच वाली इस विशेष ट्रेन को रेलवे और केंद्र सरकार बस्तर के लिए बड़ी सौगात के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं,लेकिन इस पूरी कवायद को लेकर अब कई सवाल भी उठने लगे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से बस्तरवासी दिल्ली तक नियमित रेल सेवा की मांग करते रहे, लेकिन रेलवे प्रशासन ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। अब अचानक केवल दो फेरों के लिए विशेष ट्रेन चलाए जाने को राजनीतिक कार्यक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 24 मई को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े कार्यक्रम में देशभर से भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी सुनिश्चित करने रेलवे में यह ट्रेन आम यात्रियों को छोड़ भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष व्यवस्था की है।जिससे यह ट्रेन भाजपा कार्यकर्ताओं की यात्रा को ध्यान में रखकर चलाई गई प्रतीत हो रही है।सीमित फेरे से बढ़ी नाराजगी,नियमित सेवा की मांग तेज

रेलवे प्रशासन ने इस ट्रेन को केवल एक फेरों के लिए स्वीकृति दी है। यही वजह है कि बस्तरवासियों में खुशी के साथ नाराजगी भी दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि यदि बस्तर से दिल्ली तक सीधी रेल सेवा संभव है तो इसे नियमित क्यों नहीं किया जा रहा। लंबे समय से रेल सुविधाओं की उपेक्षा झेल रहे बस्तरवासियों को अब भी स्थायी समाधान का इंतजार है।

करीब 1800 किलोमीटर लंबी यात्रा वाली यह ट्रेन जगदलपुर से रवाना होकर कोरापुट, रायपुर, नागपुर, इटारसी, भोपाल, बीना, झांसी और आगरा कैंट होते हुए हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव नहीं दिया गया है, जिससे यात्रा समय अपेक्षाकृत कम रखा गया है। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 08519, 21 मई को जगदलपुर से रवाना होकर 23 मई को सुबह नई दिल्ली पहुंचेगी, जबकि वापसी में ट्रेन संख्या 08520, 25 मई को हजरत निजामुद्दीन से चलकर 26 मई को जगदलपुर पहुंचेगी।

अब बस्तरवासियों की निगाह इस बात पर टिकी है कि रेलवे प्रशासन इस सेवा को वास्तव में जनता की जरूरत समझकर नियमित करता है या फिर यह केवल राजनीतिक आयोजन तक सीमित विशेष सुविधा बनकर रह जाएगी।

22 कोच की ट्रेन में 18 स्लीपर, फिर भी आम यात्रियों के लिए सीमित अवसर

जगदलपुर-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए गए हैं। इनमें 18 स्लीपर कोच,2 सामान्य श्रेणी तथा 2 द्वितीय श्रेणी लगेज सह दिव्यांगजन कोच शामिल हैं। रेलवे प्रशासन ने इसे ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन बताया है,लेकिन स्थानीय लोगों का सवाल है कि बस्तर जैसे बड़े संभाग को वर्षों बाद भी केवल एक फेरों की अस्थायी सुविधा ही क्यों दी जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि रेलवे बोर्ड राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए इतनी शीघ्रता से विशेष ट्रेन चला सकता है तो आम जनता की वर्षों पुरानी मांगों पर स्थायी निर्णय लेने में देरी क्यों की जाती रही।

प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के मॉडल उत्तर जारी

जगदलपुर/नवप्रदेश। प्रयास आवासीय विद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आयोजित कक्षा नवमी प्राक्कयन प्रवेश परीक्षा के मॉडल उत्तर (मॉडल आंसर-की) आदिवासी विकास विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में शामिल छात्र-छात्राएं एवं अभिभावक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मॉडल उत्तरों का अवलोकन कर सकते हैं। विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार यदि किसी परीक्षार्थी या अभिभावक को मॉडल उत्तरों पर किसी प्रकार की आपत्ति या संशय है, तो वे 30 मई 2026 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। विभाग ने परीक्षार्थियों को समय रहते उत्तरों का मिलान कर आवश्यक आपत्तियां दर्ज कराने की सलाह दी है। प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित यह परीक्षा प्रदेश के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।

बेलर में बाहरी व्यक्ति के निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने किया विरोध

एसडीएम और कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच की मांग

- **रात में चोरी-छिपे निर्माण कराने का आरोप, गांव में बढ़ी नाराजगी**

जगदलपुर/नवप्रदेश। लोहंडीगुड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलर में एक बाहरी व्यक्ति द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने मामले को लेकर एसडीएम और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित व्यक्ति को कई बार निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बावजूद वह चोरी-छिपे रात के समय निर्माण कार्य करवा रहा है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि उक्त व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य से गांव में निर्माण करा रहा है, जिसकी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए।

ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय बाद फिर से वही व्यक्ति निर्माण कार्य करता दिखाई दिया। इसकी जानकारी मिलते ही सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य का विरोध किया। इसके बाद ग्रामीण जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को तत्काल मामले की जांच करनी चाहिए। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि बिना जानकारी और अनुमति के किसी भी बाहरी व्यक्ति द्वारा निर्माण कार्य किए जाने से गांव में असंतोष का माहौल बन रहा है।

अंत में मौके पर मौजूद तहसीलदार लोहंडीगुड़ा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीणों ने जताई विशेष उद्देश्य की आशंका

बेलर गांव के ग्रामीणों ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि बाहरी व्यक्ति द्वारा लगातार विरोध के बावजूद निर्माण कार्य कराया जाना संदेह पैदा करता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य की अनुमति, उद्देश्य और संबंधित दस्तावेजों की जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए।

बस्तर जिले को मिली 11 अत्याधुनिक डायल 112 वाहन और फॉरेंसिक मोबाइल वैन

- **आपातकालीन सेवा और वैज्ञानिक जांच प्रणाली को मिलेगा बल**
- **एआई आधारित लोकेशन तकनीक से त्वरित सहायता होगी संभव**

जगदलपुर/नवप्रदेश। बस्तर जिले की आपातकालीन पुलिस सेवा और वैज्ञानिक अनुसंधान व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मंगलवार को महत्वपूर्ण पहल की गई। लालबाग मैदान में आयोजित कार्यक्रम में विधायक किरण देवसिंह और आईजी सुन्दराज पी ने जिले के लिए ग्यारह अत्याधुनिक डायल 112 वाहन तथा फॉरेंसिक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में डायल 112 वाहनों का विधिवत पूजा-अर्चना कर उनमें उपलब्ध आधुनिक संसाधनों की जानकारी भी ली गई।

कार्यक्रम में बताया गया कि राज्य में वर्ष 2018 से संचालित डायल 112 आपातकालीन सेवा का विस्तार अब सभी 33 जिलों तक कर दिया गया है, जबकि पहले यह सेवा केवल 16 जिलों में संचालित थी। नई व्यवस्था के तहत तकनीकी रूप से उन्नत संसाधनों को जोड़ा गया है, जिससे पुलिस सहायता और आपात प्रतिक्रिया प्रणाली पहले से अधिक तेज और प्रभावी होगी। डायल 112 सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित लोकेशन पहचान तकनीक भी जोड़ी गई है, जिससे संकटग्रस्त व्यक्ति की सटीक भौगोलिक स्थिति का पता लगाकर तत्काल सहायता पहुंचाई जा सकेगी। 18 मई को राजधानी रायपुर में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की अत्याधुनिक डायल 112 सेवा और आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन के बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।

एआई आधारित लोकेशन ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं

बस्तर जिले को मिली नई डायल 112 सेवा में अत्याधुनिक संचार प्रणाली,त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र और एआई आधारित लोकेशन ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। वहीं फॉरेंसिक मोबाइल वैन के माध्यम से घटनास्थल पर ही प्रारंभिक वैज्ञानिक जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे अपराध अनुसंधान में तेजी आएगी और साक्ष्यों के संरक्षण एवं विश्लेषण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सकेगी।

सुशासन तिहार शिविर में उमड़ी ग्रामीणों की भागीदारी

- **कुरुषपाल शिविर में 236 आवेदन प्राप्त, विकास कार्यों की मिली सौगात**

जगदलपुर/नवप्रदेश। बस्तर विकासखंड के ग्रामीण अंचल कुरुषपाल में बुधवार को आयोजित सुशासन तिहार शिविर में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में विभिन्न समस्याओं और मांगों से संबंधित कुल 236 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर प्रशासनिक अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की। शिविर में विभिन्न विभागों ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर योजनाओं की जानकारी दी और मौके पर ही लाभ भी वितरित किया।

शिविर में क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए 36.06 लाख रुपए की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई तथा पूर्ण हो चुके कार्यों को जनता को समर्पित किया गया। इसके साथ ही विधायक निधि से 4.50 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 1.50 मीटर लंबी पुलिया निर्माण कार्य का मार्ग भी प्रशस्त किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र हितग्राहियों को पक्के मकानों की स्वीकृति दी गई, जबकि मनरेगा के अंतर्गत डबरी निर्माण कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई।

बस्तर के 377 गाँवों में जन भागीदारी अभियान का आगाज

- **दूरस्थ अंचलों तक योजनाओं की पहुंच और शिकायत निवारण पर विशेष फोकस**

जगदलपुर/नवप्रदेश। बस्तर जिले के दूरस्थ और जनजातीय अंचलों तक शासन की योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने तथा ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से जिले में जन भागीदारी-सबसे दूर, सबसे पहले थीम के तहत आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया गया है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार संचालित यह अभियान धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जिले के चयनित 377 ग्रामों में व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है।

परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना जगदलपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस राष्ट्रीय स्तर के सूचना,शिक्षा और संचार अभियान का उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों में सीधा जमीनी संपर्क स्थापित करना, शासन की सेवाओं की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाना और आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों की शिकायतों का समाधान करना है।

शासन की योजनाओं और सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना

जन भागीदारी- दूर,सबसे पहले थीम के तहत शुरू किए गए आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य बस्तर के दूरस्थ जनजातीय गांवों तक शासन की योजनाओं और सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है। अभियान के माध्यम से ग्रामीणों की शिकायतों का त्वरित समाधान,स्वास्थ्य एवं सामाजिक जागरूकता,जनसुनवाई और सेवा संतृप्ति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

पत्नी की पिटाई से मौत मामले में पति को 10 वर्ष की सजा

जगदलपुर/नवप्रदेश। बस्तर संभाग मुख्यालय स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ने पत्नी की पिटाई से हुई मौत के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान सत्र न्यायाधीश गोविंद नारायण जांगड़े की अदालत ने आरोपी सोनसिंग कश्यप को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत हत्या के आरोप से दोषमुक्त किया, लेकिन धारा 105(2) के तहत गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी पर 100 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला 1 जुलाई 2025 का है। थाना बंडाजी क्षेत्र के ग्राम पोटनार कोटवारपारा में आरोपी सोनसिंग कश्यप का अपनी पत्नी लच्छनदई के साथ शराब पीने की बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान आरोपी ने पत्नी के शरीर के पुराने घाव वाले हिस्सों पर लात-घूंसों से बेरहमीपूर्वक हमला किया। मारपीट में उसका पैर टूट गया तथा कंधे और छाती में गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार घटना के बाद आरोपी ने घायल पत्नी का समुचित उपचार नहीं कराया।

माओवाद मुक्त क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

- **कमिश्नर डोमन सिंह ने संभाग स्तरीय अधिकारियों की ली मासिक समीक्षा बैठक**

जगदलपुर/नवप्रदेश। बस्तर संभाग के कमिश्नर डोमन सिंह ने गुरुवार को संभाग स्तरीय अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि माओवाद मुक्त हो चुके अंदरूनी क्षेत्रों में शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा ग्रामीणों को सभी लोक सेवाएं सरल और सहज तरीके से उपलब्ध कराई जाएं।

कमिश्नर ने कहा कि शासन की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसके लिए अधिकारियों को मैदानी स्तर पर सतत मॉनिटरिंग करते हुए दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली और आजीविका से जुड़ी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में हाल के वर्षों में विकास कार्यों की पहुंच बढ़ी है, वहां संवेदनशीलता के साथ कार्य कर शासन के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत करना आवश्यक है।

राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पटेल और कोटवार के रिक्त पदों को अभियान चलाकर शीघ्र भरने के निर्देश दिए। साथ ही अविवादित नामांतरण-बंटवारा प्रकरणों के निराकरण, भू-स्वामियों को खसरा बी-वन नकल, किसान किताब और व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टों की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध कराने तथा फौती-नामांतरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने कहा।

कमिश्नर ने सुशासन तिहार, बस्तर मुन्ने और नियद नेल्लानार शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों की मांगों और शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को खाद-बीज, किसान क्रेडिट कार्ड, सब्जी बीज मिनीकिट, उद्यानिकी पौधे, मत्स्यपालन सहायता, बैकयार्ड कुक्कुटपालन और सूकरत्रयी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने,सभी हैंडपंप और नलजल योजनाओं को चालू रखने तथा नए विद्युत कनेक्शन और ट्रांसफार्मर स्थापना को प्राथमिकता देने कहा।

संभाग स्तरीय लोक सेवाओं को सुलभ बनाने पर विशेष जोर

बैठक में माओवाद मुक्त क्षेत्रों में विकास योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और लोक सेवाओं को सुलभ बनाने पर विशेष जोर दिया गया। कमिश्नर डोमन सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ दूरस्थ गांवों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए। बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली, सड़क और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

ओबीसी कोटे में तय सीमा से अधिक दिव्यांगों को नियुक्ति देना गलत, आरक्षण नियमों का हो पालन: हाईकोर्ट

बिलासपुर/नवप्रदेश। हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी पर कहा कि, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित पदों पर तय सीमा से अधिक दिव्यांग उम्मीदवारों को केवल उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति देना कानूनन गलत है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मेरिट लिस्ट की समीक्षा कर 90 दिन के भीतर दोबारा मेरिट लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल उमेश कुमार श्रीवास, नेहा साहू, प्रमोद कुमार साहू सहित कई लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय ने 9 मार्च 2019 को व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के कई खाली पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिका में बताया गया कि, इस भर्ती में ओबीसी वर्ग के याचिकाकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया और मेरिट सूची में स्थान बनाया। लेकिन, जब चयन समिति ने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की, तो ओबीसी कैटेगरी के पदों पर 7% की तय सीमा से कहीं ज्यादा दिव्यांग उम्मीदवारों को चुन लिया गया। व्याख्याता बायोलॉजी ई-संवर्ग के लिए कुल 200 पद भरे जाने थे, जिसमें ओबीसी के हिस्से के पदों में से 14 पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित होने चाहिए थे, लेकिन चयन समिति ने ओबीसी कोटे के तहत ही 6 दिव्यांगों को उनकी मेरिट के आधार पर सीधे नियुक्त कर दिया। जिससे सामान्य ओबीसी उम्मीदवारों का हक प्रभावित हुआ। यही तरीका शिक्षक गणित और सहायक शिक्षक विज्ञान भर्ती में भी अपनाया गया।

हाईकोर्ट बोला- प्रक्रिया गलत और बराबरी के खिलाफ

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि, चयन समिति की तरफ से अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। इस तरह की प्रक्रिया से सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को समान अवसर नहीं मिल पाता है। अधिकारियों को दिव्यांगों को समान अवसर देने के लिए आरक्षण नियमों का सही पालन करना चाहिए था।

सरकार ने कहा- मेरिट में होने से मौका

राज्य सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि, जिन दिव्यांग उम्मीदवारों का चयन किया गया, उन्होंने मेरिट सूची में ऊंचा स्थान हासिल किया था। सर्कुलर के अनुसार उनकी योग्यता को देखते हुए बिना उनकी मूल श्रेणी की परवाह किए उन्हें नियुक्ति दी गई। वहीं, याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया क चयन समिति की यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ है।

इंदिरा साहनी मामला के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी और राजेश कुमार डरिया मामलों का हवाला देते हुए सामाजिक और विशेष आरक्षण के अंतर को समझाते हुए कहा कि वर्टिकल आरक्षण यानी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार यदि अपनी योग्यता से जनरल सीट लाते हैं, तो उन्हें कोटे में नहीं गिना जाता। वहीं होरिजोंटल आरक्षण यानी दिव्यांग, महिलाओं में से कोई दिव्यांग उम्मीदवार मेरिट से चुनकर आता है, तो उसे उसकी संबंधित सामाजिक श्रेणी के कोटे में ही समायोजित किया जाएगा, जिससे कुल आरक्षण का प्रतिशत न बदले।

न्यूज गैलरी

नागपुर में रोजगार मेले का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ

बिलासपुर/नवप्रदेश। देश के युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित 'रोजगार मेला' अभियान के तहत, 23 मई (शनिवार) को '19वां रोजगार मेला' देशभर के 47 शहरों में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का केंद्रीय शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रातः 11 बजे किया जाएगा। इसी क्रम में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल द्वारा इस मेले का आयोजन 'ऑडिटोरियम, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज (एनएफएससी), पुलिस लाइन टाकली फीडर रोड, राजनगर, नागपुर' में किया जाएगा, जिसकी शुरुआत प्रातः 10 बजे होगी। यह कार्यक्रम युवाओं के लिए न केवल एक अवसर है, बल्कि देश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी का प्रतीक भी है। इस रोजगार मेले में रेलवे, डाक, रक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न केंद्रीय विभागों में चयनित कुल 315 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इससे न केवल चयनित अभ्यर्थियों को उनके भविष्य के निर्माण में एक सशक्त आधार मिलेगा, बल्कि यह पहल समूचे क्षेत्र के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी। इस गरिमामयी अवसर पर नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र उनके शुभ हाथों से प्रदान किए जाएंगे।

बिलासपुर गुड्स शेड 28 से स्थायी रूप से बंद

बिलासपुर/नवप्रदेश। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल द्वारा माल परिवहन सुविधाओं के सुव्यवस्थित संचालन एवं बेहतर यातायात प्रबंधन के उद्देश्य से उसलापुर स्टेशन में गुड्स शेड प्रारम्भ किया गया है 7 साथ ही बिलासपुर स्थित गुड्स शेड (माल गोदाम) को 28 मई से स्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। उसलापुर स्टेशन में गुड्स शेड एक पब्लिक गुड्स शेड के रूप में कार्य करेगा। जिसका कोड UGSU और न्यूमेरिकल कोड - 14122915 है। इस गुड्स शेड के माध्यम से कोई भी व्यापारी, संस्थान अथवा आम नागरिक अपना माल भेज एवं मंगा सकेगा।

पीने की पानी की भी किल्लत, सप्लाई बहाल नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

बिजली आपूर्ति बाधित, लोगों ने ऑफिस का किया घेराव

बिलासपुर/नवप्रदेश। भीषण गर्मी के बीच बदहाल बिजली व्यवस्था से लोग परेशान हैं। ओवरलोड के कारण कहीं ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं तो कहीं तकनीकी खराबी आ रही है। वहीं बिना सूचना के होने वाले मेंटेनेंस ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आए दिन बिजली आपूर्ति बाधित होने से नाराज लोगों ने नेहरू नगर स्थित बिजली कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया।

लोगों का कहना है कि बिजली कटौती के कारण अब पीने के पानी की भी किल्लत होने लगी है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं विभाग ने समस्या समाधान का आश्वासन दिया है। नेहरू नगर के मंगला क्षेत्र, भक्त कंवरराम नगर, कस्तूरबा नगर और सिंधी कॉलोनी में इन दिनों बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में लगातार बिजली कटौती हो रही है, लेकिन शिकायतों के बावजूद विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। बुधवार रात भी कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही और अगले दिन तक सप्लाई सामान्य नहीं हो सकी। बिजली बंद रहने से पानी सप्लाई भी प्रभावित हुई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी के बीच लोगों को रातभर अंधेरे में गुजारना पड़ा, जिससे क्षेत्र में भारी नाराजगी देखने को मिली।

ट्रांसफार्मर में लगी आग, मची अफरा-तफरी

गुरुवार सुबह स्थिति उस समय और बिगड़ गई, जब सिंधी कॉलोनी के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर लंबे समय से खराब हालत में था और समय रहते मरम्मत या सुधार कार्य किया जाता तो यह स्थिति नहीं बनती। रहवासियों ने आरोप लगाया कि लो वोल्टेज की समस्या के कारण कई घरों के बिजली उपकरण और पानी की मोटर भी खराब हो चुकी हैं।

बिजली ऑफिस पहुंचकर किया प्रदर्शन, की नारेबाजी

समस्या से परेशान बड़ी संख्या में वार्डवासी गुरुवार सुबह नेहरू नगर स्थित बिजली कार्यालय पहुंचे और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया और नियमित बिजली सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं, बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही ट्रांसफार्मर बदलकर बिजली व्यवस्था सामान्य कर दी जाएगी।

नीट-यूजी पेपर घोटाले पर एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन

बिलासपुर/नवप्रदेश। एनएसयूआई ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों के भविष्य से जुड़े इस बहुचर्चित घोटाले को लेकर संगठन ने जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और एनटीए को तत्काल भंग करने की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एनएसयूआई जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह ने बेहद आक्रामक तेवर में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यदि सरकार देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं रख सकती, तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने शेरो-शायरी के अंदाज में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा – 'कुर्सी है तुम्हारा ये जनाज़ा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते! रंजीत सिंह ने कहा कि नीट-यूजी 2026 में हुआ कथित पेपर लीक केवल परीक्षा में अनियमितता नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के सपनों और मेहनत की हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की लापरवाही और शिक्षा व्यवस्था की विफलता ने देश के युवाओं को अविश्वास, तनाव और मानसिक प्रताड़ना के माहौल में धकेल दिया है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पूरी तरह टूट चुकी है। एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफे की मांग भी की। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए रंजीत सिंह ने कहा कि 'परीक्षा पे चर्चा' करने वाली सरकार अब यह बताए कि परीक्षा सुरक्षित क्यों नहीं है।

हत्या का साक्ष्य छुपाने वाले आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर/नवप्रदेश। हत्या कर साक्ष्य छुपाने वाले आरोपी को बेलगहना पुलिस ने चंद घण्टों में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उमेन्द सिंह पटेल निवासी ग्राम रतखण्डी का चौकी बेलगहना में आकर सूचना दर्ज कराया कि 19.05.2026 से 20.05.2026 की दरम्यानी रात इसका पुत्र गौरीशंकर पटेल पिता उमेन्द सिंह पटेल उम्र 23 वर्ष निवासी रतखण्डी की जहर सेवन से मृत्यु हो गयी है और आत्महत्या करने में उपयोग की गई जहर की शीशी वहीं पड़ी हुई है। प्रार्थी की उक्त सूचना पर बेलगहना पुलिस के द्वारा धारा 194 बीएनएसएस अन्तर्गत मर्ग कायम कर जांच कार्यवाही में ली गई जांच पंचनामा के दौरान पुलिस को मृतक की मृत्यु और परिस्थितियों को देखकर मामले में अपराध के घटित होने का संदेह पैदा हुआ, जिस पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को अवगत कराकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह,

अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा नुपुर उपाध्याय से दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शन से प्राप्त कर बेलगहना पुलिस के द्वारा फॉरेन्सिक टीम को घटना स्थल पर बुलाकर घटना स्थल एवं शव का बरीकी से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मृतक गौरीशंकर के बदन पर साधारण चोटों के निशान तथा अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य मिले घटना पर से ही जहर का खाली डब्बा भी बरामद हुआ उक्त संदिग्ध परिस्थितियों के आधार पर बेलगहना पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाते हुये मृतक गौरीशंकर पटेल के शव का पीएम कराया गया मृतक गौरीशंकर की हत्या का साक्ष्य मिलने पर बेलगहना पुलिस के द्वारा अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 103 (1) बीएनएस अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर अज्ञात आरोपी की तलाश में जुट गई विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक गौरीशंकर शराबी एवं झगड़ालू किस्म का था जो अपने घर वालों से अक्सर विवाद झगड़ा करता था। कुछ दिन पूर्व भी उसने घगड़ा किया था तो उसके खिलाफ पुलिस ने 151 की कार्यवाही कर जेल भेजा था ।घटना दिनांक की रात भी मृतक आत्याधिक शराब के नशे में था, परिस्थितियों को देखते हुये पुलिस को मृतक के परिजनों पर संदेह होने लगा तब पुलिस ने मृतक गौरीशंकर के परिजनों से पूछताछ की जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।, घटना दिनांक की रात अत्याधिक शराब के नशे में मारपीट पर उतारू था तब आरोपी पिता उमेन्द सिंह पटेल, मृतक का भाई शिवशंकर पटेल एवं एक अपचारी बालक के द्वारा मृतक को मारपीट कर गिरा दिया गया, और रस्सी से उसके हाथ पैर को बांध कर उसके मुंह को उसके मृत्यु होते तक दबा कर रखना बताया।

सुशासन तिहार से जनता की समस्याओं का हो रहा त्वरित निराकरण : विधायक धरमलाल कौशिक

बिल्हा समाधान शिविर में 102 आवेदन मिले, हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ

बिलासपुर/नवप्रदेश। नगर पंचायत बिल्हा के मंडी प्रांगण में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लेकर विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। शिविर का आयोजन श्री धरमलाल कौशिक के मुख्य आतिथ्य तथा अपर मुख्य सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव मनोज पिंगुआ की उपस्थिति में संपन्न हुआ। शिविर में कुल 102 आवेदन प्राप्त हुए। विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने सभी मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्रीश्री विष्णु देव साय के निर्देश पर सुशासन तिहार के माध्यम से प्रशासन सीधे गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और कोई भी जरूरतमंद हितग्राही शासन की योजनाओं से वंचित न रहे। क्रेडा के अध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी ने कहा कि सुशासन तिहार शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बना है। उन्होंने कहा कि शिविरों के जरिए ग्रामीणों एवं शहरी नागरिकों को त्वरित राहत और योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अपर मुख्य सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव श्री मनोज पिंगुआ ने कहा कि सुशासन तिहार शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम बना है। उन्होंने अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि शिविरों के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा मौके पर ही आवेदनों का निराकरण कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

उपलब्धिः शहर के युवा खिलाड़ी अवि मानिकपुरी अब भारतीय जर्सी में एशियाई हॉकी मंच पर नजर आएंगे

एशिया कप में गूंजेगा शहर का नाम, भारतीय हॉकी टीम में अवि का चयन

बिलासपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ और बिलासपुर के लिए गर्व का बड़ा क्षण सामने आया है। बिलासपुर शहर के होनहार हॉकी खिलाड़ी अवि मानिकपुरी का चयन भारतीय अंडर-18 पुरुष हॉकी टीम में हुआ है, जो आगामी Mens -18 Asia Cup 2026 में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 29 मई से 6 जून 2026 तक जापान के काकामिगाहारा शहर में आयोजित होगा। भारतीय टीम में जगह बनाकर अवि ने न सिर्फ अपने परिवार और कोच समीर दाद का सपना पूरा किया है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान दिलाई है। इस उपलब्धि के बाद बिलासपुर में खेल प्रेमियों, हॉकी खिलाड़ियों और सामाजिक संगठनों में उत्साह का माहौल है। शहर के युवा खिलाड़ी अवि मानिकपुरी अब भारतीय जर्सी में एशियाई हॉकी मंच पर नजर आएंगे। अवि मानिकपुरी के पिता जितेंद्र मानिकपुरी और माता शशिकल मानिकपुरी लंबे समय से अपने बेटे को राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाने के लिए प्रेरित करते रहे। परिवार के सहयोग और लगातार अभ्यास ने अवि को इस मुकाम तक पहुंचाया। स्थानीय स्तर से शुरुआत कर राष्ट्रीय चयन शिविर तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन अवि ने हर चुनौती को अवसर में बदला। उनके कोच

समीर दाद ने कहा कि अवि शुरू से ही अनुशासित और आक्रामक खेल शैली के खिलाड़ी रहे हैं। मैदान पर उनकी फिटनेस, डिफेंस में पकड़ और तेज निर्णय क्षमता ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। हॉकी इंडिया ने एशिया कप से पहले भोपाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाई-इंटेंसिटी सीरीज आयोजित की थी। इसी कैंप और प्रदर्शन के आधार पर अंतिम टीम का चयन किया गया। चयन से पहले खिलाड़ियों की फिटनेस, मैच अवेयरनेस और दबाव में प्रदर्शन को परखा गया। भारतीय अंडर-18 टीम की कप्तानी केतन कुशवाहा को सौंपी गई है, जबकि अवि मानिकपुरी को डिफेंडर के रूप में टीम में शामिल किया गया है। **भारतीय टीम में चयनित खिलाड़ी :** गोलकीपरः सावन कुमार, आयुष राजक, डिफेंडर्सः अंश बहुत्रा, अरमान सोरेंग, आशीष तानी पूर्ति, अर्शदीप सिंह, अवि मानिकपुरी, रोमित पाल, मिडफील्डर्सः राहुल यादव, प्रेमचंद सोय, वरिंदर सिंह, करण गौतम, सिद्धार्थ बेन फॉरवर्ड्सः, केतन कुशवाहा (कप्तान), आकाश दीप, गाजी खान, शाहरुख अली, प्रह्लाद राजभर।

जापान में होगा एशिया का महामुकाबला

मेंस -18 एशिया कप 2026 का आयोजन जापान हॉकी एसोसिएशन और एशियन हॉकी फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। भारत को ग्रुप-ए में रखा गया है, जहां उसका मुकाबला जापान, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपे और कजाकिस्तान जैसी मजबूत टीमों से होगा। टूर्नामेंट जापान के कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज हॉकी स्टेडियम में खेलाजाएगा अवि मानिकपुरी का भारतीय टीम में चयन केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं माना जा रहा, बल्कि यह बिलासपुर और छत्तीसगढ़ की हॉकी प्रतिभा की बड़ी पहचान बनकर उभरा है। खेल जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि अवि की सफलता आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की प्रेरणा देगी। शहर में लगातार मिल रही बधाइयों के बीच अब सभी की निगाहें जापान में होने वाले मुकाबलों पर टिक गई हैं, जहां बिलासपुर का यह युवा खिलाड़ी तिरंगे के लिए मैदान में पसीना बहाता नजर आएगा।

बिलासपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष अजीत मिश्रा बने एमसीएमसी के सदस्य, कलेक्टर होंगे अध्यक्ष

बिलासपुर/नवप्रदेश। बिलासपुर में आगामी स्थानीय चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनाव में पेड न्यूज और विज्ञापनों पर पैनी नजर रखने के लिए 'मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति यानी MCMC' का गठन किया गया है। और बड़ी खबर यह है कि बिलासपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजीत मिश्रा को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में बनी इस हाई-प्रोफाइल कमेटी में जनसंपर्क विभाग के संयुक्त संचालक एसडी पटेल को सदस्य

सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव के दौरान अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक दल और प्रत्याशी वोटर्स को लुभाने के लिए नियमों को ताक पर रख देते हैं। इसी को रोकने के लिए यह समिति अब 24 घंटे एक्टिव मोड पर रहेगी। आपको बता दें कि इस MCMC कमेटी के मुख्य काम क्या होंगे- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर चलने वाले हर राजनीतिक विज्ञापन का प्री-सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणीकरण करना, पेड न्यूज' जैसे मामलों की कड़ाई से जांच करना।

सुविचार

ऐसा कुछ जो आपको अभी तक मिला नहीं, उसे पाने के लिए आपको ऐसा कुछ करना होगा जो आपने अब तक किया नही।

बड़े नेता तो वाणी पर संयम रखें

राजनीति में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही रहते हैं किन्तु बड़े नेताओं को तो कम से कम आरोप लगाने के समय अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। मर्यादा की सीमा रेखा नहीं लांघनी चाहिए। राजनीतिक सुचिता बनाए रखने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है किन्तु देखा जा रहा है कि विपक्ष के नेता लगातार विवादास्पद और भड़काऊ बयानबाजी करते रहते हैं और इस पर पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष के नेता भी उन्हीं की भाषा बोलने लगते हैं इसका संदेश पार्टी के अन्य नेताओं पर गलत पड़ता है और वे अपने बड़े नेताओं की देखादेखी जो मुंह में आये बोलने लगते हैं जिससे राजनीति में कटुता बढ़ती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा गृहमंत्री अमित शाह को लेकर बेहद विवादास्पद टिप्पणी कर दी है। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तथा आरएसएस को गद्दार करार दे दिया है। उनका आरोप है कि ये रोज संविधान पर हमला कर रहे हैं और चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथों देश का हित बेच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को इस तरह की विवादास्पद टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी किन्तु उनके लिए यह कोई नई बात नहीं है वे पहले भी कई बार देश की 140 करोड़ जनता द्वारा चुने गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं और इसका उनकी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ चुका है। खुद उन्हें भी न्यायालय में माफी मांगनी पड़ी है इसके बावजूद भी वे सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। वेवजह वे आक्रामक तेवर दिखाते हैं और हास्य का पात्र बनकर रह जाते हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। वहीं भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नबीन ने राहुल गांधी पर तिखा वार करते हुए कहा है कि उनका यह बयान राहुल गांधी की अराजक सोच और चरित्र को दर्शाता है इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि न सिर्फ उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का अपमान किया है बल्कि देश की 140 करोड़ जनता को अपमानित किया है। भाजपा के भाजपा के बड़बोले नेताओं ने भी राहुल गांधी के खिलाफ टिका टिप्पणी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फणडवीस ने तो रिजेक्टेट माल कह कर उनकी खिल्ली उड़ा दी है। सही बात है कि कृया की प्रतिक्रिया तो होती ही है। राहुल गांधी को कम से कम अपने पद की गरिमा का तो ख्याल रखना चाहिए वे लोकसभा में नेताप्रतिपक्ष है इसलिए उन्हें शालीनता का परिचय देना चाहिए। विपक्ष के नेताओं को चाहिए कि इस तरह की अपमानजनक टिका टिप्पणी करने से परहेज करें। यह ठीक है कि राजनीति में पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद होते हैं लेकिन मर्यादा की सीमा रेखा किसी को भी नहीं लांघनी चाहिए अन्यथा दुनिया में भारतीय लोकतंत्र का मजाक बनता है।

बस्तर को लेकर पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप

बस्तर को नक्सली आंतक के अभिशाप से मुक्ति मिल गई है लेकिन अब बस्तर के लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरापे प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है गौरतलब है कि बस्तर प्रवास पर आये केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बस्तर पर नक्सली आंतक का सफाया पहले ही हो जाता यदि उस समय सत्तारूढ़ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के नक्सली उन्मूलन अभियान ने केन्द्र सरकार का सहयोग किया होता। गृह मंत्री अमित शाह की यह बात को छत्तीगसगढ़ के तात्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुभ गई और उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं और उनका बयान झूठ का पुलिंदा है। भूपेश बघेल के इस बयान पर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि झूठ बोलने में तो कांग्रेस पार्टी माहिर है। यदि भूपेश सरकार ने वास्तव में उतना प्रभावी काम किया होता तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बहुत पहले कमजोर पड़ जाता। सीएम साय के मुताबिक नक्सलवाद जैसे गंभीर और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अतिसंवेदनशील विषय पर राजनीतिक भ्रम फैलाना और विवादास्पद बयानबाजी करने की जगह ईमानदारी से आत्ममंथन करना चाहिए। सीएम साय की यह बात सही है। वास्तव में अब जबकि सांप गुजर गया है तो लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होगा। बस्तर को नक्सली हिंसा से मुक्ति मिल गई है। और यह नवप्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए एक स्वर्णिम उपलब्धि है। जिसपर समुचे छत्तीसगढ़ को गर्व है। अब बस्तर को लेकर परस्पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है। बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर बस्तर के विकास के लिए समवेत प्रयास करना चाहिए क्योंकि बस्तर में गनतंत्र की समाप्ति के बाद वहां सच्चे अर्थों में गणतंत्र स्थापित करने के लिए भागीरथ प्रयास करने होंगे और इसमें विपक्ष को भी अपनी सहभागिता दर्ज करानी होगी। बेहतर होगा कि अब नक्सली हिंसा को लेकर विवाद का पटाक्षेप किया जाये और बीती ताही बिसार कर आगे की सुध ली जाये।

जलवायु परिवर्तन और हीटवेव

दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर दोपहर की धूप भारी पड़ रही है, लेकिन 48 वर्षीय रिक्शा चालक रमेश के लिए काम रोकना कोई विकल्प नहीं है। करीब 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में वह ट्रैफिक के बीच पसीने से लथपथ पैडल चलाते हैं। हर कुछ मिनट में वह गले में लिपटे पुराने तौलिये से अपना चेहरा पोंछते हैं। फ्लाईओवर की छाया में कुछ पल रुकते हुए वह कहते हैं, "अगर मैं काम रोक दूं, तो मेरे बच्चों को परेशानी होगी।"

- उमानाथ सिंह

भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत दक्षिण एशिया के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी का कहर जारी है, जहां कई इलाकों में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण हीटवेव अब पहले से अधिक लंबी और कई बार जानलेवा हो रही हैं। यह भीषण और लंबी चलने वाली गर्मी लाखों लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी को संघर्ष में बदल रही है। भीड़भाड़ वाले शहरों से लेकर सूखे से जूझते गांवों तक, बढ़ता तापमान मजदूरों, किसानों, बच्चों, बुजुर्गों और डिलीवरी कर्मियों पर गंभीर असर डाल रहे हैं।

कई भारतीय शहरों में दोपहर के समय सड़कें सूनी दिखाई देती हैं, क्योंकि लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, हालांकि उनके पास जरूरी काम भी होते हैं। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, हीट एक्सॉशन, चक्कर और सांस से जुड़ी समस्याओं के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टरों के अनुसार, खुले में काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा जोखिम में हैं, क्योंकि वे लंबे समय तक सीधी धूप में रहते हैं। सड़क किनारे काम करने वाले विक्रेताओं के लिए यह गर्मी आर्थिक संकट भी बन रही है। नोएडा एक्सटेंशन के फल विक्रेता रामधन बताते हैं कि दिन के समय ग्राहक कम हो जाते हैं। वह कहते हैं, "पहले भी गर्मी होती थी, लेकिन अब यह असहनीय लगती है। कई बार फल बिकने से पहले ही खराब हो जाते हैं, जिससे काम चलाना मुश्किल हो जाता है।" हीटवेव का असर बिजली और पानी की आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। कई इलाकों में उसी समय बिजली कटौती हो रही है, जब पंखों और कूलरों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। गिरते भूजल स्तर के कारण कई क्षेत्रों में पानी के टैंकर आते- जाते देखे जा सकते हैं। पानी की कमी ने गर्मी को और भी असहनीय बना दिया है।

बढ़ते तापमान के बीच लोगों को न सिर्फ गर्मी बल्कि पीने के पानी की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। सूखे नल, घटते जलाशय और बार-बार बिजली कटौती से खासकर गरीब, किसान और कमजोर वर्गों की परेशानियां बढ़ गई हैं।

ग्रामीण इलाकों में हालात उतने ही चिंताजनक हैं। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान बताते हैं कि तेज गर्मी और मिट्टी में नमी की कमी से फसलें तेजी से सूख रही हैं। कई किसानों को डर है कि मौसम की अनिश्चितता उन्हें कर्ज के बोझ में और धकेल सकती है।

दक्षिण एशिया के शहरों में 'अर्बन हीट आइलैंड' प्रभाव भी जलवायु परिवर्तन के असर को बढ़ा रहा है। दिल्ली, जयपुर, कराची, ढाका और लाहौर जैसे शहरों में तेजी से बढ़ता शहरीकरण, कंक्रीट ढांचे, घटती हरियाली और बढ़ता प्रदूषण तापमान को खतरनाक स्तर तक ले जा रहे हैं। इन शहरों में हीटवेव, पानी की कमी, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम तेजी से बढ़ रहे हैं।

बच्चे और बुजुर्ग विशेष रूप से खतरे में हैं। कई क्षेत्रों में स्कूलों ने आउटडोर गतिविधियां कम कर दी हैं या गर्मी की छुट्टियां पहले ही घोषित कर दी हैं। डॉक्टर लोगों को दोपहर के समय बाहर न निकलने, अधिक पानी पीने और जितना हो सके घर के अंदर रहने की सलाह दे रहे हैं।

हालांकि, रोज कमाने-खाने वाले लाखों लोगों के लिए घर में रहना संभव नहीं है। शाम होते ही वे थोड़ी देर आराम के बाद फिर काम पर निकल पड़ते हैं। शाम की सड़कों पर भी गर्मी कम नहीं होती, गर्म हवाएं भट्टी जैसी महसूस होती हैं। फिर भी रिक्शा चालक और ठेले वाले काम पर लौटते हैं, क्योंकि एक दिन की कमाई का नुकसान उनके लिए संभव नहीं है। उनके लिए जलवायु परिवर्तन कोई दूर की बहस नहीं, बल्कि रोज की कड़वी सच्चाई बन चुका है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे गर्म मौसम का होना अब कोई नई बात नहीं रह गई है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण बढ़ता वैश्विक तापमान दुनिया भर में मौसम के पैटर्न को बदल रहा है। घनी आबादी और बड़ी संख्या में खुले में काम करने वाले लोगों के कारण दक्षिण एशिया जलवायु परिवर्तन के लिहाज से सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता है। वहीं, शहरों में घटती हरियाली भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, जिससे मौसम का चरम पर गर्म होना और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटना और कठिन होता जा रहा है।

प्रकृति का मौन क्रंदन, खतरे में जीवन की श्रृंखला

योगेश कुमार गोयल
वरिष्ठ पत्रकार

धरती पर जीवन का आधार केवल मनुष्य नहीं है बल्कि जीव-जंतु, पक्षी, कीट-पतंगे और पेड़-पौधे भी इस पारिस्थितिकी तंत्र का उतना ही अहम हिस्सा हैं। फिर भी मनुष्य ने अपने स्वार्थों और तथाकथित विकास के नाम पर जिस प्रकार वनों की अंधाधुंध कटाई, वन्य जीवों के आवासों का विनाश और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है, उसने धरती की जैव विविधता को गहरे संकट में डाल दिया है। जैव विविधता केवल कुछ जीवों या पौधों की गिनती भर नहीं है, यह पूरी पारिस्थितिकी का वह संतुलन है, जो जीवन को संभव और सुरक्षित बनाता है लेकिन आज यह संतुलन बुरी तरह से बिगड़ चुका है और इसके गंभीर परिणाम पूरी दुनिया भुगत रही है। धरती पर अनेक वन्य प्रजातियां या तो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। यही नहीं, हजारों प्रजातियां आज संकटग्रस्त मानी जाती हैं, जिनके अस्तित्व पर हर बीतते वर्ष के साथ खतरा और अधिक बढ़ रहा है। यह संकट केवल जीव-जंतुओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि वनस्पतियों की विविधता भी उसी तीव्र गति से घट रही है। जैव विविधता के महत्व को रेखांकित करने और लोगों को इसके संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 20 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी, जिसे 193 देशों ने समर्थन दिया था। 22 मई 1992 को नैरोबी एक्ट के तहत जैव विविधता पर अभिसमय को स्वीकार किया गया था, इसी कारण 22 मई को यह दिवस तय किया गया। इस वर्ष यह दिवस 'वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना' विषय के अंतर्गत मनाया जा रहा है. जो इस तथ्य को उजागर करता है कि पृथ्वी को बचाने की शुरुआत छोटे-छोटे स्थानीय प्रयासों से ही होती है। आज स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि जंगलों के उजड़ने से हजारों पक्षी और जानवर अपने प्राकृतिक आवास से वंचित हो गए हैं। पक्षियों की वे प्रजातियां, जो किसानों के हित में कीट नियंत्रण का काम करती थी, जैसे गिद्ध, कौए, चील, बाज, तीतर, बटेर, मोर आदि, अब संकटग्रस्त हो चुकी हैं। यह केवल जैव विविधता का नुकसान नहीं बल्कि कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरे की घंटी है। ऐसे पक्षी खेतों में कीटों का प्राकृतिक नियंत्रण करते थे लेकिन इनके लुप्त होने से अब कृत्रिम कीटनाशकों की निर्भरता बढ़ रही है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए घातक है। पर्यावरणीय असंतुलन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग और लगातार बढ़ती आबादी जैव विविधता संकट के प्रमुख कारक हैं। एक ओर जहां जंगलों की अंधाधुंध कटाई के चलते पशु-पक्षियों के प्राकृतिक आवास खत्म हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पेड़-पौधों की दुर्लभ प्रजातियां भी मानव गतिविधियों के कारण धीरे-धीरे मिट रही हैं। यही कारण है कि जैव विविधता का संरक्षण आज केवल पर्यावरणविदों का मुद्दा नहीं बल्कि यह पूरी मानव जाति के अस्तित्व से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन गया है। वन्यजीव और वनस्पतियां धरती पर जीवन की लंबी विकास यात्रा की अहम कड़ियां हैं। ये सभी प्रजातियां अरबों वर्षों के जैविक और पारिस्थितिक विकास का परिणाम हैं। वन्य जीवन में वे सभी जीव-जंतु और पौधे शामिल होते हैं, जिन्हें मनुष्य द्वारा पाला तो नहीं जाता लेकिन उनका अस्तित्व भी मानवीय गतिविधियों से सीधे तौर पर प्रभावित होता है। जैसे-जैसे जंगल उजड़ते हैं, इन प्रजातियों का जीवन संकटग्रस्त होता जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि मनुष्य ने अपने भौतिक विकास और बढ़ती जनसंख्या के दबाव में इस पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन की अनदेखी की है। यह तथ्य अब वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो चुका है कि जैव विविधता के घटने से पर्यावरण का असंतुलन बढ़ता है और इससे प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, अकाल, सूखा, बाढ़, रोगों का प्रसार जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मेरी पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांसें' में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है कि जैव विविधता में आ रही कमी किस प्रकार हमारे संपूर्ण जीवन और पर्यावरण को अस्थिर बना रही है। यह केवल प्रकृति का संकट नहीं बल्कि यह हमारे भविष्य पर मंडराता हुआ खतरा है। धरती पर हर देश की अपनी विशिष्ट जलवायु और पारिस्थितिक पहचान होती है, जिससे वहां की जैव विविधता भी विशिष्ट होती है लेकिन वनों की कटाई, खनन, शहरीकरण, औद्योगीकरण, रासायनिक खेती, प्लास्टिक प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन जैसे मानवीय कारकों ने इस विविधता को संकट में डाल दिया है। दुर्भाग्य से यह संकट केवल कुछ स्थानीय प्रजातियों तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब यह वैश्विक स्तर पर विनाश की ओर बढ़ रहा है।आज मानव अपने स्वार्थ और भौतिक जीवन के मोह में यह भूल गया है कि जीवन की आधारशिला प्रकृति ही है। वनों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और पारिस्थितिक तंत्र की अनदेखी मानव को उस दिशा में ले जा रही है, जहां जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। यदि समय रहते हमने चेतना नहीं दिखाई तो आने वाले समय में ऐसी कई प्रजातियां होंगी, जो केवल पुस्तकों और संग्रहालयों में ही मिलेंगी। विकास अनिवार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं परंतु वह विकास, जो प्राकृतिक संसाधनों को खत्म करके हासिल हो, वह आत्मघाती है। हमें ऐसा विकास मॉडल अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें प्रकृति के साथ सहअस्तित्व को महत्व दिया जाए। यदि पेड़ कटेंगे, जल स्रोत सूखेंगे, जीव-जंतु लुप्त होंगे और पक्षी गायब होंगे तो यह केवल जैव विविधता की हानि नहीं होगी बल्कि पूरी मानव सभ्यता के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लग जाएगा। अब आवश्यकता इस बात की है कि जैव विविधता के संरक्षण को नीतिगत प्राथमिकता दी जाए। सरकारें यदि वन नीति, जल नीति, कृषि नीति और शहरी विकास नीति में पारिस्थितिक संतुलन को अनिवार्य रूप से शामिल करें तो जैव विविधता का संरक्षण संभव हो सकता है। नागरिकों को भी यह समझना होगा कि यह केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर व्यक्ति का दायित्व है।

आज का इतिहास

नई दिल्ली(वार्ता)। 1915 - प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली ने आस्ट्रिया, हंगरी तथा जर्मनी के खिलाफयुद्ध की घोषणा की। 1936 - लार्ड ब्रेबॉर्न ने बम्बई (अब मुंबई) में ब्रेबॉर्न स्टेडियम की नींव रखी। यह देश का पहला स्टेडियम था। 1960 - चिली के दक्षिणी तट पर आए सबसे बड़े भूकंपों में से एक में 5,700 लोगों की मौत हो गई और इससे समुद्र में उठी उग्र लहरों ने सुदूर प्रशांत इलाकों जैसे जापान और हवाई तक में तबाही मचाई। 1963 - भारत के पहले ग्लाइडर रोहिणी ने उड़ान भरी। 1972 - पाकिस्तान द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता से त्यागपत्र। 1972 - अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड एम निक्सन मास्को पहुंचे। यह एक अमेरिकी राष्ट्रपति की सोवियत संघ की पहली यात्रा थी।1984 - बछेन्द्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 1988 - भारत ने स्वदेश में ही विकसित अन्तरमहाद्वीपीय बालिस्टिक प्रक्षेपास्त्र अग्नि का सफल परीक्षण किया। 1990 - उत्तरी एवं दक्षिणी यमन के विलय के साथ संयुक्त यमन गणराज्य का अभ्युदय।

पाठकों की बात — पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

वो पहाड देख रही हो... एक दिन चलेंगे हम उन पहाड़ों के पार... बस मै और तुम जहाँ समाज का कोई डर नहीं होगा, जहाँ BRICS और G20 का कोई पहरा नहीं होगा.. जहाँ हवाएँ तुम्हारा नाम लेकर बहेंगी, और नदियाँ हमारे ख़ामोश सपनों को गुनगुनाएँगी। एक दिन चलेंगे हम उन पहाड़ों के पार... जहाँ रातें तारों की चादर ओढ़े हमारी बातें करेंगी, जहाँ चाँद भी तुम्हारे चेहरे से रोशन होगा जहाँ Mont Blanc की ठंडी हवाएं होंगी जहाँ बादल हर सुबह हमारी खिड़की पर दस्तक देंगे। किसी दिन चलेंगे उन पहाड़ों के पार बस मै और तुम। **- अंकित उपाध्याय**

चतुर नारि हिय जस मृदु बानी ,मुक्तांगन बहु छन्द भवानी। शुक्र दिवस भू नभ छवि कैसे, मधुर माधुरी स्वर लय जैसे। तानसेन स्वर पिंगल ज्ञानी , विविध भाँति रचना गुण सानी । देखत नयन ह्दय अनुरागा, भाँति भाँति अरविंद तड़ागा। अलंकार रस वरणि न जाई , पाणिनि शोध शब्द प्रभुताई। **- राजकिशोर मिश्र 'राज'**

सुलाते थपक के सुनाते कहानी कहाँ हैं वो राजा कहाँ है वो रानी छतों पे था सोना वो सीना पिरोना किस्से कहानी इक दादी इक नानी फिरकी सा मचलना पतंगों का उड़ना नदारद हुई है वो गुड़िया सयानी सितारे चमकते घनी रात प्यारी सुनना पापा का बचपन दादी की जुबानी बिना डर के दौड़ना और जुगनू पकड़ना भुलाई हिंडोले की रस्सी सुहानी परी सा इतरना फुहारों में भीगना कश्ती कागज़ की हुई है पुरानी। **- ज्योत्सना सक्सेना**

बस यूँ ही दिल से सोसल मिडीया ने सबकी हैसियत बता दी है जो बनते थे धुरन्धर उन्हे धूल मे मिला दी है जिन्हे समझती थी सारी दुनिया नकारा आज उसको उसने सिर पे बीठा ली है।। **- अजयश्री मिश्रा**

कई ख़ुवाब हैं उनके बरक्स कडवी हक़ीक़त है ज़िन्दगी एक राहत है तो जीने में भी बहुत मुसीबत है हम ही सूरत हैं और हम ही हमारे आईने हैं अंदाज़ हमारे हैं और हम ही वक्ती रवायत हैं जला रखा है एक चिराग हमने इस मुसलसल अँधेरे में गिन रहें हैं अपनी धडकनें सामने पड़ी उनकी इजाज़त है। **- रामकिशोर उपाध्याय**

धीरे-धीरे इंसान को ख़ुद से दूर कर देती है।÷ कभी-कभी इंसान दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से हारने लगता है। हर वक़्त सोचते रहना धीरे-धीरे सुकून, खुशी और ख़ुद से जुड़ाव छीन लेता है। Overthinking बाहर से नहीं दिखती लेकिन अंदर से इंसान को पूरी तरह थका देती है। **- रेनु सिंघल**

बादल जब गरजते हैं, मन भी कहीं भीतर काँप उठता है। बिजली जब चमकती है, कुछ पुरानी यादें भी उजालों में आ जाती हैं। घटाएँ जैसे आकाश में घुमड़ती हैं, वैसे ही मन में अनकहे भाव उमड़ते रहते हैं। पर फर्क इतना है आकाश के बादल खुलकर बरस जाते हैं, मन के बादल बरसने के लिए एक अपना-सा कंधा तलाशते हैं और फिर चुपचाप भीग जाता है मन। **- सीमा नागर तुली**

राशि फल

पं. देवव्रत शर्मा

मेष : आज का दिन पुराने रिश्तों की मिठास और नई खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है। पुराने दोस्तों से मुलाकात यादों का खजाना खोल देगी। घर में नए मेहमान के आने से खुशियों की रौनक बढ़ेगी।

वृषः आज सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी होगी, क्योंकि मौसम का असर आपको कमजोर महसूस करा सकता है। बिजनेस में आपकी लंबी योजनाएँ धीरे-धीरे सफलता की राह पकड़ेंगी।

मिथुनः आज प्रॉपर्टी और निवेश के मामलों में किस्मत आपका साथ दे सकती है। नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार लाभकारी साबित होगा। हालांकि घमंड या जल्दबाज़ी किसी काम को अधूरा छोड़ सकती है।

कर्कः आज नई संभावनाएं और अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। नई नौकरी का ऑफर उत्साह बढ़ा सकता है। सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता लोगों को प्रभावित करेगी।

सिंहः आज सोच-समझकर कदम बढ़ाना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नए काम में जल्दबाज़ी करने से बचें और हर व्यक्ति को पहचानकर ही भरोसा करें। नौकरी बदलने का विचार सकारात्मक परिणाम दे सकता है।

कन्याः आज का दिन आपके लिए नई पहचान और नई उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। आपके काम की तारीफहोगी और नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा।

तुलाः आज आलस्य आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। कामों को टालने की आदत आगे परेशानी बढ़ा सकती है। जीवनसाथी के साथ शॉपिंग या घूमने का प्लान मन को खुश करेगा, लेकिन खर्च सोच-समझकर करें।

वृश्चिकः आज सफलता की राह पर आपके कदम तेजी से बढ़ सकते हैं। दोस्तों के साथ बिताया गया समय तनाव कम करेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को चुनौतियाँ मिलेंगी, लेकिन धैर्य से आगे बढ़ना होगा।

धनुः आज का दिन खुशी और मौज-मस्ती से भरा रह सकता है। माता-पिता के आशीर्वाद से रुका हुआ काम पूरा होने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में लापरवाही आपके साथियों को नाराज कर सकती है, इसलिए फोकस बनाए रखें।

मकरः आज धन और समृद्धि में बढ़ोतरी के संकेत हैं। बिजनेस की योजनाएँ उम्मीद से बेहतर परिणाम दे सकती हैं।

कुंभः आज मेहनत और नए आइडिया आपकी सफलता की चाबी बन सकते हैं। बिजनेस में नई सोच आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। अपनों के साथ घूमने का प्लान भी बन सकता है।

मीनः आज पारिवारिक उलझनें आपके मन को थोड़ा परेशान कर सकती हैं। भाई-बहनों के बीच छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है। संतान का व्यवहार भी चिंता का कारण बनेगा।

QUIZ TIME

Ramaquiz

1) पश्तून जातीय समूह मुख्य रूप से किन देशों में पाया जाता है?

2) व्हेन-लिस्टेड प्लेटफॉर्म किस संस्थान की पहल है?

3) हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किस शहर में किया?

4) लीडरशिप समिट 2024 की मेज़बानी किस संस्थान ने की?

5) लैटिन अमेरिका में किस देश ने कानून बनाकर इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला पहला देश बन गया है?

उत्तरमाला- (1) अफगानिस्तान और पाकिस्तान (2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (3) बिलासपुर (4) आईआईटी गुवाहाटी (5) उरुग्वे

पहेली

शब्द सामर्थ्य - 045

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 044 का हल

इंद्रावती पार कर पहुँची स्वास्थ्य टीम, 642 ग्रामीणों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

■ 'अत्यंत दुर्गम और अंदरूनी गाँवों में जगी बेहतर स्वास्थ्य की नई उम्मीद'

बीजापुर/नवप्रदेश। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड के अत्यंत दुर्गम और अंदरूनी क्षेत्र नूगुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कठिन परिस्थितियों के बीच पहुँचकर ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई। कलेक्टर विश्वदीप के मार्गदर्शन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में आयोजित यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग शिविर ने दूरस्थ गाँवों में स्वास्थ्य जागरूकता की नई उम्मीद जगाई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नूगुर, हिंगमेटा और हुर्रागवाली गाँवों में शिविर लगाकर कुल 642 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान मरीजों को आवश्यक दवाइयाँ निःशुल्क दी गई और गंभीर मरीजों को आगे के उपचार के लिए उच्च स्वास्थ्य केंद्रों में जाने की सलाह दी गई।

उप स्वास्थ्य केंद्र, नूगुर विकासखंड मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए स्वास्थ्य टीम को करीब 2 किलोमीटर चौड़ी इंद्रावती नदी को पार करना पड़ता है। लंबे समय तक यह इलाका नक्सल प्रभाव और दुर्गम परिस्थितियों के कारण सरकारी योजनाओं की पहुँच से दूर रहा, लेकिन अब शासन की योजनाएँ धीरे-धीरे इन गाँवों तक पहुँच रही हैं। स्वास्थ्य टीम ने कठिन रास्तों और भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद ग्रामीणों तक पहुँचकर यह साबित कर दिया है कि शासन की स्वास्थ्य सेवाएँ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए लगातार ईमानदार प्रयास किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान तीन प्रमुख गाँवों में कुल 642 ग्रामीणों की जाँच की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ग्राम नूगुर (कुल 207 मरीज) इसमें 75 एनसीडी स्क्रीनिंग, 03 बुखार, 05 खुजली, 01 गर्भवती महिला की जाँच तथा अन्य 123 मरीजों का सामान्य परीक्षण शामिल है। ग्राम हिंगमेटा (कुल 125 मरीज) यहाँ 42 एनसीडी स्क्रीनिंग, 02 खुजली सहित 81 अन्य मरीजों की जाँच की गई।

'स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति बढ़ा ग्रामीणों का भरोसा'

स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि पहले ग्रामीण स्वास्थ्य जाँच और बच्चों के टीकाकरण से बचते थे, लेकिन अब जमीनी स्तर पर स्थिति बदल रही है। ग्रामीण अब स्वयं आगे आकर स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं और बच्चों का नियमित टीकाकरण भी करवा रहे हैं। इससे गाँवों में स्वास्थ्य के प्रति न केवल जागरूकता बढ़ी है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है।

न्यूज गैलरी

अस्वच्छ व्यवसाय छात्रवृत्ति हेतु प्रमाण पत्र अब जारी होंगे ऑनलाइन

रायपुर/नवप्रदेश। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा केंद्र प्रवर्तित अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। योजना के अंतर्गत कक्षा पहली से दसवीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी जाने वाली अस्वच्छ व्यवसाय छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इस नई डिजिटल व्यवस्था से पात्र विद्यार्थियों को भटकना नहीं पड़ेगा और छात्रवृत्ति का लाभ अधिक पारदर्शी व सरल प्रक्रिया से सीधे मिल सकेगा। शिक्षा विभाग के अनुरोध पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार स्तर से ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) द्वारा इस ऑनलाइन प्रणाली का सॉफ्टवेयर तैयार कर इसे सफलतापूर्वक लाइव भी कर दिया गया है। अब छात्रवृत्ति के लिए प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को अन्य नागरिक सेवाओं की तरह ही सुगम बना दिया गया है। जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र की तर्ज पर अब तहसील कार्यालयों और अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों में स्थित लोक सेवा केंद्रों में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए आवेदन के साथ 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रारूप में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच अथवा नगरीय निकाय के पार्षद एवं क्षेत्र के पटवारी के हस्ताक्षर युक्त अनुशंसा पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रशासन द्वारा सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों तथा प्रधानपाठकों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

घरजियाबथान शिविर में 80 पेंशन आवेदनों का मौके पर ही निराकरण

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजित सुशासन तिहार 2026÷ के अंतर्गत जशपुर जिले में जनसमस्या निवारण शिविरों के माध्यम से आमजन को त्वरित राहत प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में जनपद पंचायत पत्थलगांव अंतर्गत ग्राम पंचायत घरजियाबथान में आयोजित शिविर में समाज कल्याण विभाग को प्राप्त 80 पेंशन आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित करने की प्रक्रिया तत्काल सुनिश्चित की गई। शिविर में दिव्यांग हितग्राही मोहित राम कोरवा को सहायक उपकरण के रूप में बैटरी चालित ट्राइसिकल प्रदान की गई। ट्राइसिकल मिलने से उन्हें दैनिक गतिविधियों में सुविधा मिलेगी तथा आत्मनिर्भर जीवन जीने में सहायता प्राप्त होगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक पत्थलगांव गोमती साय उपस्थित रहीं। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य सुरुचि पैंकरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। विधायक गोमती साय ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की योजनाएं सीधे गांव-गांव तक पहुंच रही हैं और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और ऐसे शिविर इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शिविर के दौरान ग्रामीणों को "नशामुक्त भारत अभियान" के तहत शपथ भी दिलाई गई। सभी उपस्थित लोगों ने नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। सुशासन तिहार के तहत आयोजित यह शिविर न केवल समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बना, बल्कि सामाजिक जागरूकता और जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का भी सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया।

गेड़ई शिविर में हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में सुशासन तिहार 2026 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी क्रम में मनोरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रेमने के ग्राम गेड़ई में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। शिविर में कुल 165 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को आवास की चाबी प्रदान की गई। वहीं कृषि विभाग द्वारा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। खाद्य विभाग द्वारा नए राशन कार्ड प्रदान किए गए तथा राजस्व विभाग द्वारा हितग्राहियों को बी-1 दस्तावेज वितरित किए गए। इसके अलावा वन विभाग द्वारा पौधों का वितरण तथा उद्यानिकी विभाग द्वारा फलदार पौधों का वितरण किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित किया गया।

प्रदेश में नीली क्रांति की ओर अग्रसर

■ गिफ्ट तिलापिया और आधुनिक तकनीकों से बदल रही मछुआरों की तकदीर': मंत्री नेताम

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ की समृद्ध जल-संरचना और अनुकूल जलवायु के चलते मछली पालन अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों और मछुआरा हितैषी योजनाओं के कारण छत्तीसगढ़ आज मत्स्य बीज उत्पादन में न केवल पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है, बल्कि देश में अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में छठवें स्थान पर है, जहाँ सालाना 9.59 लाख मीट्रिक टन मछली का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। मतस्य पालन मंत्री राम विचार नेताम आज राजधानी रायपुर में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित को संबोधित कर रहे थे। मंत्री नेताम ने बताया कि प्रदेश में कुल उपलब्ध 2.081 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में से 96.25 प्रतिशत क्षेत्र को मछली पालन के अंतर्गत विकसित कर लिया गया है। इसके माध्यम से राज्य के 2.25 लाख से अधिक मछुआरों को स्वरोजगार के स्थायी साधन मिले हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के अंतिम व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मछली पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने से आज हमारे मत्स्य पालकों को बिजली दरों में छूट, ब्याज मुक्त ऋण और पानी की दरों में बड़ी राहत मिल रही है। मंत्री नेताम ने कहा कि मत्स्य किसानों के आय में वृद्धि करने विभाग अब आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों जैसे केज कल्चर, आर.ए.एस. और बायोफ्लॉक को बढ़ावा दे रही है। ''गिफ्ट तिलापिया'' के लिए रायपुर और कांकेर में विशेष क्लस्टर विकसित कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य वर्ष 2028 तक तिलापिया उत्पादन को 30,000 मीट्रिक टन तक पहुँचाना है, जिससे हमारे राज्य को सालाना 90 से 100 करोड़ रुपये का विदेशी निर्यात राजस्व प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ का पानी और यहाँ के मछुआरों की मेहनत मिलकर राज्य में नीली क्रांति का नया इतिहास लिख रहे हैं। मत्स्य संचालक नारायण सिंह नाग ने बताया कि उत्कृष्ट गुणवत्ता का मत्स्य बीज तैयार करने के लिए राज्य में मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 123 सर्कुलर हेचरी, 102 मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, 3,698 संवर्धन पोखर, 01 पंगेशियस हेचरी (धमतरी), 07 मांगुर हेचरी (बालोद, कबीरधाम, बिलासपुर, कोरबा, कोण्डागांव एवं महासमुंद), 02 मोनोसेक्स तिलापिया हेचरी (रायपुर एवं बलौदाबाजार), संचालित हो रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 606 करोड़ से अधिक मत्स्य बीज का उत्पादन हो रहा है। छत्तीसगढ़ न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरल और गोवा जैसे राज्यों को भी उच्च गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज की आपूर्ति कर रहा है।

अरुण साव प्रथम तेलीन सत्ती माता महोत्सव में हुए शामिल

रायपुर/नवप्रदेश। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कोण्डागांव जिले के केशकाल में साहू संघ बस्तर संभाग द्वारा आयोजित प्रथम तेलीन सत्ती माता महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप और भोजराज, विधायक नीलकंठ टेकाम और आशाराम नेताम सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं समाज के प्रमुखजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री साव ने तेलीन सत्ती माता को नमन करते हुए महोत्सव के प्रथम आयोजन पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि केशकाल घाटी से गुजरने वाले यात्री तेलीन सत्ती माता का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिससे उनकी यात्रा सफल और मंगलमय होती है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में यह महोत्सव और अधिक भव्य स्वरूप में आयोजित होगा तथा सभी के सहयोग से इसका गौरव लगातार बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के गौरव हैं और उनके नेतृत्व में गांव, गरीब एवं किसानों के कल्याण के लिए अनेक जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि साहू समाज अन्य समाजों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ महतारी के गौरव को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सुशासन तिहार: नवविवाहिता को मिला राशन कार्ड, समस्याओं का हुआ निराकरण

■ खाद्य सुरक्षा की चिंता हुई दूर, हितग्राही ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित सुशासन तिहार 2026 आम नागरिकों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन रहा है। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के ग्राम मुड़गांव में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में नवविवाहिता सेजल सिंह को नया राशन कार्ड प्रदान किया गया, जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी। सेजल सिंह ने बताया कि हाल ही में विवाह होने के कारण उनका नाम किसी राशन कार्ड में दर्ज नहीं था। इसके चलते उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले खाद्यान्न का लाभ नहीं मिल पा रहा था। समस्या के समाधान के लिए उन्होंने सुशासन तिहार के दौरान खाद्य विभाग में नए राशन कार्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जनसमस्या निवारण शिविर में अधिकारियों ने उनके आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नया राशन कार्ड जारी कर उन्हें मौके पर ही सौंप दिया। राशन कार्ड प्राप्त होने पर सेजल सिंह ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें हर महीने बिना किसी परेशानी के राशन मिल सकेगा। सेजल सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से गांव में ही उनकी समस्या का समाधान हो गया और उन्हें शासकीय योजना का लाभ सहजता से प्राप्त हुआ।

संघर्ष से आत्मनिर्भरता तक उषा कुंजाम बनीं ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा

■ 3.90 लाख रूपए के लोन से स्थापित की राइस मिल और टोरा मिल प्रसंस्करण इकाई

रायपुर/नवप्रदेश। अपनी कड़ी मेहनत और अटूट आत्मविश्वास के दम पर बीजापुर जिले के सुदूर आदिवासी गांव मुरदोण्डा (तहसील- उसूर) की रहने वाली 38 वर्षीय उषा कुंजाम ने संघर्ष भरे जीवन को सफलता की नई पहचान दी है। आज वे न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अपने क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बन चुकी हैं।

उषा कुंजाम लंबे समय तक बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझती रहीं। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच आय का कोई स्थायी साधन नहीं था और सुदूर वनांचल क्षेत्र होने के कारण रोजगार के अवसर भी बेहद सीमित थे। इसी बीच उन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, बीजापुर के माध्यम से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना की जानकारी मिली। विभाग के मार्गदर्शन में उन्होंने ऋण के लिए आवेदन किया और वित्तीय वर्ष 2025-26 में आईसीआईसीआई बैंक की बीजापुर शाखा से उन्हें 3 लाख 90 हजार 400 रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ। इस आर्थिक सहायता से उषा कुंजाम ने अपने गांव में ही राइस मिल और टोरा मिल (महुआ बीज) प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की। इस पहल से स्थानीय स्तर पर बड़ा बदलाव आया है। टोरा तेल का वैल्यू एडिशन- पहले क्षेत्र में टोरा सिर्फ 8 से 10 रुपये प्रति किलो के मान से कौड़ियों के दाम बिकता था। अब उषा इससे तेल निकालकर आकर्षक पैकेजिंग करती हैं और बाजार में 100 प्रति लीटर की दर से बेच रही हैं।

रानीसागर बोटिंग परियोजना की सामग्री छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की सुरक्षा और संरक्षण में

रायपुर/नवप्रदेश। राजनांदगांव जिले में पर्यटन संवर्धन हेतु वर्ष 2012-13 में मोहारा के लिए नौकाविहार योजना स्वीकृत की गई थी, जिसे बाद में तकनीकी कारणों से रानीसागर तालाब में स्थानांतरित किया गया। इस परियोजना के लिए लगभग 72.34 लाख रुपए की लागत से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, मोटर बोट और अन्य आवश्यक सामग्री क्रय की गई थी। रानीसागर बोटिंग परियोजना का लोकार्पण वर्ष 2015 में किया गया था और निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एक निजी एजेंसी द्वारा जनवरी 2015 से अगले तीन वर्षों तक इसका सफल संचालन भी किया गया। इस अवधि का पूरा प्रशासनिक और आय संबंधी रिकॉर्ड विभाग के पास सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2017 के बाद आर्थिक व्यवहार्यता की कमी और आमजन की रुचि घटने के कारण बोटिंग का संचालन प्रभावित हुआ। रखरखाव और सुरक्षा की दृष्टि से वर्ष 2019 में समस्त सामग्री को विधिवत प्रक्रिया के तहत विभागीय संरक्षण में ले लिया गया था।

पण्डरीडांड की प्रभावती को मिली आत्मनिर्भरता की नई राह

■ बकरी पालन के लिए मिली आर्थिक सहायता, अब स्वरोजगार से मजबूत होगी आजीविका

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित सुशासन तिहार 2026 ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के साथ-साथ स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा दे रहा है। शासन की योजनाओं का लाभ अब सीधे गांवों तक पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिल रहा है। इसी क्रम में सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के ग्राम पण्डरीडांड निवासी प्रभावती को सुशासन तिहार के तहत पशुधन विकास विभाग द्वारा बकरी पालन के लिए 4 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। प्रभावती ने बताया कि इस सहायता राशि से वे बकरी खरीदकर आजीविका गतिविधि शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि इससे परिवार की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अब गांव में ही समस्याओं का समाधान हो रहा है और योजनाओं का लाभ लेने के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ता। प्रशासन स्वयं ग्रामीणों तक पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहा है और त्वरित समाधान कर रहा है। प्रभावती ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। सुशासन तिहार के माध्यम से जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन कर प्रशासन ग्रामीणों तक सीधे पहुंच रहा है। इन शिविरों में विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

नए तकनीकी उपकरणों, डिजिटलीकरण और सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करने दिए निर्देश

लोक निर्माण विभाग के कार्यों में जनहित और तकनीकी दक्षता पर जोर

■ निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और तेजी सुनिश्चित करने के निर्देश'

रायपुर/नवप्रदेश। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर में पीडब्ल्यूडी मुख्यालय शिनर्माण भवनश् में आयोजित बैठक में विभाग के कार्यों में जनहित और तकनीकी दक्षता पर जोर दिया। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और तेजी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिक दक्षता और ज्यादा गति से काम करने नए तकनीकी उपकरणों, डिजिटलीकरण और सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करने को कहा।

विभागीय सचिव बंसल ने बैठक में सभी टेंडर प्रक्रियाओं को पूरी पारदर्शिता और समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और तेजी दोनों सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इनमें कोई कोताही नहीं बरती जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों की नियमित और कड़ी मॉनिटरिंग के साथ ही जनहित एवं तकनीकी दक्षता का भी विशेष ध्यान रखने को कहा।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि आधुनिक जियो-इन्फॉर्मेटिक्स तकनीक के माध्यम से निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग, मैपिंग और प्रोजेक्ट प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने विभागीय सचिव को टेंडर प्रक्रिया के तहत कार्य आबंटन, निर्माण कार्यों की बिलिंग प्रक्रिया एवं भुगतान प्रणाली के बारे में भी बताया।

बैठक में प्रदेशभर में चल रहे निर्माण कार्यों, टेंडर प्रक्रिया की प्रगति तथा आगामी परियोजनाओं की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में अधिकारियों और ठेकेदारों के कार्य निष्पादन, विभिन्न तकनीकी प्रक्रियाओं तथा भुगतान की समयबद्ध व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी व्यवस्थाओं, गुणवत्ता नियंत्रण और ठेकेदारों की कार्यप्रणाली के बारे में भी पूछा। बंसल ने रायपुर में कचना रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य की भी जानकारी ली।

न्यूज गैलरी

शहीद रामकुमार यादव की नवमी पुण्यतिथि मनाई

कांकेर / नवप्रदेश। नगर में झुनियापारा कांकेर मे स्थित रामकुमार यादव जी के प्रतिमा स्थल पर आज कांकेर विधानसभा के विधायक आदरणीय आशाराम नेताम जी, नगरपालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक व शहीद परिवार एवं यादव समाज के द्वारा दीप प्रज्वलित कर पुष्प माला अर्पित कर नवमी पुण्यतिथि मनाई गई। प्रतिमा स्थल मे श्रध्दांजली अर्पित कर शहीद रामकुमार शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मे शहीद परिवार का सम्मान व पुष्प अर्पित कर शहीद जवान को याद किया गया इस अवसर पर यादव समाज के जिलाध्यक्ष गिरधर यादव समाज 45टीने बताया कि शहीद रामकुमार यादव चोलनार दन्तेवाड़ा जिले मे एक नक्सली हमले मे 20 मई 2018 में शहीद हो गए थे तब यादव समाज ने कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नाम शहीद रामकुमार यादव के नाम से हो इसकी मांग कि थी और लगातार प्रयास के बाद शासन ने शहीद रामकुमार यादव के नाम से इस स्कूल का नाम परिवर्तित कर रखा ।

स्कूल मे यादव समाज बीच-बीच मे कई कई तरह के सकारात्मक आयोजन करते रहता है स्कुल के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी बच्चों को सम्मानित करता है और उनके उत्साहवर्धन के लिए प्रयासरत रहता है।इस अवसर पर शहीद रामकुमार यादव शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कि प्राचार्या व बी. आर. सी. नवनीत पटेल व्दारा शहीद रामकुमार यादव जी कि माता व उनके परिवार को सम्मानित किया गया इस अवसर पर स्कुल के स्टाफ शहीद परिवार से रामस्वरूप यादव, वंशीका यादव वैभव यादव व यादव समाज के राजेश यादव,? धनेश यादव, हेमन्त यादव, कमल यादव, विजय यादव, बल्लु यादव, तीजुराम यादव, चिन्टू यादव, कमल यादव, जागेश्वर यादव, योगेश यादव व समाजिक जन उपस्थित थे।

उप जेल बीजापुर के आसपास 500 मीटर क्षेत्र नो फ्लाई जोन घोषित

बीजापुर / नवप्रदेश। जिला प्रशासन ने उप जेल बीजापुर की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जेल परिसर के ऊपर एवं आसपास 500 मीटर की परिधि को नो फ्लाई जोन घोषित किया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विश्वदीप ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत आदेश जारी किया है।कार्यालय जेल अधीक्षक, उप जेल बीजापुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा 04 मई 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में प्रदेश की सभी जेलों के आसपास नो फ्लाई जोन घोषित करने के निर्देश दिए गए थे। जारी आदेश के तहत उप जेल बीजापुर के ऊपर एवं आसपास ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट विमान तथा अन्य हल्के हवाई वाहनों के उड़ान संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा एजेंसी को प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हवाई वाहन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जेल की सुरक्षा, कैदियों की निगरानी तथा हवाई मार्ग से किसी भी प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति रोकने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। पुलिस अधीक्षक बीजापुर, सहायक जेल अधीक्षक बीजापुर एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

बीजापुर में विकसित कृषि संकल्प अभियान का सफल समापन

बीजापुर / नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 05 मई से 20 मई 2026 तक संचालित ÷विकसित कृषि संकल्प अभियान÷ का सफल समापन बीजापुर जिले के विभिन्न विकासखंडों में किया गया। अभियान के अंतिम दिन विभिन्न वैज्ञानिक दलों ने किसानों के बीच पहुंचकर आधुनिक एवं उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी साझा की। यह अभियान निदेशक विस्तार सेवाएं, इं.गां.कृ.वि. रायपुर के निर्देशानुसार कृषि विज्ञान केंद्र बीजापुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख श्री अरुण सकनी के मार्गदर्शन में संचालित किया गया। अभियान के सुचारु संचालन हेतु जिले के सभी विकासखंडों के लिए चार अलग-अलग वैज्ञानिक दलों का गठन किया गया था। उसूर विकासखंड के लिए डॉ. शमशेर आलम, भैरमगढ़ के लिए डॉ. मिथलेश कुमार एवं डॉ. राजकमल पटेल, भोपालपटनम के लिए डॉ. भूपेंद्र कुमार एवं डॉ. दिनेश मारापी तथा बीजापुर विकासखंड के लिए डॉ. सुनीता पटेल एवं श्री अरविंद आयाम को दल प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।अभियान के दौरान सभी दलों ने प्रतिदिन दो चयनित ग्रामों में पहुंचकर किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं, नवीन कृषि तकनीकों एवं आगामी खरीफ फसलों की तैयारी संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कीं। किसानों को बीज उपचार, मृदा परीक्षण, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, जैविक उर्वरकों के उपयोग, ग्रीष्मकालीन जुताई, रोग एवं कीटों के जैविक प्रबंधन, पौध संरक्षण, बागवानी फसलों की उन्नत खेती, आधुनिक कृषि यंत्रों एवं ड्रोन तकनीक के उपयोग, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, मशरूम उत्पादन तथा मधुमक्खी पालन जैसे विषयों पर विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण दिया गया।

मिशनरी हस्तक्षेप के विरोध में ग्रामीण लामबंद, चित्रकोट में अंतिम संस्कार को लेकर दिनभर तनाव

■ सार्वजनिक मुक्तिधाम में दफनाने के प्रयास पर भड़का विवाद

जगदलपुर/नवप्रदेश। बस्तर संभाग के लोहंडीगुड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चित्रकोट के पदरगुड़ापारा में धर्मांतरित व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर बुधवार को दिनभर तनाव की स्थिति बनी रही। गांव के सार्वजनिक मुक्तिधाम में शव दफनाने के प्रयास का ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा और देर शाम परिजनों की सहमति के बाद शव को मसीही कब्रिस्तान में दफनाया गया।

ग्रामीणों का आरोप था कि गांव की पारंपरिक व्यवस्था और सामाजिक मान्यताओं की अनदेखी करते हुए सार्वजनिक मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार कराने का प्रयास किया जा रहा था। विरोध के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए,जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया। सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। ग्रामीणों तथा पारंपरिक व्यवस्था से जुड़े

माटी पुजारी, नाईक, सिरहा-गुनिया सहित अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि गांव में मिशनरी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इससे सामाजिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। पूर्व सरपंच रैतूराम कश्यप सहित ग्रामीणों ने कहा कि गांव की परंपराओं और सामाजिक नियमों को किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।

मामले में दिनभर चली चर्चा और विरोध के बाद मृतक के छोटे भाई पुष्पेंद्र बघेल ने लोहंडीगुड़ा तहसीलदार को लिखित आवेदन सौंपकर शव को निकटस्थ मसीही कब्रिस्तान में दफनाने पर सहमति जताई। इसके बाद प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कराई गई और स्थिति सामान्य हुई।

अंतिम संस्कार विवाद के दौरान माहरा समाज चित्रकोट परगना के अजय बघेल,बजरंग दल विभाग संयोजक सिकंदर कश्यप, विहिप विभाग सेवा प्रमुख अनिल अग्रवाल,बजरंग दल जिला संयोजक विष्णु ठाकुर,सह संयोजक योगेश रैली,पूर्व जिला संयोजक मुन्ना बजरंगी,विवेक शुक्ला,शिवा नाग,इन्द्र टेमरे, पवन नामदेव,लोकेंद्रनाथ नाग सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

परंपरा और धर्मांतरण को लेकर बढ़ रही संवेदनशीलता

चित्रकोट क्षेत्र में अंतिम संस्कार को लेकर उत्पन्न विवाद ने ग्रामीण अंचलों में परंपरा, धार्मिक पहचान और सामाजिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को फिर चर्चा में ला दिया है। सार्वजनिक मुक्तिधाम के उपयोग को लेकर ग्रामीणों ने इसे सामाजिक परंपराओं से जुड़ा विषय बताते हुए विरोध दर्ज कराया।

साल जंगलों में बिखेर रही 'नवरंग' की रंगत

■ तितिर और बिरिंगपाल के जंगलों में इंडियन पित्ता की मधुर सिटी से गूंज रहा वनांचल

■ सुबह-शाम की सिटी बन रही आकर्षण का केंद्र

जंगलों की सुंदरता बढ़ा रहा 'नवरंग'

इंडियन पित्ता अपनी रंगीन बनावट और मधुर आवाज के कारण जंगलों की जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तितिर और बिरिंगपाल के साल जंगलों में इसकी बढ़ती मौजूदगी प्रकृति प्रेमियों के लिए सुखद संकेत मानी जा रही है। पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार यह पक्षी स्वच्छ और संतुलित वन पर्यावरण का संकेतक भी है। गर्मी के मौसम में इसकी सक्रियता बढ़ जाती है और सुबह-शाम इसकी सिटी जंगलों के वातावरण को और अधिक मनमोहक बना देती है।

जगदलपुर/नवप्रदेश। बस्तर के तितिर गांव और बिरिंगपाल के साल जंगल इन दिनों बेहद रंग-बिरंगी चिड़िया 'इंडियन पित्ता' यानी 'नवरंग' की मौजूदगी से जीवंत हो उठे हैं। अपने आकर्षक नौ रंगों और मीठी सुरीली आवाज के कारण यह पक्षी इन दिनों पक्षी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों का खास आकर्षण बना हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली यह छोटी किंतु मजबूत चिड़िया अपने अनोखे रंगों और व्यवहार के लिए जानी जाती है।

शासकीय काकतीय महाविद्यालय के प्रो सुशील दत्ता इसके शरीर और पंखों में नौ अलग-अलग रंग दिखाई देते हैं। सिर पर भूरा और काला रंग,गले में सफेद आभा,पेट और निचले हिस्से में चमकीला लाल रंग,नीले पंख तथा हरी पीठ इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं। लगभग 19 सेंटीमीटर लंबी यह चिड़िया देखने में छोटी जरूर होती है, लेकिन इसकी उपस्थिति जंगलों में अलग ही पहचान बना देती है।

प्रो दत्ता ने कहा इंडियन पित्ता को 'सिक्स ओ क्लॉक बर्ड' भी कहा जाता है, क्योंकि यह सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे नियमित रूप से साफ सिटी जैसी आवाज निकालती है। आवाज निकालते समय यह अपना सिर और गर्दन पीछे की ओर झुकाकर चोंच ऊपर उठाती है, जिससे इसकी दो स्वर वाली विशेष सिटी जंगलों में गूंज उठती है।

प्रो दत्ता ने बताया इन दिनों गर्मी से बरसात के बीच यह पक्षी घोंसला बनाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। घने जंगलों,झाड़ियों और पतझड़ी वनों को पसंद करने वाली यह चिड़िया दिनभर जमीन पर गिरी सूखी पत्तियों के बीच भोजन तलाशती है। जमीन के कीड़े,उनके लार्वा और केंचुए इसका मुख्य भोजन हैं। सर्दियों में यह दक्षिण भारत और श्रीलंका की ओर प्रवास कर जाती है,इसलिए बस्तर क्षेत्र में इसे ग्रीष्मकालीन मेहमान माना जाता है। समूचे व्यवहार और घोंसला निर्माण की दुर्लभ गतिविधियों को प्रोफेसर दत्ता ने अपने कैमरे में कैद किया है। खास बात यह है कि नर और मादा दोनों एक समान दिखाई देते हैं तथा दोनों मिलकर घोंसला बनाने में सहयोग करते हैं।

जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने रथ रवाना

कांकेर / नवप्रदेश। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी श्री जितेन्द्र कुर्रे के मार्गदर्शन में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण कार्य के लिए जिले में जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले की आम जनता को जनगणना के महत्व एवं प्रक्रिया की जानकारी देने के उद्देश्य से विगत दिनों जनगणना जागरूकता रथ को रवाना किया गया।

जनगणना रथ के माध्यम से नागरिकों को जनगणना 2027 के प्रथम चरण में होने वाले मकान गणना एवं मकान सूचीकरण से संबंधित जानकारी दी जा रही है। रथ द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं नगरीय क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को जनगणना कार्य में सहयोग करने तथा सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे जनगणना कार्य में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए गणना कर्मियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि जनगणना कार्य सुचारू एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

पशुपालन से बदली प्यारेलाल यादव की जिंदगी

बीजापुर / नवप्रदेश। पशुपालन एवं डेयरी व्यवसाय ग्रामीण परिवारों के लिए आय का बेहतर माध्यम बनता जा रहा है। शासन की योजनाओं का लाभ लेकर जिले के ग्राम मंगापेठा निवासी श्री प्यारेलाल यादव ने भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। श्री प्यारेलाल यादव पूर्व में कृषि कार्य कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे, लेकिन सीमित आय के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके बाद उन्होंने पशुधन विकास विभाग की राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना का लाभ लेकर वर्ष 2022-23 में दो गायों के पालन से डेयरी व्यवसाय की शुरुआत की। दूध उत्पादन बढ़ने के साथ उनकी आय में लगातार वृद्धि हुई। व्यवसाय से होने वाली आय को बचत कर उन्होंने अतिरिक्त दो गायें खरीदीं। वर्तमान में उनके पास कुल 8 गौवशीय पशु हैं, इससे उन्हें सालाना लगभग 1 लाख 50 हजार रुपये की शुद्ध आय प्राप्त हो रही है।

विकास के साथ बस्तर के संसाधनों का स्थानीय लोगों को लाभ मिले : कांग्रेस

कांकेर / नवप्रदेश। राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय कांकेर मै बस्तर क्षेत्र के विकास, आदिवासी अधिकारों, जल-जंगल-जमीन की सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार तथा उद्योगों से जुड़े मुद्दों को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान बस्तर की जनता की ओर से केंद्र एवं राज्य सरकार के समक्ष कई गंभीर सवाल और मांगें रखी गई।

पत्रकार वार्ता में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव जनक नन्दन कश्यप ने कहा कि बस्तर के लोग विकास चाहते हैं, लेकिन ऐसा विकास जो आदिवासियों की संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों और अधिकारों की रक्षा करते हुए हो। उन्होंने कहा कि लंबे समय से बस्तर के नागरिक विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। पत्रवार्ता के दौरान मुख्य रूप से एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण एनएमडीसी मुख्यालय को जगदलपुर लाने 2000 स्कूलों के बंद होने, आदिवासियों की जमीनों की सुरक्षा तथा खनिज संसाधनों के बाहरी कंपनियों को दिए जाने जैसे मुद्दे उठाए गए। वक्ताओं ने सवाल किया कि आखिर बस्तर के संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है।

महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार

कांकेर / नवप्रदेश। महंगाई के विरोध में कांग्रेसजनों ने पुराने बस स्टैंड पर प्रदर्शन करते हुए महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नरेश ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार के गलत नितीयों के कारण से देश व प्रदेश में पेट्रोल डीजल, खाद्य सामाग्री एंव सराफा (सोना, चांदी) की कितमों में लगातार बढोतरी से आम जनता पूरी तरह से प्रभावित हो रहे है। जिसके कारण मध्यम वर्ग किसान, मजदूर, व्यापारी तथा आम नागरिकों को आर्थिक संकटो का सामना करना पड़ रहा हैं और बढ़ती महंगाई के कारण से जनता में व्यापक आक्रोष व्याप्त है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 20 मई शाम 05:30 बजे पुराना बस स्टैण्ड कांकेर में मंहगाई के मुद्दे पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कांकेर शहर / ग्रामीण द्वारा केन्द्र व राज्य सरकार के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन किया गया।

इस दौरान मुख्य रूप से नरेश ठाकुर, नितिन पोटाई , राजेश भास्कर, यासीन कराणी,मनोज जैन, सुनील गोस्वामी, अजय रेणु, विजय यादव, मुकेश तिवारी, पुरुषोत्तम पाटिल, अजय भाषवानी ,सोमेश सोनी, ओम प्रकाश देवांगन, इशहाक अहमद, शिवांकित श्रीवास्तव, खोमेंद्र उइके, सत्यार्थ , रोशन आरा, भारती सलाम, लक्ष्मी सहारे, लता मंडावी, यासमीन खान, वीना जैन, संग्राम नेताम, के डी मिश्रा,चंद्रलोक सिंह, सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रेरणा: उषा ने गांव में राइस मिल और टोरा मिल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की

मुरदोण्डा की उषा कुंजाम बनीं ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा

बीजापुर / नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के सुदूर आदिवासी अंचल ग्राम मुरदोण्डा, तहसील उसूर, जिला बीजापुर की निवासी 38 वर्षीय श्रीमती उषा कुंजाम ने संघर्षों से भरे जीवन को मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर सफलता की नई पहचान दी है। आज वे न केवल आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अपने क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुकी हैं।

उषा कुंजाम लंबे समय तक बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच आय का कोई स्थायी साधन

नहीं होने से जीवन काफी कठिनाइयों में बीत रहा था। सुदूर आदिवासी क्षेत्र होने के कारण रोजगार के अवसर भी सीमित थे, जिससे आर्थिक और मानसिक परेशानियाँ लगातार बढ़ती जा रही थीं। इसी दौरान उन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, बीजापुर के माध्यम से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME की जानकारी प्राप्त हुई। विभाग के मार्गदर्शन और सहयोग से उन्होंने योजना अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन किया। सभी आवश्यक प्रक्रियाएँ पूर्ण होने के बाद वर्ष 2025-26 में आईसीआईसीआई बैंक बीजापुर से उन्हें 3 लाख 90 हजार 400 रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ। इस आर्थिक सहयोग से उषा कुंजाम ने अपने गांव में राइस मिल तथा टोरा मिल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की। पहले क्षेत्र में टोरा मात्र 8 से 10 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता था, जिससे ग्रामीणों को बहुत कम लाभ मिल पाता था। अब वे टोरा का प्रसंस्करण कर उससे तेल निकालती हैं, उसकी पैकेजिंग कर लगभग 100 रुपये प्रति लीटर की दर से बाजार में बेचती हैं। यह तेल मंदिरों में दीप प्रज्वलन एवं पर्व, त्योहारों में अधिक उपयोग होने के कारण लगातार मांग में बना रहता है। इसके साथ ही टोरा से निकलने वाली खली को भी 12 से 15 रुपये प्रति किलो की दर से बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने राइस मिल की स्थापना कर ग्रामीणों को बड़ी सुविधा उपलब्ध कराई है। पहले गांव के लोगों को धान से चावल निकलवाने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में जाना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की परेशानी होती थी।

मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही जनता

अंतागढ़ / नवप्रदेश। क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की बदहाल स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। गांवों में पेयजल, शिक्षा, सड़क, आंगनबाड़ी और बिजली जैसी बुनियादी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, जबकि दूसरी ओर उच्च स्तर के जनप्रतिनिधियों की निधि उपयोग नहीं हो पाने के कारण वापस लौट रही है। इस स्थिति को लेकर क्षेत्र में शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जनता छोटी-छोटी समस्याओं के लिए परेशान है, लेकिन जिम्मेदारों का ध्यान जमीनी समस्याओं की ओर नहीं है। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। कई जगह भवन जर्जर हैं, संसाधनों की कमी है, फिर भी सुधार कार्यों में अपेक्षित गति दिखाई नहीं दे रही! ग्रामीणों मे चैनसिंह उयके छिंदभाट सुरेवाही पंचायत,कौड़ों खसगांव शिव हिड़को वार्डपंच बुलावंड पंचायत

कोयेपारा करन सिंह उयके सदाराम पारा भैंसासुर पंचायत शिवलाल आचला खोड़पानी टेमरूपानी पंचायत का कहना है कि पानी कि समस्या ज्यादा इस क्षेत्र मे बनी हुई है जबकि दिनों दिन जलस्तर का घटना चिंता का विषय है!

पहले नक्सल समस्या थी बड़ी वजह, अब तो विकास कि रफ़्तार होः लोगों का कहना है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के नाम पर वर्षों तक सुरक्षा और विशेष व्यवस्थाओं की बात की गई, लेकिन अब नक्सल समाप्ति के दावे के बाद भी आम जनता तक विकास की मूल सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं।

ग्रामीणों में यह भावना बढ़ रही है कि जनता के टैक्स और संसाधनों से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ आम लोगों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच रहा।

जल जीवन पर गंभीर सवाल, कई गावों मे अधूरे कार्य?

क्षेत्र में जल जीवन मिशन और नल-जल योजनाओं की स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए है कई गांवों में अधूरे कार्य छोड़ दिए गए हैं।

छग को वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता: राजेश

अम्बिकापुर/नवप्रदेश। घने वनों की हरियाली, जलप्रपातों की गूंजती कलकल ध्वनि, समृद्ध जनजातीय संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ अब वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर तेजी से अपनी अलग पहचान बना रहा है।

कभी देश के भीतर ही सीमित पहचान रखने वाला छत्तीसगढ़ अब विदेशी सैलानियों के लिए भी आकर्षण का नया केन्द्र बनता जा रहा है। वर्ष 2025 में 820 विदेशी पर्यटकों का राज्य आगमन इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ की अनछुई प्राकृतिक संपदा, सांस्कृतिक विविधता और शांत वातावरण दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और आत्मीयता दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता रखती है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार पर्यटन स्थलों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार, बेहतर संपर्क मार्ग, सुरक्षित वातावरण, प्रकृति पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। बस्तर, सरगुजा, मैनपाट और जशपुर जैसे क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए विशेष योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। अग्रवाल ने कहा कि पर्यटन केवल राज्य

की पहचान को ही मजबूत नहीं करता, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित करता है। आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ विदेशी पर्यटकों के लिए भारत का एक नया और आकर्षक पर्यटन केन्द्र बनकर उभरेगा। राज्य सरकार तथा छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का विकास, बेहतर सड़क संपर्क, पर्यटक सुरक्षा, डिजिटल प्रचार-प्रसार और पर्यटन अधोसंरचना के विस्तार से छत्तीसगढ़ अब राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन जगत में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। छत्तीसगढ़ को 'पर्यटकों का स्वर्ग' कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहां प्रकृति और संस्कृति का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जो पर्यटकों को एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। चित्रकोट जलप्रपात की भव्यता, तीरथगढ़ जलप्रपात की प्राकृतिक सुंदरता, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता, सिरपुर और रतनपुर जैसे ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों की विरासत, बस्तर की जनजातीय परंपराएँ, लोकनृत्य तथा सरगुजा और जशपुर की शांत वादियाँ विदेशी पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित कर रही हैं। छत्तीसगढ़ विश्व पर्यटन जगत में एक अनूठा गंतव्य बनकर उभर रहा है।

न्यूज गैलरी

लूण्ड्रा के ग्राम बिल्हमा के जितन को मिली पक्के आवास की चाबी

अम्बिकापुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे 'सुशासन तिहार' के अंतर्गत गांव-गांव जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ग्रामीण की मांग और शिकायतों का समाधान कर शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के लूण्ड्रा विकासखंड के ग्राम बिल्हमा के रहने वाले जितन का पक्के मकान का बरसों पुराना सपना साकार हुआ है। 'सुशासन तिहार' के आयोजन में हितग्राही को उनके नए पक्के आवास की चाबी सौंपी गई है। अपने नए घर की चाबी पाकर भावुक हुए हितग्राही जितन ने बताया कि पक्का मकान मिलने से पहले उनका परिवार एक कच्चे और जर्जर घर में रहने को मजबूर था। उन्होंने अपनी पुरानी याद करते हुए बताया कि, ष्पहले हम कच्चे घर में रहते थे। बारिश के दिनों में भारी जलभराव और पानी टपकने से हम लोग और हमारा सामान भीग जाया करता था। हर एक-दो साल में घर टूट जाता था और उसे फिर से बनाने में भारी परेशानी व खर्च उठाना पड़ता था।शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना से मिले पक्के घर ने परिवार के जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला दिया है। जितन ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि, ष्अब शासन ने हमें पक्का घर दे दिया है। इस नए घर में हमारे बच्चे और पूरा परिवार बेहद खुशी और सुरक्षित तरीके से रह रहेंगे है। अब हमें मौसम की मार का कोई डर नहीं है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशन में गांव-गांव में मनाए जा रहे श्सुशासन तिहारश् के तहत ग्रामीणों को तैयार हुए नए घर की चाबी सौंपी जा रही हैं। जितन ने इस बुनियादी जरूरत को समझने और उनका खुद के घर का सपना पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हृदय से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि शासन के प्रयासों के कारण आज हम जैसे आम नागरिकों का पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है।

रोजगारोन्मुखी नि:शुल्क आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण

अम्बिकापुर/नवप्रदेश। केन्द्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रोद्योगिकी संस्थान (सिपेट) रायपुर में एसईसीएल बिलासपुर द्वारा प्रायोजित रोजगारोन्मुखी नि:शुल्क आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 1000 जरूरतमंद युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना है। जिला कौशल विकास प्राधिकरण के सहायक संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदकों के चयन हेतु 21 मई से 28 मई 2026 तक लाईवलीहुड कॉलेज भवन नमनाकला रोड गांधी चैक के पास अंबिकापुर में काउंसिलिंग हेतु शिविर आयोजित की गई है। जिसमें 06 कोर्स मशीन ऑपरेटर- प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मशीन ऑपरेटर- इंजेक्शन मोल्डिंग, मशीन ऑपरेटर- प्लास्टिक एक्सट्रूजन, मशीन ऑपरेटर- ब्लो मोल्डिंग, मशीन ऑपरेटर-टूल रूम, मशीन ऑपरेटर और प्रोग्रामर - सी.एन.सी. मिलिंग के 04 माह के कोर्स में नि:शुल्क प्रशिक्षण हेतु जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं का चयन किया जायेगा। आवेदन करने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 11वीं उत्तीर्ण एवं आयु 18 से 28 वर्ष होना चाहिये। इच्छुक हितग्राही 10वीं की अंक सूची, आधार कार्ड की प्रति, छायाप्रति एवं 02 रंगीन फोटो के साथ शिविर स्थल पर उपस्थित होकर लाभ ले सकते हैं। इच्छुक हितग्राही पंजीयन हेतु श्री गेंदलाल ढीढी मोबाईल नं. 9589566641 तथा श्री नीरज कुमार सार्वा मोबाईल नं. 9993788497 से संपर्क कर अपना पंजीयन करा सकते हैं।

बिलमा के जमुनिया का बना आयुष्मान कार्ड, इलाज की दूर हुई चिंता

अम्बिकापुर/नवप्रदेश। राज्य शासन द्वारा चलाए जा रहे 'सुशासन तिहार' अभियान का सकारात्मक असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। इस अभियान के माध्यम से दूरस्थ अंचलों के ग्रामीणों तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। इसी कड़ी में लूण्ड्रा विकासखंड के ग्राम बिलमा के जमुनिया को सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित जन समस्या निवारण शिविर अपना आयुष्मान कार्ड प्राप्त हुआ है, जिससे उनके परिवार को अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक चिंताओं से मुक्ति मिल गई है। ग्राम बिलमा के हितग्राही जमुनिया ने अपनी खुशी और राहत व्यक्त करते हुए बताया कि पहले आयुष्मान कार्ड नहीं होने के कारण उन्हें अपना और अपने परिवार का इलाज कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने अपनी आपबीती साझा करते हुए कहा, पहले तबियत बार-बार खराब होती थी और कार्ड न होने के कारण इलाज कराने में बड़ी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही थी। लेकिन आज 'सुशासन तिहार' के अंतर्गत आयोजित शिविर में मेरा आयुष्मान कार्ड आसानी से बन गया है। अब हम इसी कार्ड के माध्यम से बिना किसी परेशानी के अपना समुचित इलाज करवा सकेंगे।लंबे समय से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे जनमुनिया ने राहत की सांस लेते हुए इस संवेदनशील पहल के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार की अनूठी पहल से हम जैसे गरीब और आम नागरिकों की समस्याओं का सीधा समाधान हो रहा है। 'सुशासन तिहार' के माध्यम से प्रशासन स्वयं जनता के द्वार पहुंचकर उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण कर रहा है। इस अभियान के तहत जन समस्या निवारण शिविर लगाकर लोगों को आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, और पेंशन जैसी विभिन्न शासकीय योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में सुशासन की सरकार' की परिकल्पना साकार हो रही है।

नवागढ़ की प्राचीन धरोहरों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार सजग

अम्बिकापुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कोंडागांव जिले के नवागढ़ क्षेत्र में प्राप्त प्राचीन पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में त्वरित संज्ञान लिया है।

मंत्री अग्रवाल ने पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय को निर्देशित किया है कि नवागढ़ क्षेत्र में उपलब्ध प्राचीन प्रतिमाओं और अन्य पुरातात्विक अवशेषों का विशेषज्ञ दल के माध्यम से शीघ्र स्थल निरीक्षण एवं विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाए। संस्कृति मंत्री अग्रवाल ने कहा कि नवागढ़ क्षेत्र में 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी से संबंधित प्राचीन प्रतिमाओं और अन्य अवशेषों की जानकारी सामने आने के बाद इस स्थल का वैज्ञानिक अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विशेषज्ञ दल द्वारा क्षेत्र में उपलब्ध सभी प्रतिमाओं, स्थापत्य अवशेषों, शिल्प कलाकृतियों और संभावित पुरातात्विक स्थलों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तथा उनका विस्तृत दस्तावेजीकरण भी किया जाए, ताकि इन धरोहरों के ऐतिहासिक महत्व का समुचित आकलन किया जा सके। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि सर्वेक्षण और स्थल निरीक्षण से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यकतानुसार इन पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। यदि स्थल का ऐतिहासिक महत्व प्रमाणित होता है, तो उसे संरक्षित पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में भी पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती प्राचीन सभ्यताओं, स्थापत्य कला और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं से परिपूर्ण रही है। प्रदेश के अनेक अंचलों में ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिनका व्यवस्थित अध्ययन और संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार इन धरोहरों की पहचान, संरक्षण और उनके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। अग्रवाल ने कहा कि राज्य की ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और आम नागरिकों की सहभागिता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इन धरोहरों का संरक्षण केवल अतीत को सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों और इतिहास से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है।

सरगुजा में मिलीं 140 वर्ष पुरानी तंत्र साधना की दुर्लभ पांडुलिपियां

अम्बिकापुर/नवप्रदेश। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा देशभर में संचालित पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान के अंतर्गत सरगुजा जिले से लगातार महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की जानकारी सामने आ रही है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पांडुलिपियों के संरक्षकों द्वारा स्वप्रेरणा से प्रशासन को सूचना दी जा रही है, जिनका प्रशिक्षित सर्वेयरों द्वारा दस्तावेजीकरण एवं ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। इसी क्रम में अम्बिकापुर के ब्रम्हपारा राममंदिर के सामने पाण्डेय परिवार के पास तंत्र साधना से संबंधित पांडुलिपियां पाई गई। बुधवार को पांडुलिपियों को देखने सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा उपायुक्त आर के खूंटे के साथ पाण्डेय परिवार के घर पहुंचे। पांडुलिपियों के संरक्षक राकेश पाण्डेय ने अपने पूर्वजों की धरोहर पांडुलिपियों की जानकारी देते हुए बताया कि तंत्र साधना से संबंधित लगभग 140 वर्ष पुरानी चार पांडुलिपियां हैं। पांडुलिपियां वनदुर्गा तंत्र साधना , भुजंग प्रपात, अथ बगलामुखी और वनदुर्गा अथर्वण रहस्य रचनाएं संवत् 1886 में उनके प्रपितामह स्व. चतुरा प्रसाद शर्मा द्वारा लिखी गई थीं। सम्भागायुक्त दुग्गा ने कहा कि ज्ञानभारतम अभियान भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, लोक संस्कृति, पांडुलिपियों, पुरातात्त्विक धरोहरों एवं जनजातीय विरासत के संरक्षण और संवर्धन का एक महत्वपूर्ण अभियान है। यह पहल समाज में इतिहास, साहित्य, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का कार्य करती है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जगदलपुर से आए सरगुजा के प्रभारी अधिकारी हरनेक सिंह ने पांडुलिपियों को अपलोड करने का कार्य किया।

अम्बिकापुर में निजी एवं शासकीय विद्यालयों की समीक्षा बैठक आयोजित

अम्बिकापुर/नवप्रदेश। कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देशानुसार परीक्षा परिणाम, निजी विद्यालयों के संचालन एवं आगामी सत्र हेतु कार्य योजना के संबंध में सर्व अशासकीय प्राचार्यध्प्रधान पाठक, उमा विद्यालय, हाई स्कूल एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं की बैठक जिला शिक्षा अधिकारी डॉ दिनेश झा की अध्यक्षता में शासकीय पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित की गई।

बैठक में बीईओ, एबीईओ, बीआरसीसी सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।बैठक में अशासकीय विद्यालयों के नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण संबंधी आवेदनों पर विस्तृत जानकारी देते हुए चेकलिस्ट अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ।

बोर्ड परीक्षा परिणाम, विद्यालय संचालन, 2020, अपार आईडी, यूडाईस एवं ड्रॉपआउट विद्यार्थियों के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई।हाई एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा परिणाम की विद्यालयवार समीक्षा करते हुए अच्छे प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों की सराहना की गई तथा खराब परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों को आगामी सत्र हेतु कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा में अशासकीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर पाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध मान्यता निरस्तीकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। बैठक में विद्यालयों को 2020 का पालन करने, एनसीईआरटी की पुस्तकों से अध्यापन कराने तथा अतिरिक्त पुस्तकें संचालित करने से पूर्व पालक समिति एवं जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमति लेने के निर्देश दिए गए। मनमानी फीस वृद्धि अथवा पुस्तकों के संबंध में शिकायत प्रमाणित पाए जाने पर संबंधित विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई। बैठक में शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के प्राचार्यों, विखं शिक्षा अधिकारियों एवं संकुल समन्वयकों के साथ परीक्षा परिणाम, पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं सायकल वितरण, भवन विहीन विद्यालयों तथा अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता की समीक्षा की गई।बैठक में निर्देशित किया गया कि कोई भी छात्र-छात्रा शाला त्यागी न हो। पीव्हीटीजी बच्चों एवं आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बच्चों का सर्वेक्षण कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ते हुए 16 जून को विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित कराया जाए।

आंगनबाड़ी सहायिका के 2 रिक्त पदों पर भर्ती, आवेदन 3 जून तक

अम्बिकापुर/नवप्रदेश। एकीकृत बाल विकास परियोजना अंबिकापुर (ग्रामीण)के परियोजना अधिकारी ने बताया कि आंगनबाड़ी सहायिका के 02 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक एवं पात्र महिला अभ्यर्थियों से 03 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भरे जाएंगे। रिक्त पदों में सेक्टर सकालो के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंन्द्र चिखलाडीह में सहायिका 01 एवं सेक्टर भफौली अंतर्गत आंगनबाड़ी केंन्द्र उरांवपारा में आंगनबाड़ी सहायिका के 01 पद भर्ती की जानी है। उन्होंने बताया कि उक्त पदों पर केवल महिला ही आवेदन कर सकती है।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ/स) अम्बिकापुर मण्डल अम्बिकापुर
निविदा आमंत्रण तिथि: 19.05.2026
ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

01. निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये Log in करें http://eproc.cgstate.gov.in
02. संबंधित संभाग-स.क्र. 1 से 6 अम्बिकापुर, स.क्र. 7 से 9 सूरजपुर एवं स.क्र. 10 पत्थलगांव संभाग
03. स.क्र. 01- 'स' वर्ग एवं ऊपर ठेकेदार एवं स.क्र. 02 से 10 -'द' वर्ग एवं ऊपर ठेकेदार
04. ऑनलाईन निविदा डालने की अंतिम तिथि- स.क्रं.1 से 9-12.06.2026 एवं स.क्र.10-05.06.2026

सरल क्र.	एन.आई.टी.क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1	33	लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग अम्बिकापुर के अंतर्गत विभिन्न शासकीय आवासीय भवनों का एम ओ डब्ल्यू कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	120.00
2	34	लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग अम्बिकापुर के अंतर्गत विभिन्न शासकीय गैर आवासीय भवनों का एम ओ डब्ल्यू कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	80.00
3	35	लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग सीतापुर के अंतर्गत विभिन्न मार्गो में पुल पुलियों का विशेष मरम्मत कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	30.00
4	36	लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग क्रं. 1 अम्बिकापुर के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में पुल पुलियों का विशेष मरम्मत कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	30.00
5	37	लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग क्र. 2 अम्बिकापुर के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में पुल पुलियों का विशेष मरम्मत कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	29.99
6	38	जिला सरगुजा के धौरपुर सन्ना मार्ग लंबाई 50.00 कि.मी. का सर्वे कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	22.47
7	39	लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग सूरजपुर अंतर्गत विभिन्न मार्गो में डब्ल्यू.एम.एम पैच एवं बिटुमिन ईमल्शन पैच रिपेयर का कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	35.00
8	40	लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग सूरजपुर एवं प्रेमनगर अंतर्गत विभिन्न मार्गों में साधारण मरम्मत का कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	20.00
9	41	लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग प्रेमनगर अंतर्गत विभिन्न मार्गो में डब्ल्यू.एम.एम पैच एवं बिटुमिन ईमल्शन पैच रिपेयर का कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	25.00
10	42	जिला जशपुर के पत्थलगांव के शासकीय महाविद्यालय पत्थलगांव के छात्रावास भवन में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	63.92

जी- 262700886/8

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग
अम्बिकापुर मंडल अम्बिकापुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़, जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)
फैक्स नम्बर - 07771-242743 ई-मेल :- nagarpalikamdgr@yahoo.in फोन नम्बर - 07771-242743

क्र./245 /न.पा./ लो.नि.वि./2026 — मनेन्द्रगढ़, दिनांक 21/5/26

!! मैन्युअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना !!

एतद् द्वारा नगरपालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ में एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से त्रिलिफाफा पद्धति से मोहर बंद लिफाफा में स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से निम्नलिखित कार्य हेतु मैन्युअल निविदा आमंत्रित की जाती है। लिफाफे में कार्य का नाम टी.डी.आर./एफ.डी.आर. का विवरण एवं दिनांक लिफाफा के ऊपर अंकित होने पर ही लिफफा स्वीकार किया जायेगा।
1. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय - 12.06.2026 अपरान्ह 3:00 बजे तक
2 निविदा खोलने की तिथि एवं समय - 15.06.2026 पुर्वान्ह 12:00 बजे से

(राशि रु. लाखों में)

स. क्र.	कार्य का नाम	अनु. लागत (लाख में)	अमानत राशि (टी.डी.आर. / एफ.डी.आर.)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य की अवधि
1	विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ के शा.प्रा.शा. वार्ड नं. 09 मनेन्द्रगढ़ नवीन अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य।	8.07	6100.00	750.00	4 माह
2	विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ के शा.उ.मा. विद्यालय (टी. संवर्ग) मनेन्द्रगढ़ कक्ष भवन मरम्मत कार्य।	4.00	4000.00	750.00	4 माह
3	नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत वार्ड नं. 11 जलगृह पानी टंकी में स्थित 25 एच.पी. मोटर पम्प मरम्मत कार्य।	3.00	3000.00	750.00	1 माह
4	वार्ड नं. 05 में 20 एच.पी. 01 नग पम्प कम्प्लीट फिटिंग सहित लगाये जाने का कार्य।	3.00	3000.00	750.00	1 माह
5	मौहारपारा में पानी टंकी के पास 20 एच.पी. 01 नग पम्प कम्प्लीट फिटिंग सहित लगाये जाने का कार्य।	3.00	3000.00	750.00	1 माह
6	नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत शा. कन्या उ.मा.वि. शिक्षा विभाग के स्कूल परिसर में मरम्मत कार्य।	5.00	5000.00	750.00	3 माह

नोट - उक्त निविदा हेतु शासन की विभागीय वेबसाईट www.uad.cg.gov.in से निविदा प्रपत्र फार्म A एवम् फार्म B डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर निविदा प्रपत्र शुल्क डीडी. के रूप मे तथा अमानत राशि एफ.डी.आर./टी.डी.आर. / के रूप में एवं निविदा के समस्त दस्तावेज सील एवं स्व प्रमाणित सहित स्वीकार की जावेगी। निविदा से संबंधित कार्यो की विस्तृत जानकारी एवं नियम तथा शर्ते कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की विभागीय वेबसाईट वेबसाईट www.uad.cg.gov.in में देखा जा सकता है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मण्डल दुर्ग (छत्तीसगढ़)
// निविदा निरस्त करने की सूचना //

इस कार्यालय की निविदा सिस्टम क्र. 27/189830 एवं 31 / 190355 ज्ञाप क्र. 2215/सा./ 2026 दुर्ग दिनांक 27.04.2026 एवं ज्ञाप क्र. 2458/ सा./ 2026 दुर्ग दिनांक 05.05.2026 जिसका जी क्र. 00474 एवं 262700681 का अपरिहार्य कारण से निविदा निरस्त किया जाता है।

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मण्डल दुर्ग
जी-262700889/2 — दूरभाष 0788-2210876

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग मुंगेली संभाग मुंगेली (छ.ग.)
निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक- 2625/NIT-1/2026-27/व.ले.लि./ — मुंगेली दिनांक 19/05/2026
निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- 28/05/2026 अपरान्ह 05.30 बजे तक
ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदायें प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- 03/06/2026 अपरान्ह 05.30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि :- 04/06/2026 पूर्वान्ह 11.30 बजे

एनआईटी क्र. (1) निविदा क्र. (T0029-T0036) कार्य का नाम / NO of Calls - समस्त कार्य प्रथम आमंत्रण निविदाकारों की श्रेणी- समस्त कार्यों हेतु ई- पंजीयन के अंतर्गत श्रेणी 'द' से 'अ'	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में) अमानत राशि (रू.में) बैंक साल्वेंसी (रू.में) निविदा प्रपत्र की कीमत (रू.में) कार्य अवधि
जेल भवन के बाहर दीवार (आउटर वाल) का विशेष मरम्मत कार्य	9.98 7485.00 149700.00 750.00 02 माह (वर्षा ऋतु सहित)
उपसंभाग मुंगेली अंतर्गत एच टाइप शासकीय आवासगृह एवं ट्रांजिट हास्टल करही में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य	9.95 7463.00 149250.00 750.00 02 माह (वर्षा ऋतु सहित)
जिला मुंगेली अंतर्गत बाल कल्याण समिति भवन निर्माण कार्य	8.65 6488.00 129750.00 750.00 03 माह (वर्षा ऋतु सहित)
जिला मुंगेली अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड के भवन निर्माण कार्य	8.65 6488.00 129750.00 750.00 03 माह (वर्षा ऋतु सहित)
जिला मुंगेली के शासकीय डॉ ज्वाला प्रसाद मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुंगेली के शौचालय का मरम्मत कार्य	8.63 6473.00 129450.00 750.00 02 माह (वर्षा ऋतु सहित)
तहसील कार्यालय भवन पथरिया का विशेष मरम्मत कार्य	5.00 3750.00 75000.00 750.00 02 माह (वर्षा ऋतु सहित)
हायर सेकेंडरी स्कूल भवन दशरंगपुर में अंदर बाहर एवं छत का प्लास्टर का मरम्मत कार्य	3.00 2250.00 45000.00 750.00 01 माह (वर्षा ऋतु सहित)
जिला जेल मुंगेली के बंदी परिजनों हेतु बनाये गये मुलाकाती शेड एवं पाकशाला में बने शेड में नया टिन लगाने का कार्य	1.00 750.00 15000.00 750.00 01 माह (वर्षा ऋतु सहित)

निविदा संबंधी शर्ते विभागीय वेबसाईट www.pwd.cg.nic.in में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

जी- 262700883/3

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
मुंगेली संभाग मुंगेली (छ.ग.)

खरीफ 2026 के लिए खाद-बीज वितरण व्यवस्था को लेकर समन्वय बैठक आयोजित

मुंगेली/नवप्रदेश। जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में खरीफ वर्ष 2026 हेतु खाद एवं बीज की सुचारू वितरण व्यवस्था को लेकर समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी खरीफ सीजन में किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने और वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में विधायक पुन्नूलाल मोहले, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय, कलेक्टर कुन्दन कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी, जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर जी.एल.यादव, तीनों अनुविभागों के एसडीएम, जनपद पंचायत अध्यक्ष मुंगेली रामकमल सिंह परिहार, कृषि विभाग के उपसंचालक श्रीमती वीणा ठाकुर, सहायक संचालक कृषि श्रीमती ललिता मरावी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी सुभाष सोनी, जिला उर्वरक निरीक्षक मनहरण कुर्रे, जिला किसान संघ अध्यक्ष, कृषि स्थायी समिति के सभापति, प्रगतिशील किसान तथा थोक उर्वरक विक्रेता उपस्थित थे।

विधायक पुन्नूलाल मोहले ने कहा कि खाद वितरण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। कृषकों के ऋण पुस्तिका में वितरित खाद का अनिवार्य रूप से अंकन किया जाए, जिससे एक ही किसान द्वारा अलग-अलग स्थानों से उठाव न हो। उन्होंने कहा कि किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड की जानकारी दें तथा मृदा परीक्षण के आधार पर खरीफसीजन में आवश्यक खाद उपयोग के संबंध में

जागरूक करें। सभी समितियों एवं दुकानों में खाद की रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाए तथा निर्धारित दर पर ही खाद वितरण सुनिश्चित हो। जिले के सभी किसानों को डिजिटल ऋण पुस्तिका शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। संयुक्त खातेदार किसानों को उनके हिस्से के अनुपात में खाद वितरण किया जाए, ताकि किसी भी किसान को परेशानी का सामना न करना पड़े। कलेक्टर ने कहा कि मुंगेली कृषि प्रधान जिला है, इसलिए खरीफ सीजन में खाद-बीज वितरण की व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सभी कृषकों को सहकारी एवं निजी क्षेत्र के माध्यम से पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से खाद उपलब्ध कराया जाएगा और किसानों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बड़े किसान अपने धारित रकबे के अनुसार खाद उठाव करें, ताकि सभी किसानों को समय पर खाद मिल सके, यूरिया का उपयोग केवल कृषि कार्यों में ही करें। उन्होने बताया कि खाद वितरण से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को नामांतरण, सीमांकन एवं विवादित-अविवादित बंटवारे के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए, ताकि किसान समय पर एग्रीस्टैक में पंजीयन कर खाद प्राप्त कर सकें।

न्यूज गैलरी

छह माह से मानदेय नहीं मिलने पर बंद हुआ पानी टंकी संचालन

मुंगेली/नवप्रदेश। ग्राम पंचायत पौनी में शासन की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी टंकी निर्माण एवं पाइपलाइन बिछाने का कार्य ठेकेदार के माध्यम से कराया गया है। किन्तु वर्तमान समय में ग्राम के अनेक मोहल्लों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है तथा जहां पाइपलाइन बिछाई गई है वहां कई स्थानों पर पाइपलाइन टूट-फूट एवं लीकेज की स्थिति में है, जिसकी तत्काल मरम्मत कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। उक्त योजना के अंतर्गत पानी टंकी के नियमित संचालन, मोटर पंप चालू-बंद करने एवं देखरेख हेतु ग्राम के निवासी काशीराम साहू, पिता दुकलहा साहू को मासिक मानदेय पर कार्य हेतु रखा गया था, किन्तु विगत लगभग छह माह से उनका मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। मानदेय राशि नहीं मिलने के कारण काशीराम साहू द्वारा पिछले पांच दिनों से पानी टंकी का संचालन बंद कर दिया गया है तथा उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जब तक उनका बकाया मानदेय भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक वे पानी टंकी की चाबी नहीं देंगे एवं मोटर पंप निकाल देंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए काशीराम साहू का लंबित मानदेय राशि ठेकेदार के माध्यम से शीघ्र भुगतान कराया जाए, पानी टंकी का नियमित संचालन पुनः प्रारंभ कराया जाए।

करियर, मोटिवेशन और व्यक्तित्व विकास पर मिलेगा विशेष मार्गदर्शन

मुंगेली/नवप्रदेश। राजपूत क्षत्रिय समाज मुंगेली-तखतपुर परिक्षेत्र द्वारा समाज के छात्र-छात्राओं को शिक्षा, कैरियर एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में सही दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से ÷भविष्य निर्माण मार्गदर्शन एवं प्रेरणा कार्यक्रम÷ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रेरित करने, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने एवं उन्हें जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर सफलता की ओर अग्रसर करने हेतु विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय, जिला पंचायत सीईओ एवं जिला शिक्षा अधिकारी एलपी डाहिरे से समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट कर कार्यक्रम में सम्मिलित होने एवं विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने हेतु आमंत्रण प्रदान किया। प्रतिनिधिमंडल द्वारा अतिथियों को कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा से अवगत कराया गया तथा बताया गया कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में विद्यार्थियों को समय पर सही मार्गदर्शन मिलना अत्यंत आवश्यक है। कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी उचित जानकारी एवं प्रेरणा के अभाव में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ऐसे में समाज द्वारा यह प्रयास विद्यार्थियों के भविष्य को नई दिशा देने वाला सिद्ध होगा। अतिथियों ने समाज द्वारा शिक्षा एवं युवा पीढ़ी के हित में किए जा रहे इस सराहनीय प्रयास की प्रशंसा करते हुए कार्यक्रम में अपनी सहमति प्रदान की एवं आयोजन की सफलता हेतु शुभकामनाएं दीं।

प्रशासन की अपील पर व्यापारियों ने स्वेच्छा से हटाया अतिक्रमण

मुंगेली/नवप्रदेश। नगर में लगातार बढ़ते यातायात और अवैध कब्जे के दबाव को कम करने और आम नागरिकों को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है, नगर के बिलासपुर मुख्य मार्ग को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए प्रशासन द्वारा सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने संयुक्त कार्रवाई की यह कार्रवाई नगर के व्यस्ततम इलाके दाऊपारा से लेकर कलेक्टर निवास, नगर पालिका सीमा तक चलाई गई। सड़क को चौड़ा और बाधारहित बनाने के लिए की गई इस कार्रवाई से पहले नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी दुकानदारों और व्यापारियों को मुनादी कराकर अपील की थी। प्रशासन ने व्यापारियों को समझाइश दी थी कि वे सड़क और नाली के ऊपर किए गए अपने अतिक्रमण को स्वतः ही हटा लें। इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला प्रशासन की अपील पर कई जागरूक व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने-अपने शेड, काउंटर और अन्य सामग्रियां हटा लीं। इसके बाद,जो अतिक्रमण बाकी रह गए थे,उन्हें भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासनिक अमले द्वारा हटाया गया। नगर को व्यवस्थित करने की इस बड़ी मुहिम में जिला प्रशासन के कई प्रमुख विभागों ने एक साथ मिलकर मोर्चा संभाला, इस संयुक्त कार्रवाई में नगर पालिका परिषद, राजस्व विभाग, नजूल विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी दल-बल के साथ सुबह से ही मुस्तैद नजर आए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर बेतरतीब ढंग से फैले मलबे, अवैध टीन शेड और चबूतरों को साफकिया गया। बिलासपुर मार्ग में अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के पीछे प्रशासन का उद्देश्य केवल सड़क चौड़ीकरण ही नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा भी है। अधिकारियों ने बताया कि दाऊपारा से लेकर कलेक्टर निवास तक मुख्य सड़क के दोनों ओर आधुनिक और सुव्यवस्थित फुटपाथ का निर्माण कराया जा रहा है।

मनरेगा कार्यों में चल रहा फर्जी हाजरी का खेल

मजदूरों ने ऑन कैमरा कहा फोटो खिंचवाकर चले जाते हैं, पंचायत फुलकोना का मामला

इन्द्रपाल यादव

अनूपपुर/नवप्रदेश। जनपद पंचायत बदरा अंतर्गत ग्राम पंचायत फूलकोना में मनरेगा कार्यों में बड़े स्तर पर अनियमितताओं और फर्जी हाजिरी लगाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शासन की महत्वाकांक्षी रोजगार योजना को पंचायत के जिम्मेदार लोग भ्रष्टाचार का जरिया बना चुके हैं।

बताया जा रहा है कि हितग्राही फूलमती पति दयाराम के नाम पर खेत तालाब स्वीकृत किया गया है, लेकिन जमीनी स्थिति कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आरोप है कि कार्यस्थल पर वास्तविक मजदूरों की बजाय फर्जी तरीके से ऑनलाइन हाजिरी लगाई जा रही है और रोजगार के नाम पर राशि निकाली जा रही है।

ग्रामीणों के अनुसार रोजगार सहायक विनोद चतुर्वेदी के संरक्षण में यह पूरा खेल चल रहा है। वहीं गणेश चौधरी पर भी फर्जी हाजिरी लगाने के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि

कार्यस्थल पर मजदूर नियमित रूप से काम नहीं करते, बल्कि केवल फोटो खिंचवाने के समय मोटरसाइकिल से पहुंचकर उपस्थिति दर्ज कराई जाती है और बाद में पोर्टल पर फोटो अपलोड कर दी जाती है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ÷मेट÷ और ÷मुंशी÷ के नाम पर अपनी पत्नियों एवं परिचितों को खड़ा कर फोटो अपलोड कराई जाती है, जबकि वास्तविक मजदूरों को काम और मजदूरी दोनों से वंचित किया जा रहा है। इस पूरे मामले में गणेश चौधरी, सुनील एवं रोजगार सहायक विनोद चतुर्वेदी की मिलीभगत की चर्चा ग्रामीणों के बीच जोरों पर है।

गांव के लोगों का कहना है कि मनरेगा योजना का उद्देश्य जरूरतमंद ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना है, लेकिन फूलकोना पंचायत में यह योजना कुछ लोगों के लिए कमाई का साधन बनती जा रही है। हितग्राहियों को यह तक जानकारी नहीं रहती कि उनके नाम पर कौन-कौन मजदूरी दिखाकर भुगतान निकाला जा रहा है।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने पर संबंधित लोग खुलेआम चुनौती देते हैं कि ÷हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऊपर तक कमीशन जाता है।÷

अब सवाल यह उठता है कि जब शासन डिजिटल इंडिया और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का दावा कर रहा है, तब आखिर ग्राम पंचायत फूलकोना में इस प्रकार की अनियमितताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं मनरेगा विभाग से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके।

इनका कहना है?

इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ से दूरभाष के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ।

-**जिला पंचायत**, सीईओ अनूपपुर

में बाहर हूं। वापस आने पर संबंधित स्थल का निरीक्षण करूंगा और स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि कहां अनियमितता या फर्जीवाड़ा हो रहा है।

– **स्वरूप सिंह**, सरपंच ग्राम पंचायत फुलकोना

मैं स्वयं कार्यस्थल पर नहीं जाता हूं। वहां मेंट एवं मुंशी उपस्थित रहते हैं, वहीं मजदूरो की हाजिरी लगाते हैं। यदि किसी प्रकार की फर्जी हाजिरी दर्ज हुई होगी तो उसे जांच कर डिलीट कर दिया जाएगा।

-**विनोद चतुर्वेदी**, रोजगार सहायक ग्राम पंचायत फुलकोना?

कई दिनों से अखबार में देख रहे हैं, लेकिन आज तक न कोई कार्यवाही हुआ।

– **मोतीलाल केवट**, ग्रामवासी पंचायत फुलकोना

गर्मी में बार-बार बिजली गुल से जनता परेशान

मुंगेली/नवप्रदेश। जिले में इन दिनों भीषण गर्मी और लगातार हो रही बिजली की ट्रिपिंग से आम जनता त्रस्त हो चुकी है,एक ओर तापमान 40 से 45 डिग्री के पार पहुँच चुका है वही दूसरी ओर दिन में 4-5 बार और रात में 2-3 बार बिजली बंद हो जाने से लोगो का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लोग घरो में पंखा, कूलर और एसी के सहारे गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे है लेकिन लगातार बिजली गुल होने से हालत और खराब हो रही है।

दिन में 4 बार 5 बार और रात में 2 बार 3 बार बंद हो रही है

बिजली- जिलेवासियों का कहना है कि दिन में 4 से 5 बार और रात में 2 से 3 बार बिजली ट्रिपिंग हो रही है बार-बार बिजली बंद होने से लोग पसीने से तरबतर होकर वर्षो पुराने साधन हाथ पंखा के सहारे समय बिताने को मजबूर है। लोगो का कहना है कि इस भीषण गर्मी में छोटे बच्चो, बुजूर्गो और मरीजो को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। गर्मी और लू के कारण उल्टी-दस्त और अन्य बिमारियो का खतरा बढ़ रहा है।

मेंटनेंस के बाद भी नही सुधरी व्यवस्था- आम नागरिक सवाल उठा रहे है कि हर वर्ष मानसून पूर्व मेंटनेंस के नाम पर कई घंटो तक बिजली बंद रखी जाती है इस वर्ष भी अप्रैल माह में 2-3 घण्टा विद्युत केन्द्रो में मेंटनेंस के नाम पर बिजली बंद कर दिया गया था बावजूद यदि दिन मे 4 से 5 और रात में 2-3 बार बिजली ट्रिपिंग हो रही है तो लोग पूछ रहे है कि ये आखिर कैसा मेंटनेंस था।

देशव्यापी केमिस्ट्स हड़ताल सफलतापूर्वक संपन्न

मुंगेली/नवप्रदेश।-ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर देशभर के केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट्स द्वारा अवैध एवं अनियंत्रित ऑनलाइन दवा बिक्री तथा जन स्वास्थ्य एवं लाखों छोटे केमिस्ट्स के अस्तित्व से जुड़े गंभीर मुद्दों के विरोध में राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल सफलतापूर्वक आयोजित की गई। राज्य केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के आह्वान पर जिले के सभी केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट्स ने अपने प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रखकर आंदोलन को सर्वसम्मति से समर्थन प्रदान किया। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन

ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के हड़ताल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित ज्ञापन संभागीय आयुक्त, जिलाधीश, एस.डी.एम., तहसीलदार के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें सरकार का ध्यान अत्यंत गंभीर मुद्दों की ओर आकर्षित किया गया, दवाओं की अवैध एवं अनियमित ऑनलाइन बिक्री,बिना वैध एवं सत्यापित चिकित्सकीय पर्चे के दवाओं की बिक्री एवं होम डिलीवरी ऑनलाइन दवा प्लेटफॉर्म्स द्वारा अत्यधिक छूट की अनुचित नीति, जिससे छोटे एवं लाइसेंसधारी केमिस्ट्स गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि जीएसआर 817 (ई) एवं जीएसआर 220(ई) को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, जिनका दुरुपयोग विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एवं क्विक कॉमर्स ऑपरेटर्स द्वारा दवाओं की अनियंत्रित डिलीवरी के लिए किया जा रहा है।

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए आज रोजगार मेला

मुंगेली/नवप्रदेश। जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा 22 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह रोजगार मेला जिला रोजगार कार्यालय, रोजगार मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। रोजगार मेला में इलेक्ट्रॉनिक मीटर टेक्नीशियन के 50 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा एवं स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं सेल्स मैनेजर के 05 पदों तथा इंश्योरेंस एजेंट जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज परिसर जमकोर, जिला मुंगेली में प्रातः 11 बजे से शाम 3 बजे तक आयोजित होगा। के 25 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे। जिला रोजगार कार्यालय ने योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होने की अपील की है।

विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर सुदूर वनांचल लमनी में स्वास्थ्य शिविर आयोजित

मुंगेली/नवप्रदेश। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डां. शीला शाहा एवं डीपीएम गिरीश कुर्रे, बी.एम.ओ. कमलेश खैरवार के मार्गदर्शन में आदिवासी एवं सुदूर वनांचल ग्राम लमनी में एनसीडी कार्यक्रम अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिले के सुदूर वनांचल जनजाति ग्राम लमनी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर व

जागरूक कर कैम्प लगा कर 78 ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। शिविर में 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी ग्रामीणों का रक्तचाप एवं मधुमेह परीक्षण कर स्वास्थ्य परामर्श एवं निःशुल्क दवाईयां दी गई। ग्रामीण अंचल एटीआर में शिविर लगाने का उदेश्य लोगो को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर स्वास्थ्य सेवा से जोड़ कर उन्हें उन्हें ईलाज के लिए अस्पताल पहुंच कर ईलाज कराकर स्वस्थ रखना है। इस शिविर में बीपी, शुगर, कुष्ठ टी.बी. डेगू, मलेरिया, नाक, कान गला ऑखों की जानकारी लेकर निःशुल्क दवाईयां दी गई। शिविर में पहले से बीपी के 10 केस मिले जिनका ईलाज चल रहा था, हाई बीपी के 12, बीपी मध्यम स्तर में 04 के साथ 40 लोगो का बीपी सामान्य पाया गया है। शुगर के मामले में 04 मरीज मिले। टी.बी. से मुक्ति अभियान के बार में परीक्षण में दो केस सामने आये है। जिन्हों ने टी.बी. से मुक्ति पायी है। ग्रामीण क्षेत्र में यह मुक्ति उल्लेखनीय है। शिविर में गैर संचारी रोग के जिला नोडल अधिकारी डॉ. मनीष बंजारा ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य की प्रति जागरूक करते हुए कहा कि सुदुर ग्रामीण अंचल जनजाति के लोगो को नशा से मुक्ति के लिए प्रेरित किया।

पेज 1 का शेष...

49 हजार करोड़ की बोधघाट...

केवल घोषणा तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे धरातल पर उतारने की तैयारी में है। 1979 में मध्य प्रदेश शासन के समय केंद्र सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी। उस समय इसका उद्देश्य 500 मेगावाट बिजली उत्पादन था, लेकिन अब इसका स्वरूप बदलकर बहुउद्देशीय कर दिया गया है। वर्तमान अनुमान के अनुसार इसकी लागत 49 हजार करोड़ रुपए से अधिक पहुंच चुकी है।

कांग्रेस शासन में भूपेश ने परियोजना सर्वे की दी थी स्वीकृति

हालांकि परियोजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज भी विस्थापन और जनसहमति की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में इस परियोजना के सर्वे और डीपीआर के लिए सैद्धांतिक सहमति देते हुए 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। उस दौरान उन्होंने नक्सलियों और विरोध करने वाले संगठनों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आदिवासियों के खेतों तक पानी और रोजगार पहुंचना चाहिए। लेकिन बाद में चुनावी दौर में उनका रुख बदला और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब तक बस्तर के लोग सहमत नहीं होंगे, तब तक बोधघाट परियोजना शुरू नहीं की जाएगी।

डिजिटल कृषि से जमाखोरों...

जाएगा। केंद्रीय स्तर पर एक 'विशेष सेल' बनाया गया है जो हर हफ्ते खाद-बीज की मॉनिटरिंग रिपोर्ट सीधे मंत्री को सौंपेगा। केंद्र सरकार ने देशभर के लिए 62 लाख टन यूरिया और 25 लाख टन डीएपी का प्रबंध कर लिया है।

दो बड़े ऐतिहासिक सुधार

इस बार खरीफ सीजन से छत्तीसगढ़ में 'नवीन ई-उर्वरक वितरण प्रणाली' लागू होने जा रही है। इसके तहत खाद वितरण व्यवस्था में दो बड़े ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं। एग्रीस्टेक पोर्टल : अब केवल उन्हीं किसानों को रासायनिक उर्वरक मिलेगा, जिनका पंजीकरण एग्रीस्टेक पोर्टल पर होगा। कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार ने इसके लिए पीएम किसान पोर्टल के डेटा को तेजी से माइग्रेट करने और सभी सात जिलों के कलेक्टरों को युद्ध स्तर पर पंजीकरण पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

पुलवामा ग्रेनेड अटैक में...

और कमांडर बन गया। अभी वह पाकिस्तान से ही काम कर रहा था। उस पर आरोप है कि वह युवाओं को अल बद्र में शामिल होने के लिए उकसाता था और फंडिंग भी करता था। जांच एजेंसियों के अनुसार 2020 में सीआरपीएफ जवानों पर ग्रेनेड हमले और युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती कराने जैसी गतिविधियों में भी शामिल रहा।

ईरान जंग पर ट्रम्प-नेतन्याहू में...

ऑपरेशन को 'ऑपरेशन स्लेजहैमर' नाम दिया जाना था। लेकिन करीब 24 घंटे बाद ट्रम्प ने घोषणा कर दी कि मंगलवार के लिए तय हमलों को फिलहाल रोक दिया गया है। ट्रम्प ने कहा कि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों की अपील पर यह फैसला लिया गया।

पीएम नरेंद्र मोदी की ५ दिवसीय...

मूल्य 40 अरब डॉलर है। इन कंपनियों की भारत में पहले से ही मजबूत उपस्थिति है और उनका कुल निवेश लगभग 180 अरब डॉलर का है।

यात्रा की उपलब्धियां

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल थे।

- नीदरलैंड के साथ व्यापार, रक्षा, सेमीकंडक्टर, AI और ग्रीन हाइड्रोजन पर रणनीतिक साझेदारी रोडमैप जारी किया गया।

- स्वीडन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति।

- नॉर्वे में तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भागीदारी।

बंगाल के मदरसों में 'वंदे ...

राजनीतिक बहस बेहद तेज हो गई है।

इस संबंध में पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा निदेशालय ने बकायदा एक आधिकारिक दिशा-निर्देश और शासनादेश जारी किया है। इस सरकारी आदेश में साफ और कड़े शब्दों में कहा गया है कि पुराने सभी नियमों और पूर्ववर्ती प्रथाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए यह नया नियम राज्य भर में लागू किया जा रहा है।

तेंदूपत्ता संग्राहकों के बीच...

समृद्धि लाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों की आय और कार्य परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वनाधारित आजीविका से जुड़े लोगों के हितों के संरक्षण और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए निरंतर प्रयास सुनिश्चित किए जाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संग्राहकों को चरण पादुका का वितरण कर उनका उत्साहवर्धन भी किया।

मौसम की 'अग्नि' परीक्षा...

शरबत,गन्ने का रस और कई प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स की मांग तेजी से बढ़ी है। हर सौ कदम पर लोगों को इन पेय पदार्थों की जरुरत महसूस हो रही है।

अब मदद होगी और तेज: जिले को मिली 24 अत्याधुनिक डायल-112 वाहन सेवा की सौगात

बिलासपुर/नवप्रदेश। आम नागरिकों को त्वरित सुरक्षा एवं आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में बिलासपुर जिले को 24 नई अत्याधुनिक डायल-112 वाहनों की बड़ी सौगात मिली है। बिलासागुड़ी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने वर्चुअली जुड़कर कहा कि संकट में 112 वाहन सेवा लोगों का सबसे बड़ा सहारा बन रही है। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई वाहनों के शामिल होने से जिले में पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम और अधिक मजबूत एवं प्रभावी होगा।

कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि डायल-112 सेवा आज आम जनता के भरोसे का मजबूत माध्यम बन चुकी है। नई तकनीक और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये वाहन आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों तक और तेजी से पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने लगातार कार्य कर रही है, ताकि हर नागरिक को सुरक्षित वातावरण मिल सके। कार्यक्रम में तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि डायल-112 सेवा जनता के भरोसे का प्रतीक बन चुकी है। संकट के समय यह सेवा लोगों को त्वरित राहत और सुरक्षा का एहसास कराती है। बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने वर्चुअली जुड़कर कहा कि डायल-112 सेवा की विशेषता यह है कि सूचना मिलते ही टीम लोकेशन ट्रेस कर तत्काल सहायता पहुंचाती है। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि किसी भी दुर्घटना, अपराध या आपदा में सबसे पहले पुलिस ही मौके पर पहुंचती है। उन्होंने कहा कि समाज और प्रशासन दोनों को मिलकर कानून व्यवस्था को मजबूत करना होगा। पुलिस जवान दिन-रात जनता की सुरक्षा में लगे रहते हैं और उनका सम्मान हर नागरिक का दायित्व है। विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि डायल-112 सेवा ने आम नागरिकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है।

डायल-112 सेवा अब प्रदेश के सभी 33 जिलों में: आईजी

आईजी रामगोपाल गर्ग ने कहा कि डायल-112 सेवा को अब प्रदेश के सभी 33 जिलों में विस्तारित किया गया है। इसमें पुलिस के साथ-साथ फायर एवं एम्बुलेंस सेवाओं को भी जोड़ा गया है, जिससे लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर त्वरित सहायता मिल रही है। उन्होंने बताया कि कई बार प्रसव जैसी आपात स्थितियों में भी डायल-112 टीम ने समय पर पहुंचकर मदद की है। व्हाट्सएप सुविधा शुरू होने से आमजन के लिए सहायता प्राप्त करना और आसान होगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि नई डायल-112 वाहन सेवा से जिले में आपातकालीन सेवाओं की कार्यक्षमता और बेहतर होगी। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण अंचलों में भी त्वरित सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित यह व्यवस्था नागरिकों के बीच सुरक्षा और भरोसे की भावना को और मजबूत करेगी। एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा कि डायल-112 सेवा पुलिस की त्वरित कार्रवाई प्रणाली की पहचान बन चुकी है। महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, फायर एवं एम्बुलेंस सेवाओं के समन्वय से लोगों को तत्काल सहायता मिल रही है। नई वाहनों के जुड़ने से रिस्पॉन्स टाइम में और सुधार आएगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाओं की पहुंच मजबूत होगी।

न्यूज गैलरी

कांग्रेस का पेट्रोल-डीजल मूल्य वृद्धि पर विरोध-प्रदर्शन आज

सीपत/नवप्रदेश। पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीपत द्वारा आज शुक्रवार 22 मई को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर संगठन ने व्यापक तैयारी पूरी कर ली है और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है। ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र धीवर ने बताया कि इससे पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीपत की प्रथम मासिक बैठक आज दोपहर 1 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सीपत में आयोजित होगी। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक के पश्चात शाम 3 बजे सीपत पेट्रोल पंप के समीप पेट्रोल-डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि और बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया, जिलाध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र धीवर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीपत अध्यक्ष राजेंद्र धीवर ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है।

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू स्वच्छ भारत मिशन-उरबन 2.0 की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में हुए शामिल

सीवेज ट्रीटमेंट व अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणालियों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करें राज्य: तोखन

बिलासपुर/नवप्रदेश। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता तथा आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू की उपस्थिति में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन-उरबन की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दूसरे दिन एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, लेगेसी वेस्ट रिमेडिएशन, शहरी स्वच्छता, स्वच्छ सर्वेक्षण, उत्तर-पूर्वी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की चुनौतियों तथा नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक के दौरान राज्य मंत्री तोखन साहू ने सीवेज उपचार संयंत्र के प्रभावी संचालन एवं उपयोग की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के प्रवास के दौरान यह देखा गया कि कई स्थानों पर सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित होने के बावजूद उनका समुचित उपयोग नहीं हो रहा है, जिसके कारण बिना उपचारित जल नदियों में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने राज्यों एवं शहरी निकायों को निर्देशित किया कि उपलब्ध अधोसंरचना की कार्यक्षमता सुनिश्चित करते हुए सीवेज प्रबंधन प्रणालियों का प्रभावी संचालन किया जाए। बैठक में विभिन्न राज्यों द्वारा शहरी स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की भी सराहना की गई। छत्तीसगढ़ के स्वच्छता मॉडल को 100 प्रतिशत महिला नेतृत्व आधारित मॉडल के रूप में प्रशंसित किया गया, वहीं रायपुर शहर को जीरो डंप-साइट जोन घोषित किए जाने तथा वैज्ञानिक लैंडफिल प्रबंधन एवं लेगेसी वेस्ट रिमेडिएशन की अभिनव पहलों के लिए विशेष रूप से सराहा गया। सत्र के दौरान अमृतसर द्वारा मौसमी एवं तैरते कचरे के प्रबंधन, नवी मुंबई द्वारा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल, तथा पटना द्वारा द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी शहरों में वित्तीय व्यवहार्यता से जुड़ी चुनौतियों एवं एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के अनुभव साझा किए गए। 'स्वच्छता तक पहुंच, खुले में शौच मुक्त वातावरण (ओडीएफ++) की ओर संक्रमण और मशीनीकृत गाद निकासी' विषयक सत्र में उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने 'मैनहोल से मशीन होल तक' की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए मैनहोल में मानव प्रवेश समाप्त करने हेतु तकनीक आधारित व्यवस्थाओं एवं संभावित कानूनी उपायों पर बल दिया।

मैकेनाइज्ड डीस्लजिंग, कौशल विकास को बढ़ावा

मध्यप्रदेश ने सुरक्षित स्वच्छता संबंधी नीतिगत पहलों, देवास ने मैकेनाइज्ड सीवर सफाई मॉडल, ओडिशा ने गरिमा पहल के अंतर्गत स्वच्छता कर्मियों के कल्याण, तथा पंजाब ने ओडीएफ++ शहरों के निर्माण हेतु एकीकृत स्वच्छता प्रबंधन के अनुभव साझा किए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने जानकारी दी कि नमस्ते योजना के माध्यम से स्वच्छता कर्मियों के लिए मैकेनाइज्ड डीस्लजिंग, कौशल विकास, सुरक्षा उपकरण एवं वित्तीय सहायता को बढ़ावा दिया जा रहा है। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल एवं राज्य मंत्री तोखन साहू ने उत्तर-पूर्वी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र विशेष की चुनौतियों एवं समाधान पर भी विस्तृत चर्चा की। इसमें विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यटन आधारित स्वच्छता मॉडल एवं सतत शहरी विकास की रणनीतियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्रीय मंत्रियों ने शहरी स्वच्छता एवं सफाई अभियानों को सफल बनाने के लिए मजबूत राजनीतिक नेतृत्व एवं सक्रिय जनभागीदारी को अत्यंत आवश्यक बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आह्वान को भी दोहराया, जिसमें कोविड काल की उपयोगी व्यवस्थाओं—जैसे घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं, वर्चुअल मीटिंग एवं पेट्रोल-डीजल की खपत में कमी—को पुनः अपनाने की बात कही गई है, ताकि पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण को गति मिल सके। राष्ट्रीय समीक्षा बैठक ने स्वच्छ भारत मिशन-रबन 2.0 के अंतर्गत स्वच्छ, हरित एवं सतत शहरी विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ किया।

अवैध उत्खनन पर कार्रवाई, 2 पोकलेन एक जेसीबी मशीन सहित 20 वाहन जब्त

बिलासपुर/नवप्रदेश। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश एवं उप संचालक खनिज के मार्गदर्शन में जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज अमले ने विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाकर 2 पोकलेन मशीन, 1 जेसीबी मशीन तथा 20 वाहनों को जब्त किया है। उप संचालक खनिज प्रशासन श्री किशोर गोलघाटे ने बताया कि ग्राम महमंद (सीपत क्षेत्र) में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान बिना वैध अभिवहन पास के रेत परिवहन करते पाए जाने पर दो हाईवा वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की गई। इनमें से एक वाहन को जांच चौकी लावर लाया गया, जबकि दूसरे वाहन का चालक वाहन को सड़क के बीच छोड़कर चाबी लेकर फरार हो गया। वाहन मालिक को तत्काल सूचना दी गई, लेकिन उसके उपस्थित नहीं होने पर संबंधित वाहन स्वामी के खिलाफ थाना तोरवा में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग द्वारा 7 मई से 20 मई तक चकरभाठा, बोदरी, सकरी, बेलगहना, रतनखण्डी, करहीकछार, सलका, पोड़ी, महमंद, लालखदान, मंगला, मस्तूरी, चौरमट्टी एवं लखराम सहित विभिन्न क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया गया।

कार्यालय कलेक्टर, जिला-सक्ती एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक /10/अ-82/2025-26 सक्ती, दिनांक 11/05/26

चूँकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की **साराडीह बैराज के डूबान क्षेत्र में प्रभावित ग्राम सकराली (पूरक प्रकरण)** हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा-19 के तहत् यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

- अनुसूची -

भूमि का वर्णन -
1. जिला - सक्ती
2. तहसील - डभरा
3. ग्राम - सकराली/ प.ह.नं. - 26
4. भूमि का क्षेत्रफल - 8.832 हेक्टेयर

खसरा नं.	रकबा (हे.में.)	खसरा नं.	रकबा (हे.में.)	खसरा नं.	रकबा (हे.में.)
911	0.336	1044/3	0.109	2115/3	0.709
956/1	0.166	1044/4	0.101	2115/4	0.296
956/2	0.154	1093/1	0.101	2115/5	0.101
956/3	0.202	1428/7	0.324	2115/9	0.219
958/2	0.121	1428/8	0.263	2115/10	0.458
1000/2	0.073	1428/9	0.174	2115/12	0.085
1000/4	0.121	1433/1	0.032	2118/4	0.096
1000/7	0.053	1436/2	0.065	2119/1	0.573
1000/21	0.142	1441/1/क	0.370	2119/3	0.024
1000/10	0.028	2113/2	0.150	2122/1	0.526
1000/11	0.024	2113/3	0.146	2131/3	0.388
1000/13	0.020	2113/8	0.344	2131/4	0.388
1000/14	0.040	2113/10	0.077	**52**	**8.832**
1000/18	0.040	2113/11	0.255		
1000/20	0.085	2113/18	0.061		
1001/7	0.085	2113/20	0.020		
1001/8	0.020	2113/21	0.077		
1001/10	0.142	2113/24	0.125		
1001/11	0.081	2113/27	0.060		
1001/5	0.081	2115/2	0.101		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(विनय कुमार कश्यप)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी डभरा

(अमृत विकास तोपनो)
कलेक्टर
जिला-सक्ती (छ.ग.)
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जी- 262700877/2

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

अनुलग्नक-अ

कार्य विवरण: पांच (05) वर्षों की अवधि के लिए कोरबा (KRBA) रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्लेटफार्मों और स्टेशन परिसर के भीतर उपयुक्त स्थानों पर साइनबोर्ड, पिलर कियोस्क, ग्लो साइनबोर्ड/बैकलिट, हैंगिंग स्टैटिक बोर्ड के रूप में वाणिज्यिक विज्ञापन (गैर- डिजिटल) प्रदर्शित करने का लाइसेंस, जिसका कुल प्रदर्शन क्षेत्र 2000 वर्ग फुट है, लाइसेंस धारक के खर्च का लाइसेंस एवं पांच (05) वर्षों की अवधि के लिए चांपा (CPH) रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्लेटफार्मों और स्टेशन परिसर के भीतर उपयुक्त स्थानों पर साइनबोर्ड, पिलर कियोस्क, ग्लो साइनबोर्ड/बैकलिट, हैंगिंग स्टेटिक बोर्ड के रूप में वाणिज्यिक विज्ञापन (गैर- डिजिटल) प्रदर्शित करने का लाइसेंस, लाइसेंस धारक के खर्च पर आबंटन हेतु ई-नीलामी आमंत्रित की गई है। कैटलॉग पहले ही दिनांक 08.05.2026 को आईआरईपीएस वेबसाइट (https://ireps.gov.in) पर प्रकाशित किया जा चुका है। विवरण इस प्रकार हैं:-

कैटेलॉग क्रमांक	श्रेणी	नीलामी दिनांक एवं समय	लॉट क्रमांक	लॉट विवरण	अनुबंध अवधि
ADVT-CPH-KRBA	Advertising on Station Premises (Non-Digital)	25.05.2026 13:30	ADVT-BSP-KRBA-OSN-195-26-1	कोरबा (KRBA) रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्लेटफार्मों और स्टेशन परिसर के भीतर उपयुक्त स्थानों पर साइनबोर्ड, पिलर कियोस्क, ग्लो साइनबोर्ड/बैकलिट, हैंगिंग स्टैटिक बोर्ड के रूप में वाणिज्यिक विज्ञापन (गैर- डिजिटल) प्रदर्शित करने का लाइसेंस, जिसका कुल प्रदर्शन क्षेत्र 2000 वर्ग फुट है, लाइसेंस धारक के खर्च का लाइसेंस।	1826 दिन
			ADVT-BSP-CPH-OSN-152-26-2	चांपा (CPH) रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्लेटफार्मों और स्टेशन परिसर के भीतर उपयुक्त स्थानों पर साइनबोर्ड, पिलर कियोस्क, ग्लो साइनबोर्ड/बैकलिट, हैंगिंग स्टेटिक बोर्ड के रूप में वाणिज्यिक विज्ञापन (गैर- डिजिटल) प्रदर्शित करने का लाइसेंस, लाइसेंस धारक के खर्च पर लाइसेंस।	

सहायक वाणिज्य प्रबंधक (माल भाड़ा-II)
द.पू.म.रेलवे, बिलासपुर

सीपीआर/10/128

सुरक्षा: रेल परिचालन की सुरक्षा व गति में सुधार के उद्देश्य से किया जा रहा कार्य

गोंदिया स्टेशन यार्ड में पॉइंट परिवर्तन कार्य, कुछ ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

बिलासपुर/नवप्रदेश। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल अंतर्गत गोंदिया यार्ड में अधोसंरचना उन्नयन कार्य के तहत पॉइंट क्रमांक 11बी/112 को 52 किलोग्राम रेल सेक्शन से 60 किलोग्राम रेल सेक्शन में परिवर्तित किए जाने हेतु 21 एवं 22 मई को विशेष ट्रैफिक एवं इंजीनियरिंग ब्लॉक लिया जाएगा। यह कार्य रेल परिचालन की सुरक्षा एवं गति में सुधार के उद्देश्य से किया जा रहा है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोनों दिनों में कुल 08 घंटे 30 मिनट का ब्लॉक लिया जाएगा। इसमें इंजीनियरिंग विभाग द्वारा स्विच नवीनीकरण एवं पॉइंट सेटिंग सहित आवश्यक कार्य हेतु 06 घंटे का ब्लॉक रहेगा। इसके उपरांत सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग द्वारा वायरिंग डिस्कनेक्शन, परीक्षण एवं संबंधित तकनीकी कार्यों के लिए 02 घंटे का ब्लॉक लिया जाएगा। साथ ही विद्युत विभाग द्वारा ओएचई परीक्षण हेतु अतिरिक्त 30 मिनट का ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान गोंदिया स्टेशन की लाइन क्रमांक 06 एवं 07 पर ट्रेनों का आगमन एवं प्रस्थान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अप दिशा की ट्रेनों का लाइन क्रमांक 7, 8, 9 एवं 10 पर अप मेन लाइन से प्रवेश नहीं किया जाएगा। ओएचई परीक्षण अवधि में विभिन्न विद्युत रेलगाड़ियों की आवाजाही पर भी अस्थायी प्रतिबंध लागू रहेगा। इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात डाउन मेन लाइन पर ट्रेनों की गति बढ़ाकर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की जा सकेगी, जिससे रेल संचालन अधिक सुरक्षित एवं सुगम होगा। रद्द गाड़ियों में गाड़ी संख्या 68817 गोंदिया-गढ़ा मेमू पैसेंजर, 21 एवं 22 मई 2026 को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 68818 गढ़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर, 21 एवं 22 मई 2026 को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर, 21 एवं 22 मई 2026 को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर, 22 एवं 23 मई को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 68721 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर, 21 मई को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 68723 डोंगरगढ़-गोंदिया मेमू पैसेंजर, 21 मई को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 68724 गोंदिया-दुर्ग मेमू पैसेंजर, 22 मई 2026 को रद्द रहेगी। रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि यात्रा से पूर्व अपनी गाड़ी की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर यात्रा करें। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद है।

ठेका कर्मचारी की संदिग्ध मौत

एमजीआर रेल लाइन पर मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस

सीपत/नवप्रदेश। एनटीपीसी के सीपत परियोजना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। एनटीपीसी सीपत के एमजीआर रेल लाइन में सुबह लगभग 11:45 बजे सीआईएसएफ के जवानों को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। घटना की जानकारी तत्काल स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। पुलिस की मौजूदगी में मृतक की शिनाख्त अमृतांशु सिंह पिता धनंजय सिंह के रूप में हुई। वह मूल रूप से बिहार राज्य के रोहतास जिले के काराकाट थाना अंतर्गत ग्राम बेलवाई निवासी था। वर्तमान में वह एनटीपीसी सीपत में स्टेज-3 निर्माण कार्य कर रही मेसर्स आरवीपीआर एजेंसी में स्टाफ के रूप में कार्यरत था। घटना के बाद परियोजना क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों में शोक का माहौल है।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
"सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन" सेक्टर-24, कयाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर-492018
फोन-0771-2990592, email-mdcgmandiboard@gmail.com, website-www.agriportal.cg.nic.in

क्र./बी-6/मंडी कांकेर/57-02/26-27/1228 रायपुर, दिनांक- 21/05/ 2026

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना
Main Portal:http://eproc.cgstate.gov.in

कृषि उपज मंडी समिति कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर अंतर्गत छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड द्वारा ऑनलाईन निविदाएँ छ.ग. लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत, सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारो से प्रपत्र 'अ' प्रतिशत दर पर अधोलिखित निर्माण कार्यों हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती है -

ऑनलाईन निविदा डालने की अंतिम तिथि - 15.06.2026
फिजिकल सबमिशन की अंतिम तिथि - 22.06.2026

क्र.	कार्य का नाम/स्थल	अनुमानित लागत (लाख में)	एस.ओ.आर. विवरण
1	मंडी समिति कांकेर के **उप मंडी प्रांगण अमोड़ा** में 200 मे. टन गोदाम 01 नग निर्माण कार्य। **(तृतीय आमंत्रण)**	12.11	लो.नि.वि. भवन/विद्युत कार्य हेतु दिनांक 01.01.2015 / 01.07.2015 से प्रभावशील एस.ओ.आर. पर।
2	मंडी समिति कांकेर के **उपमंडी प्रांगण सरोना** में बाउण्ड्रीवाल 290 रनिंग मीटर सह 04 नग गेट निर्माण। **(द्वितीय आमंत्रण)**	21.81	
3	**मूल मंडी प्रांगण कांकेर** में एम.आई.जी. टाईप आवासीय भवन (भूतल एवं प्रथम तल में कुल 06 नग), 200 मि.टन व 150 मि. टन क्षमता गोदाम, सी.सी. सड़क (1330 वर्ग मी.), पूर्व निर्मित 21 नग सेण्ड्री शॉप का मरम्मत कार्य तथा अमोड़ा लेम्पस में 200 मि.टन गोदाम निर्माण कार्य।	156.19	लो.नि.वि. भवन/विद्युत कार्य हेतु दिनांक 01.01.2015 / 01.07.2015 एवं सड़क कार्य दिनांक 01.01.2025 से प्रभावशील एस. ओ. आर. पर।

उपरोक्त निर्माण कार्यो की निविदा की सामान्य एवं विशेष शर्ते, धरोहर राशि, निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल http://eproc.cgstate.gov.in वेबसाईट पर निर्धारित तिथि तक देखे जा सकते है।

सही/-
सचिव
कृषि उपज मंडी समिति कांकेर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

संवाद- 47895/2

सही/-
भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति कांकेर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर मंडल, बिलासपुर

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना
Portal: http://eproc.cgstate.gov.in

छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर में निम्नलिखित कार्य नवीन ई-पंजीयन में पंजीकृत ठेकेदार हेतु **दिनांक 08.06.2026** तक निविदा आमंत्रित की जाती है-

क्र.	नि.आ.सू.क्र./ दिनांक	कार्य का नाम	लागत (लाख में)
1	34	बी.टी.आई. चौक नहर पुल से खोखसा आर.ओ.बी. सड़क तक विभाजक और आर. सी.सी. नाली लं. 1310 मी. का निर्माण कार्य। **प्रथम आमंत्रण। चांपा संभाग, चांपा। मद संख्या-8443 जमा मद**	50.88
2	35	जिला खनिज संस्थान न्यास मद (डी.एम.एफ.) के अंतर्गत लाईवलीहुड कॉलेज परिसर जांजगीर स्थित 500 सीटर ऑडिटोरियम भवन जांजगीर के आंतरिक एवं बाह्य रेनोवेशन का कार्य। **प्रथम आमंत्रण। चांपा संभाग, चांपा। मद संख्या - 8443 जमा मद**	100.00
3	36	जिला खनिज संस्थान न्यास मद (डी.एम.एफ.) के तहत् अर्जुनी से करूमहु मार्ग के कि.मी. 1/2 से 2/10 = 2.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण कार्य। **प्रथम आमंत्रण। चांपा संभाग, चांपा। मद संख्या - 8443 जमा मद**	74.21
4	37	जिला खनिज संस्थान न्यास मद (डी.एम.एफ.) के तहत् जांजगीर बायपास मार्ग के कि.मी. 1/2 से 2/4 (100) = 1.30 कि.मी. में मजबूतीकरण एवं डामर नवीनीकरण कार्य। **प्रथम आमंत्रण। चांपा संभाग, चांपा। मद संख्या - 8443 जमा मद**	77.26
5	38	जिला खनिज संस्थान न्यास मद (डी.एम.एफ.) के तहत् जांजगीर-केरा-शिवरीनारायण मार्ग के कि.मी. 3/6 से 3/10 = 0.60 कि.मी. में डामर नवीनीकरण कार्य। **प्रथम आमंत्रण। चांपा संभाग, चांपा। मद संख्या - 8443 जमा मद**	73.68
6	39	जिला खनिज संस्थान न्यास मद (डी.एम.एफ.) के तहत् तरौद तागा धाराशिव (मुख्य जिला मार्ग) मार्ग के कि.मी. 2/4 से 3/2 = 1.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण कार्य। **प्रथम आमंत्रण। चांपा संभाग, चांपा। मद संख्या - 8443 जमा मद**	71.90
7	40	जिला खनिज संस्थान न्यास मद (डी.एम.एफ.) के तहत बोड़सरा सिवनी मार्ग के कि.मी. 1/2 से 4/6 = 3.60 कि.मी. में डामर नवीनीकरण कार्य। **प्रथम आमंत्रण। चांपा संभाग, चांपा। मद संख्या - 8443 जमा मद।**	66.85

निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखें जा सकते है।

अधीक्षण अभियंता
लो.नि.वि., बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर

जी-262700855/7

ST. XAVIER'S HIGH SCHOOL
(A Unit of St. Xavier's Chain of Schools)
Congratulations
Class XII CBSE Board Result (AISSCE-2026)
VYAPAR VIHAR, BILASPUR CBSE AFFILIATION NO. - 3330223
RAYA KHAN 97.8 %
ANUSHA EKKA 97 .6 %
NATASHA DHAMECHA 97%
EVA OSHEEN MASIH 96.6 %
RAVISHANKAR 95.4 %
NANDITA RATHORE 94.8 %
ROHIT MATLANI 94.6 %
ATHARVA TIWARI 94 %
SARVASVA SHRIVASTAVA 93.2 %
DEV PRATAP SINGH 93.2 %
JAGRITI PATEL 92.4 %
AKSHAT TANDON 92.4 %
ANJALI RAJPUT 92.2 %
ANSH PANJWANI 91.6 %
KURELLA RISHITA 91.6 %
LAKSHYA DINDOURE 91.4 %
PRATTYUSH KESHARWANI 91%
ARSHI JUNAID 90.8 %
HIMANSHU MANJHI 89.8 %
AKSHITA GUPTA 89.6 %
MIMANSA CHITRAKAR 89.6 %
BHARNI, BILASPUR CBSE AFFILIATION NO. - 3330044
ANVESHA AGRAWAL 97.%
ANSHIKA GUPTA 94 %
TEJAS VILAS SAHU 93.6 %
PRASHANT SENDREY 92.2 %
ARUNA SINGH KANWAR 92 %
SAKSHAM SHARMA 91.6 %
AANYA GUPTA 91%
P. ANSHIKA RAO 90.4 %
SAUMYA TEKAM 89.4 %
MAMTA MARKAM 89.2%
MUNGELI CBSE AFFILIATION NO. - 3330182
ANANT UPADHYAY 96 %
RANU LEDWANI 96 %
VAIBHAVI KASHYAP 93.6%
AARAV SONI 92.2 %
HARSHITA TIWARI 92 %
SHOURYA DEEP 91.2 %
AKASH BANJARE 90.6%
ANKURI SINGH 90.2 %
JANHAVI THAKUR 89.6 %
VAISHALI RAJESHWANI 89.4 %
ADMISSION OPEN
SCHOLARSHIP FOR NEW ADMISSION IN CLASS XI
DESIGNED FOR BOARD + COMPETITIVE EXCELLENCE
XI & XII School Timing "7:00 AM – 11:30 AM" *
"More Time for Self-Study & Competitive Preparation"
BHARNI (HOSTEL)
9826862004, 7773085667
In front of CRPF Camp, Kota Road, Bharni, Bilaspur (C.G.)
* VYAPAR VIHAR
07752-353557, 9630004301
In-front of ITC office, Vyapar Vihar, Bilaspur (C.G.)
MUNGELI
9826129896, 7999117127
Sai Mangalam, Pandariya Road, Mungeli (C.G.)

चीन में कुदरत की दोहरी मार, लियूझोउ शहर में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप

बीजिंग/ए.। मई का महीना दक्षिण और पूर्वी एशिया के लिए मौसम के दो चरम और विपरीत रूपों को लेकर आया है। जहां एक ओर भारत भीषण हीटवेव की चपेट में है. वहीं दूसरी चीन इस समय कुदरत के दोहरे कोहराम से कराह रहा है. चीन के दक्षिणी और मध्य प्रांतों में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई है. इसके ठीक पहले दक्षिण चीन के गुआंशी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र में एक के बाद दो शक्तिशाली भूकंप के झटकों ने धरती को हिला कर रख दिया। चीन में आपदाओं की शुरुआत दक्षिणी क्षेत्र में स्थित गुआंशी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र से हुई. यहां के लियूझोउ शहर में 18 मई को तड़के सुबह 5.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने सोते हुए लोगों को झंझोड़ कर रख दिया।

इस भूकंप का केंद्र जमीन से महज 8 किलोमीटर की गहराई पर था, जिसके कारण बेहद तेज और विनाशकारी झटके महसूस किए गए. भूकंप के कारण लियूझोउ शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में 13 इमारतें पूरी तरह जमींदोज हो गईं और दर्जनों अन्य मकानों में गंभीर दरारें आ गईं। इस आपदा में 2 लोगों की मौत हो चुकी है. मलबे के नीचे दबे कुछ और लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।

तमिलनाडु में विजय मंत्रिमंडल का विस्तार

चेन्नई/ए.। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बृहस्पतिवार को मंत्री पद की शपथ ले रहे कांग्रेस नेता एस राजेश कुमार को टोकते हुए उन्हें लिखित शपथ ही पढ़ने को कहा। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार किल्लियूर से विधायक हैं और वह आज शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रियों में शामिल रहे। लोक भवन में राज्य के मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के दौरान जब कुमार लिखित शपथ पढ़ रहे थे, तभी अचानक वह कांग्रेस नेताओं कामराज, राजीव गांधी और राहुल गांधी की प्रशंसा में नारे लगाने लगे। इसके बाद राज्यपाल ने टोकते हुए कुमार से कहा, ÷यह आपकी शपथ का हिस्सा नहीं है। कुमार के शपथ लेने के कुछ ही मिनट बाद सलेम दक्षिण से टीवीके विधायक ए विजय तमिलन पार्थिबन ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मंच पर उपस्थित पार्टी नेता और मुख्यमंत्री सी जोसफविजय की प्रशंसा करते हुए नारे लगाए। श्रीपेरंबुदूर से टीवीके सदस्य थेन्नारासु ने भी मंत्री के रूप में अपनी शपथ लेते हुए कहा कि वह पार्टी और उसके नेता के प्रति निष्ठावान रहेंगे।

विजय ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्री राजेश कुमार और पी. विश्वनाथन ने चेन्नई के लोक भवन में पद की शपथ ली। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने नव नियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई। यह मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद में 23 विधायकों को शामिल करने के प्रस्ताव के बाद हुआ, जिसे तमिलनाडु के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 35 है। इस विस्तार के साथ अब तक 33 मंत्रियों ने शपथ ली है। कुल मंत्रिपरिषद में से 21 विधायक तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) से और 2 कांग्रेस से हैं।

शुभेंदु सरकार में घुसपैठ पर नकेल बीएसफ को 27 किमी जमीन, लगाए जाएंगे कंटीले तार

■ बीएसएफ ने सरकार के फैसले की सराहना की

मुर्शिदाबाद/ए.। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए बीएसएफको 27 किलोमीटर जमीन सौंप दी है। गुरुवार को राज्य सचिवालय नबान्ना में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया की शुरुआत की।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

राज्य के मुर्शिदाबाद और मालदा जिले इस समय सुरक्षा और राजनीतिक दोनों वजहों से बेहद अहम माने जा रहे हैं। इन्हीं संवेदनशील इलाकों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सीमा पर फेंसिंग और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया।

दरअसल, मुर्शिदाबाद और मालदा दोनों जिले सीधे बांगलादेश सीमा से जुड़े हैं और यहां बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुर्शिदाबाद में मुस्लिम

आबादी करीब 66 प्रतिशत और मालदा में 51 प्रतिशत है। भाजपा लंबे समय से इन इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही है। पार्टी का आरोप है कि अवैध घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए स्थानीय स्तर पर पहचान दिलाई जाती रही है।

हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के शुरुआती फाइनल आंकड़ों में भी मुर्शिदाबाद और मालदा चर्चा में रहे। करीब 60 लाख से ज्यादा लंबित मतदाताओं में लगभग एक-तिहाई सिर्फ इन दो सीमावर्ती जिलों से हैं। मुर्शिदाबाद में ऐसे मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा 11.01 लाख बताई गई, जबकि मालदा में यह आंकड़ा 8.28 लाख है।

पश्चिम बंगाल की सीमा लगभग 2,200 किलोमीटर तक बांग्लादेश से लगती है, जबकि भारत-बांग्लादेश की कुल सीमा करीब 4,000 किलोमीटर लंबी है। इनमें से लगभग 1,600 किलोमीटर हिस्से में पहले ही फेंसिंग की जा चुकी है, जबकि करीब 600 किलोमीटर क्षेत्र अब भी बिना बाड़ के है।

सरकार की ओर से इस बार कुल 27 किलोमीटर क्षेत्र के लिए जमीन सौंपी गई है। इसमें 18 किलोमीटर हिस्से में कंटीले तारों की बाड़ लगाई जाएगी, जबकि नौ किलोमीटर क्षेत्र बीएसएफचौकियों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए इस्तेमाल होगा।

वहीं, बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीन कुमार ने राज्य सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा अभियानों में जिस सहयोग की लंबे समय से जरूरत थी, वह अब नई सरकार के तहत मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर लगाया आरोप

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर असहयोग के जरिए सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीमा पर बाड़बंदी राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धर्मांतरण और अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़े अपराधों का हवाला देते हुए कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा को मजबूत करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में और जमीन भी बीएसएफ को हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया का खर्च केंद्र सरकार और बीएसएफद्वारा उठाया जाएगा।

असम विधानसभा के दूसरी बार स्पीकर बने रंजीत कुमार दास

गुवाहाटी। असम विधानसभा को गुरुवार को नया अध्यक्ष मिल गया। चार बार के भाजपा विधायक रंजीत कुमार दास को सर्वसम्मति से 16वीं असम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। प्रोटेम स्पीकर चंद्र मोहन पटवारी ने सदन में घोषणा करते हुए बताया कि रंजीत कुमार दास के समर्थन में तीन नामांकन दाखिल किए गए थे। उनके खिलाफ किसी अन्य विधायक ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जिसके बाद उन्हें निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष घोषित कर दिया गया।

यह दूसरी बार है जब रंजीत कुमार दास असम विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले 2016 में भाजपा की पहली सरकार बनने के दौरान भी उन्होंने स्पीकर पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उस समय राज्य में पहली बार भाजपा सत्ता में आई थी और दास को विधानसभा संचालन की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

रंजीत कुमार दास असम की भवानीपुर-सोरभोग विधानसभा सीट से विधायक हैं। वह 2011 से लगातार चार बार विधानसभा चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं। उन्होंने राज्य की राजनीति में संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं।

सीएम सरमा के पहले कार्यकाल में रहे कैबिनेट मंत्री

दास मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के पहले कार्यकाल (2021-2026) में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने भाजपा की असम इकाई के अध्यक्ष के रूप में भी पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया। उनके दोबारा विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने को भाजपा नेतृत्व और संगठन में उनके लंबे अनुभव का अहम संकेत माना जा रहा है।

नीट पेपर लीक मामलाः कांग्रेस का जयपुर में हल्लाबोल

■ बैरिकेडिंग पर चढ़े कार्यकर्ता, पुलिस ने चलाई वाटर कैनन

■ डोटासरा ने एनटीए भंग करने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की

किशनगंज। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार को कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय के खिलाफजोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से पैदल मार्च करते हुए शहीद स्मारक के रास्ते बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़े। प्रदर्शन के चलते पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते में कई जगह बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी मुख्यालय की ओर बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।

नीट का पेपर कहां मिलेगा, बीजेपी के बाड़े में के लगे नारे

प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफजमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने "नीट का पेपर कहां मिबैरिकेडिंग पर चढ़े कार्यकर्ता, पुलिस ने चलाई वाटर कैनन लेगा, बीजेपी के बाड़े में" जैसे नारे लगाए, जिससे माहौल और गरमा गया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर गंभीर सवाल उठाए। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, ये लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक के किंगपिन हैं। इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड धर्मेंद्र प्रधान ही हैं। पैसे कमाए जा रहे हैं और सरकारों को अस्थिर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने 2024 में ही कहा था कि नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। ये लोग हमें भाषण दिया करते थे, लेकिन खुद ही बेईमान और भ्रष्ट निकले।

बांद्रा में बवाल को लेकर 10 के खिलाफ एफआईआर, हुई थी हिंसक झड़प

मुंबई/ए.। मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हिंसक झड़प हो गई। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में दस नामजद आरोपियों समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा 100-150 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के कई धाराओं में मामला दर्ज किया है।

इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 109 भी लगाई है। पुलिस ने बताया कि, 20 मई को बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास गरीब नगर क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाने का अभियान चलाया जा रहा था। यह कार्रवाई मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के तहत की जा रही थी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुंबई पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, होम गार्ड और अन्य कर्मचारी मौके पर तैनात थे। जैसे की तोड़फोड़ का काम शुरू हुआ वैसे ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन भीड़ ने कार्रवाई रोकने की कोशिश की। कुछ ही देर में हालात तनावपूर्ण हो गए और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और अन्य वस्तुएं फेंकनी शुरू कर दीं।

महंगाई का असरः खपत की रफ्तार थामी तो विकास दर को लग सकता है झटका

नई दिल्ली/ए.। भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत कारखाने नहीं बल्कि बाजार हैं। गांव की किराना दुकान से लेकर शहर के मॉल तक जो खर्च होता है, वही आर्थिक विकास की असली धड़कन है। यही वजह है कि उपभोग में थोड़ी भी सुस्ती अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दे सकती है। वह भी ऐसे समय में, जब देश पश्चिम एशिया में जारी तनाव, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, विदेशी निवेशकों की लगातार पूंजी निकासी, डॉलर की तुलना में रुपये में रिकॉर्ड गिरावट और बढ़ते आयात बिल जैसे संकटों से जूझ रहा है।

दरअसल, भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा घरेलू खर्च है।?घरेलू जीडीपी में निजी खपत की हिस्सेदारी करीब 57 फीसदी है। यानी लोगों की जेब, खरीदारी और

भरोसा ही विकास का सबसे बड़ा इंजन है। दिसंबर, 2025 तिमाही के दौरान निजी खपत बढ़कर जीडीपी के 57.5 फीसदी तक पहुंच गई। चिंता इसलिए बढ़ी है, क्योंकि पिछले तीन महीनों में कई एजेंसियों ने भारत की वृद्धि दर के अनुमान घटाए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 के लिए विकास दर अनुमान को 6.6 फीसदी से घटाकर 6.4 फीसदी कर दिया है। मूडीज रेटिंग्स ने भी 2026 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.8 फीसदी से घटाकर 6.0 फीसदी किया है। वहीं, इंडिया रेटिंग्स ने पश्चिम एशिया तनाव और अल-नीनो के जोखिम को देखते हुए 2026-27 में वृद्धि दर 6.7 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। यानी भारत मौजूदा संकट में भी तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था तो बना हुआ है, लेकिन बाहरी झटकों से अछूता नहीं है। रोजमर्रा के सामान साबुन, तेल, बिस्कुट, शैंपू, चाय, पैकेज्ड फूड...देश की खपत का सबसे तेज संकेत देते हैं। इसी मोर्चे पर चेतावनी दिख रही है।

वर्ल्डपैनल बाय न्यूमरेटर के मुताबिक, जनवरी-मार्च तिमाही में एफएमसीजी वैल्यू ग्रोथ 13.1 फीसदी और वॉल्यूम ग्रोथ 5.4 फीसदी रही। एजेंसी का अनुमान है कि 2026 में वॉल्यूम ग्रोथ 5 फीसदी तक जा सकती है, अगर कच्चा तेल स्थिर रहे और मानसून साथ दे। महंगाई और मौसम का दबाव बना रहा, तो एफएमसीजी की वृद्धि दर 3-4 फीसदी तक सिमट सकती है।

अंडर-23 वनडे टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा

नई दिल्ली/ए.। आगामी 2026/27 घरेलू सीजन में अंडर-23 पुरुषों के वनडे टूर्नामेंट की जगह टी20 फॉर्मेट लेगा, जबकि कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी विजेता बनाम शेष भारत का मैच घरेलू सीजन के कैलेंडर में वापस आ जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को यह जानकारी दी। 2026-27 के घरेलू सीजन में पुरुषों और महिलाओं के क्रिकेट में कई आयु-वर्ग श्रेणियों में कुल 1,788 मैच खेले जाएंगे। इस सीजन की शुरुआत प्रतिष्ठित दलीप ट्रॉफी से होगी, जो 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में खेली जाएगी। इसके बाद 1 अक्टूबर से ईरानी कप की शुरुआत होगी। यह संभवतः जम्मू या श्रीनगर में खेला जाएगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर अभी रणजी ट्रॉफी के मौजूदा विजेता हैं, जिसे उन्होंने इस साल की शुरुआत में हुबली में जीता था। रणजी ट्रॉफी दो-चरणों वाले फॉर्मेट में जारी रहेगी। एलीट ग्रुप में 32 टीमें चार ग्रुप में होंगी और प्लेट ग्रुप में छह टीमें सामान्य 'होम-एंड-अवे' फॉर्मेट में खेलेंगी। कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी विजेता बनाम शेष भारत का मुकाबला 1-4 अक्टूबर को फिर से खेला जाएगा। मेंस अंडर-23 स्टेट 'ए' ट्रॉफी को टी20 फॉर्मेट में बदलने के अलावा, विजी ट्रॉफी वनडे प्रतियोगिता के बजाय टी20 फॉर्मेट में खेली जाएगी। कूच बिहार ट्रॉफी के नॉकआउट चरण बेंगलुरु और मैसूर में आयोजित किए जाएंगे, ताकि जनवरी के दौरान मैचों में प्रतिस्पर्धी संतुलन बना रहे। विजय मर्चेंट ट्रॉफी (अंडर-16) को बेहतर शेड्यूलिंग और खिलाड़ियों की तैयारी के लिए नवंबर-जनवरी के समय में आगे बढ़ा दिया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एलीट ग्रुप के लीग मैच 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक विशाखापत्तनम, मुंबई, कोलकाता और मोहाली में होंगे।

फिल्म 'बंदर' का ट्रेलर रिलीज, जेल में कैद हुए बॉबी देओल

मुंबई/ए.। बॉबी देओल करियर की दूसरी पारी में लीक से हटकर किरदार कर रहे हैं। अनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म 'बंदर' में बॉबी देओल एक बार फिर से इंटेंस रोल में दिख रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में उनके किरदार में कई शेड्स नजर आ रहे हैं।

फिल्म 'बंदर' के ट्रेलर की शुरुआत बॉबी देओल के किरदार के साथ होती है, जो कम उम्र की लड़कियों को डेट करता है। लेकिन एक लड़की से मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देती है। उसे सलाखों के पीछे धकेल देती है। बॉबी देओल का किरदार खुद को बेगुनाह कहता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता है।

'बंदर' के ट्रेलर को देखकर लगता है कि यह कहानी दुष्कर्म के झूठे आरोप पर आधारित है। बॉबी का किरदार इस वजह से जेल भी जाता है। जेल के बुरे अनुभवों से वो गुजरता है। अपने किरदार में बॉबी काफी रम हुए नजर आते हैं। अलग-अलग सिचुएशन में उनकी एक्टिंग असर छोड़ती है।

कब होगी फिल्म रिलीज?

अनुराग कश्यप निर्देशन 'बंदर' की कहानी सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने लिखी है। निखिल द्विवेदी इसके प्रोड्यूसर हैं। इस फिल्म में बॉबी देओल के अलावा सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आजाद, इंद्रजीत सुकुमारन, जितेंद्र जोशी, राज बी. शेट्टी और नागेश भोंसले जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे। 'बंदर' 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

जेब कट रही, स्वाद छूट रहा : पहले पेट भरता था, अब जेब खाली करता है 'नाश्ता'

थाली से ठेले तक महंगाई का हमला, हर निवाला हुआ महंगा

छत्तीसगढ़ में महंगाई अब लोगों की जेब पर खुला हमला बन चुकी है। पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का नाश्ता तक छीन लिया है। रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और जगदलपुर समेत कई शहरों में समोसा, डोसा, भजिया और खस्ता जैसे आम स्नैक्स अब 'महंगे स्वाद' में बदल चुके हैं। एक महीने पहले तक 25-30 रुपये में मिलने वाला समोसा अब 40 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि डोसा 160 रुपये में बिक रहा है। होटल संचालक बढ़ती लागत का हवाला देकर मनमाने दाम वसूल रहे हैं और प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है। न कोई रेट तय, न कोई निगरानी... नतीजा यह कि हर होटल अपनी मर्जी से ग्राहकों की जेब काट रहा है। हालत यह है कि अब 100 रुपये में पेट नहीं भरता, सिर्फ स्वाद की औपचारिकता पूरी होती है। महंगाई की इस मार ने साफ कर दिया है कि आम आदमी की थाली से सस्ता नाश्ता तेजी से गायब होता जा रहा है।

- महंगाई ने बिगाड़ा होटल और रेस्टोरेंट में खाने का बजट
- महंगाई ने छीना स्वाद, नाश्ता खाने से पहले सोचना पड़ेगा!
- 40 रुपए प्लेट समोसा, भजिया, मुंगौड़ी, 160 का डोसा

महंगाई की कड़ाही में खौलते दाम, ग्राहकों का निकला दम

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में बढ़ती महंगाई अब सीधे आम आदमी की थाली और जेब पर असर डाल रही है। राजधानी रायपुर से लेकर दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर, जगदलपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने खाने-पीने की चीजों को महंगा कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि कभी चाय-नाश्ते के साथ आसानी से मिलने वाला समोसा अब लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। एक महीने पहले तक शहरों के होटल और ठेलों में समोसा 25 से 30 रुपये प्लेट मिल जाता था, लेकिन अब वही प्लेट 35 से 40 रुपये तक पहुंच गई है। सिर्फ समोसा ही नहीं, बल्कि डोसा, भजिया, खस्ता, मुंगौड़ी और आलुगुंडा जैसे लोकप्रिय नाश्तों के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। आम लोगों का कहना है कि पहले जहां 100 रुपये में परिवार का हल्का नाश्ता हो जाता था, अब उतने पैसे में दो लोगों का पेट भरना भी मुश्किल हो गया है।

डीजल महंगा होने से परिवहन खर्च बढ़ा, व्यवसाय की लागत भी बढ़ी

होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का तर्क है कि बढ़ती लागत के कारण उन्हें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। पेट्रोल-डीजल महंगा होने से परिवहन खर्च बढ़ गया है, वहीं गैस सिलेंडर की कीमतों ने होटल व्यवसाय की लागत को और बढ़ा दिया है। खाद्य तेल, दाल, मसाले और सब्जियों की कीमतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में होटल संचालक अपने हिसाब से रेट तय कर रहे हैं।

जिला प्रशासन की स्पष्ट गाइडलाइन नहीं

लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि जिला प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की स्पष्ट गाइडलाइन या निगरानी नहीं है। होटल और रेस्टोरेंट अपने स्तर पर कीमतें तय कर रहे हैं, जिससे ग्राहकों को मनमानी दरों का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि अलग-अलग इलाकों में एक ही सामान के अलग-अलग दाम वसूले जा रहे हैं।

कीमतों पर नियंत्रण नहीं तो महंगाई बढ़ेगी

आर्थिक जानकारों का मानना है कि यदि डीजल और गैस की कीमतों पर नियंत्रण नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है। इसका असर केवल होटल कारोबार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि घर के बजट पर भी गहरा असर पड़ेगा।

नाश्ता भी आम आदमी से दूर होता जा रहा

महंगाई की इस मार ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ रसोई ही नहीं, बल्कि सड़क किनारे मिलने वाला नाश्ता भी आम आदमी की पहुंच से धीरे-धीरे दूर होता जा रहा है। छोटे-छोटे खर्च अब जेब पर भारी पड़ने लगे हैं, और लोगों के चेहरे पर एक ही सवाल है— 'आखिर महंगाई रुकेगी कब?

डोसा प्रेमियों पर पड़ा सबसे ज्यादा असर

सबसे ज्यादा असर डोसा प्रेमियों पर पड़ा है। पहले जो सादा डोसा 70 से 80 रुपये में मिल जाता था, वही अब कई होटलों में 110 रुपये तक पहुंच गया है। मसाला डोसा की कीमत तो कई जगह 150 से 160 रुपये तक हो चुकी है। मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बाहर खाना अब धीरे-धीरे महंगा सौदा बनता जा रहा है।

ईंधन की बढ़ती कीमतों ने बिगाड़ा बजट

परिवहन से लेकर रसोई तक असर, खाद्यान्न, किराया और रोजमर्रा की वस्तुएं लगातार हो रहीं महंगी, गृहिणियों की चिंता बढ़ी, बाहर खाने वाले भी टेंशन में

जयदेव सिंह

- महंगाई का तड़का, खाने की कीमत ने बिगाड़ा बजट
- अब 100 रुपये में सिर्फ स्वाद मिलेगा, पेट नहीं भरेगा

नवप्रदेश विशेष

महासमुंद/नवप्रदेश। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी तथा पेट्रोल पंपों में सीमित मात्रा में ईंधन वितरण के निर्णय ने आम लोगों से लेकर व्यापारिक वर्ग तक की चिंता बढ़ा दी है। इसका असर अब केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी सप्लाई चेन, बाजार व्यवस्था और घरेलू बजट पर साफ दिखाई देने लगा है। खाद्यान्न, तेल, शक्कर, डिस्पोजल सामग्री, परिवहन किराया और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई ने आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। व्यापारियों और आम लोगों का कहना है कि यदि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही और ईंधन आपूर्ति सीमित रही, तो आने वाले दिनों में महंगाई और भी भयावह रूप ले सकती है।

खाद्यान्न पर सीधा असर, चावल-दाल के दाम बढ़ने लगे: डीजल की कीमत बढ़ने से परिवहन लागत में तेजी आई है। इसका सीधा असर खाद्यान्न और किराना सामग्री पर देखने को मिल रहा है। व्यापारियों के अनुसार, पहले जो चावल का कट्टा लगभग 1000 रुपये में मिलता था, उसमें 15 रुपये तक की वृद्धि हो चुकी है। आने वाले दिनों में यही बढ़ोतरी 30 से 50 रुपये प्रति कट्टा तक पहुंच सकती है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन बड़ी मात्रा में चावल दक्षिण भारत और महाराष्ट्र से आता है। वहीं दाल महाराष्ट्र और गेहूं मध्यप्रदेश से मंगाया जाता है। ऐसे में मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से खाद्यान्न आपूर्ति पर संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि यदि डीजल की कमी के कारण ट्रक और मालवाहक वाहन कम संख्या में आने लगे, तो बाजार में खाद्यान्न की कमी और जमाखोरी की स्थिति पैदा हो सकती है।

तेल, शक्कर और डिस्पोजल सामग्री के दामों में भारी उछाल: बढ़ती महंगाई का असर अब हर वर्ग महसूस कर रहा है। बाजार में खाद्य तेल, शक्कर और डिस्पोजल सामग्री के दामों में अचानक वृद्धि दर्ज की गई है। जो खाद्य तेल पहले 1800 से 1900 रुपये में मिलता था, वह अब 2350 से 2550 रुपये तक पहुंच गया है। शक्कर, जो कुछ दिन पहले 42-43 रुपये प्रति किलो बिक रही थी, अब 44-45 रुपये हो गई है।

डिस्पोजल ग्लास और कटौरी के दाम बढ़ गए

शादी-विवाह सीजन में उपयोग होने वाले डिस्पोजल ग्लास, जो पहले 13-14 रुपये में मिलते थे, अब 22-23 रुपये तक पहुंच गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि केवल अनाज ही नहीं, बल्कि लगभग हर वस्तु के दाम बढ़ चुके हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों ने पहले ही रसोई का बजट बिगाड़ रखा था, अब डीजल महंगा होने से स्थिति और गंभीर हो गई है।

खेती-किसानी पर भी बढ़ा आर्थिक दबाव

ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई पंप, ट्रैक्टर और अधिकांश कृषि उपकरण डीजल पर निर्भर हैं। डीजल महंगा होने से खेती की लागत बढ़ रही है। किसानों को ट्रैक्टर संचालन, सिंचाई, खाद और बीज की ढुलाई में अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईंधन कीमतों में लगातार वृद्धि होती रही, तो कृषि उत्पादन लागत बढ़ने से खाद्यान्न महंगाई और तेज होगी।

सरकार के सामने संतुलन बनाने की चुनौती

यदि ईंधन कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी रही, तो आने वाले समय में खाद्य पदार्थों से लेकर निर्माण सामग्री और यात्रा तक लगभग हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ सकती है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वह तेल कंपनियों के हित और आम उपभोक्ताओं को राहत देने के बीच संतुलन बनाकर प्रभावी नीति तैयार करे।

परिवहन महंगा, आम यात्रियों की जेब पर बोझ

देश में अधिकांश ट्रक, बसें और मालवाहक वाहन डीजल पर चलते हैं। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट लागत तेजी से बढ़ी है। इसका असर बस किराया, ऑटो और टैक्सी भाड़ा, ट्रक भाड़ा और ऑनलाइन डिलीवरी चार्ज तक में दिखाई देने लगा है। दैनिक यात्रा करने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है असर

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ईंधन कीमतों में लगातार वृद्धि से महंगाई दर बढ़ सकती है। इससे आरबीआई पर ब्याज दरों को नियंत्रित रखने का दबाव भी बढ़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी केवल वाहन चलाने की लागत नहीं बढ़ाती, बल्कि परिवहन, कृषि, उद्योग, खुदरा बाजार पर प्रभाव डालती है।

जमाखोरी-कालाबाजारी का बढ़ा खतरा

व्यापारिक वर्ग का कहना है कि सीमित मात्रा में डीजल वितरण से कालाबाजारी को बढ़ावा मिल सकता है। आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग जमाखोरी कर मुनाफाखोरी कर सकते हैं, जिससे बाजार में कृत्रिम संकट और महंगाई बढ़ने की आशंका है। प्रशासन को ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेना जरूरी है।

लोगों की जुबानी महंगाई का दर्द

बाजार की स्थिति बेहद खराब : संभू साहू

जिला चैंबर ऑफकॉमर्स के अध्यक्ष संभू साहू ने कहा कि बाजार की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। उन्होंने बताया कि खाद्य तेल 1800-1900 रुपये से बढ़कर 2350-2550 रुपये तक पहुंच गया है। शक्कर और डिस्पोजल सामग्री के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डीजल सीमित मात्रा में देने का निर्णय कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहा है और बाजार पर सरकार का नियंत्रण कमजोर दिखाई दे रहा है।

घर का बजट बिगाड़ दिया : जयश्री दास

गृहिणी जयश्री दास ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर घर के बजट पर पड़ रहा है। पहले गैस सिलेंडर महंगा हुआ और अब खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुएं महंगी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

भाड़ा बढ़ाने पर यात्री बैठना नहीं चाहते : शेख

छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ के जिलाध्यक्ष शेख अजीम ने कहा कि यात्रियों को यह पता है कि डीजल-पेट्रोल महंगा हो गया है, लेकिन वे किराया बढ़ाने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि 10 रुपये की सवारी के बदले 15 रुपये मांगे जाते हैं, तो लोग ऑटो में बैठना नहीं चाहते और ई-रिक्शा का विकल्प चुन रहे हैं। सरकार ई-वाहनों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन पारंपरिक वाहन चालकों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

रसोई से व्यापार तक असर : मोनिका गोलछा

गृहिणी और व्यवसायी मोनिका गोलछा ने कहा कि महंगाई की मार से गृहस्थी और व्यापार दोनों प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि कपड़ों के व्यापार में भी लागत बढ़ रही है, जबकि घर का बजट संभालना मुश्किल होता जा रहा है।

अब बचत करना भी मुश्किल : सुनीता साहू

गृहिणी सुनीता साहू ने कहा कि रोजमर्रा की हर जरूरत महंगी हो गई है। खाने-पीने की वस्तुओं से लेकर घरेलू सामान तक सबके दाम बढ़ गए हैं। घर का बजट संभालना पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है।

महंगाई अब चूल्हे तक पहुंच चुकी है : सोनम

गृहिणी सोनम ने कहा कि सब्जी, राशन, दूध और तेल जैसी जरूरी वस्तुएं महंगी हो गई हैं। महिलाएं छोटी-छोटी बचत कर घर चलाती हैं, लेकिन अब बचत करना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई रसोई तक पहुंच चुकी है।

अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस: डीजल-कामर्शियल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से फीकी पड़ी चाय की प्याली, 5 की चाय 8 और 10 की 15 रुपए तक पहुंची

दूध और ईंधन के दाम बढ़े, अब चाय की चुस्की पड़ रही भारी

शाहिन कुरैशी

रायपुर/नवप्रदेश। महंगाई ने राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में आम आदमी की जेब में चौतरफा हमला बोल दिया है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के मूल्य में तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि के साथ ही दूध के दाम भी दो रुपये बढ़ा दिए गए हैं। नतीजतन अब चाय की चुस्की महंगी पड़ रही है।

अब तक चालू चाय 5 रुपये में मिलती थी, जो अब सात रुपये में मिल रही है। वहीं स्पेशल चाय 7 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो गई है। चाय प्रेमी जो दिनभर में चार से पांच बार चाय पी लेते हैं उनको प्रति दिन दस रुपये की अतिरिक्त चपत लग रही है। टी स्टॉल वालों का कहना है कि पहले कमर्शियल गैस का दाम बढ़ाया गया था और अब दूध के दाम भी बढ़ गए हैं, इसलिए उन्हें चाय के दाम बढ़ाने पड़े हैं। दूसरी ओर चाय प्रेमी इस मूल्य वृद्धि को अनुचित करार दे रहे हैं। उनका कहना है दूध में दो रुपये की वृद्धि को प्रति कप दो रुपये महंगा कर हर चाय प्रेमियों से वसूलना गलत है। संयोग से आज 21 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी सहित यहां के टी-स्टालों और होटलों में दिनभर चाय प्रेमियों की भीड़ उमड़ी रही, लेकिन चाय के दाम बढ़ जाने के कारण चाय फीकी लगी।

गौरतलब है कि यह महंगाई केवल चाय तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध के चलते पेट्रोल, डीजल, गैस सहित खाने-पीने की चीजों पर भी गहरा असर पड़ा है। महंगाई ने इस कदर कहर ढाया है कि एक कप चाय पीने के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा है। इस मूल्य वृद्धि का असर केवल चाय प्रेमियों पर ही नहीं बल्कि चाय के छोटे-छोटे टपरी संचालकों के व्यापार पर भी पड़ने लगा है। दुकानदारों का कहना है उन्हें मजबूरन चाय की कीमत बढ़ानी पड़ी, क्योंकि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। जिससे उनके दैनिक ब्रिकी में गिरावट आ रही है। उनका कहना है कि जब दूध, कमर्शियल गैस और शक्कर जैसी दैनिक रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई है तो हम पुराना रेट कैसे चला सकते हैं। लागत निकालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमें मजबूरन रेट बढ़ाना पड़ा।

ईंधन की कालाबाजारी रोकने कड़े कदम जरूरी

बाजार में ईंधन व दूध जैसी चीजों की हो रही कालाबाजारी को रोकने कड़े कदम उठाने चाहिए वरना कल को दैनिक जीवन उपयोगी वस्तुएं भी गायब होने लगेगी इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां एक तरफ आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर लोग चाय की चुस्की लेकर चाय दिवस मना रहे थे वहीं दूसरी तरफ चर्चा का मुख्य विषय चाय की बढ़ती कड़वी कीमत ही रही।

चाय दुकानों में सामान रेट लिस्ट होना चाहिए

चाय प्रेमियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है।उनका कहना है कि दूध में दो रुपये की बढ़ोत्तरी का ये मतलब नहीं कि हर एक कप पर दो रुपए वसूला जाए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से लोगों ने मांग की है कि स्थानीय होटलों चाय स्टालों के लिए एक पारदर्शी रेट लिस्ट तय करनी चाहिए, ताकि इस महंगाई के दौर में आम आदमी को थोड़ी राहत मिल पाये।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक प्रधान संपादक यशवंत धोटे द्वारा, मिनल पब्लिकेशन एंड प्रोडक्शन प्रा.लि. शेड नंबर 74, सेक्टर-सी, उरला इंडस्ट्रीयल एरिया रायपुर, से मुद्रित कर तृतीय तल, सुपर मार्केट कॉम्पलेक्स, राजा रघुराज सिंह स्टेडियम के सामने अग्रसेन चौक, बिलासपुर से प्रकाशित, RNI NO.CHHHIN/2015/62431, संपादक-चन्द्रशेखर* (पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के लिए उत्तरदायी), स्थानीय संपादक-विक्रम सिंह ठाकुर, समाचार संपादक-संदीप दीवान, फोन नंबर : 07752-468654, navpradeshbilaspur01@gmail.com